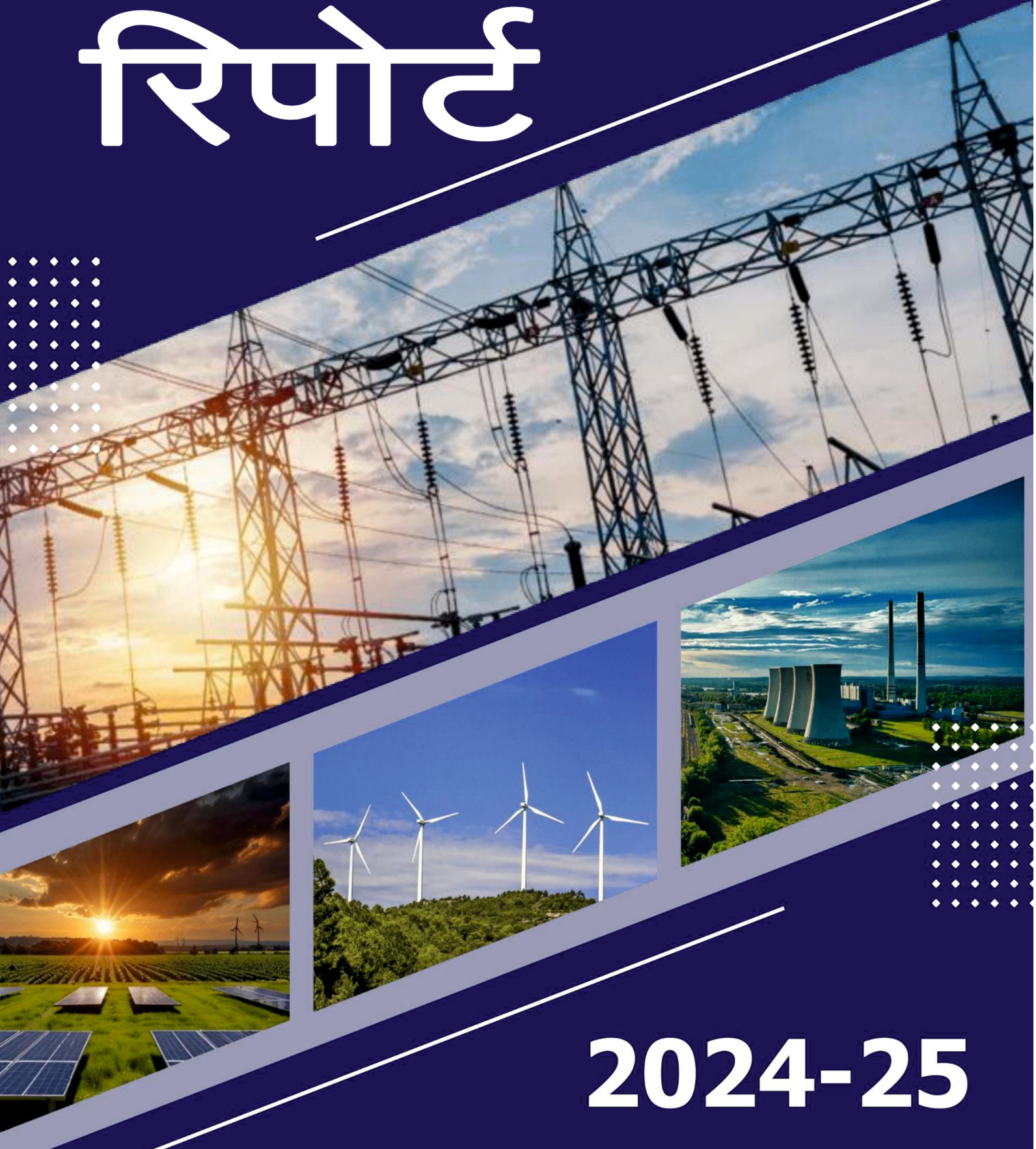


विनियामक फोरम (एफओआर)



वार्षिक रिपोर्ट



2024-25

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25



विनियामक फोरम (एफओआर)

प्रकाशक:

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय: केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के माध्यम से
8वां तल, टॉवर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर नई दिल्ली-110029

दूरभाष+91-11-26189709

प्रस्तावना

विनियामक फोरम (एफओआर) ने 2024-25 के दौरान भारत के विद्युत क्षेत्र के नियामक ढाँचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है। जैसे-जैसे विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, बाजार उदारीकरण, उपभोक्ता सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति सहित महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे-वैसे समन्वित, उत्तरदायी और दूरदर्शी विनियमन की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है।

इस संदर्भ में, एफओआर ने केंद्रीय और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के बीच संवाद, सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण फोरम के रूप में कार्य किया। संगठित बैठकों, विशेषज्ञताप्राप्त कार्य समूहों, केंद्रित अध्ययनों और अनेक नीतिगत पहलों के माध्यम से, एफओआर ने सदस्य आयोगों को साझा चुनौतियों का समाधान करने, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, आदर्श विनियम विकसित करने और क्षेत्रीय परिवर्तनों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाया।

वर्ष के दौरान, फोरम ने नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, इंदौर और गुवाहाटी सहित देश भर के विभिन्न स्थानों पर पाँच नियमित बैठकें और एक विशेष बैठक आयोजित की। इन बैठकों ने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक नियामक हस्तक्षेपों से लेकर वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपायों और उपभोक्ता अधिकारों एवं सेवा गुणवत्ता को बढ़ाने की पहल तक, विविध विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया।

वर्ष के दौरान फोरम ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं। फोरम ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा अधिसूचित आपूर्ति संहिता में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने, भारत में ग्रिड स्थिरता के लिए जलविद्युत, विशेष रूप से पंप स्टोरेज के विकास में तेजी लाने और डिस्कॉम की व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण पर कार्य समूह की अंतिम रिपोर्ट अंगीकृत की। फोरम ने अध्ययन रिपोर्टों और मॉडल विनियमों की सिफारिशों का समर्थन किया तथा अतिरिक्त अधिभार की गणना के लिए नई पद्धतियों पर विचार-विमर्श किया, जिसका उद्देश्य राज्यों में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाना है। नवीकरणीय एकीकरण को सुगम बनाने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में तकनीकी न्यूनतम उत्पादन स्तर को कम करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी उल्लेखनीय चर्चा हुई, साथ ही सहायक सेवाओं और मांग-पक्ष प्रबंधन में उभरते मुद्दों के समाधान के लिए नियामक उपायों पर भी चर्चा हुई।

फोरम ने डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता, स्मार्ट मीटरिंग को लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियों और विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों सहित व्यापक प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। इसने क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विनियामक मुद्दों, जैसे राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को जारी किए गए जीएसटी नोटिस, दीर्घकालिक संविदाओं में व्यापार मार्जिन के बारे में चिंताएं और आरई परियोजनाओं के लिए बोली दिशानिर्देशों में कार्यान्वयन अंतराल, पर प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया।

विनियामक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए क्षमता निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए, विदेश व्यापार संगठन (आईआईएफटी) ने वर्ष के दौरान एक क्षमता निर्माण नीति को मंजूरी दी। नवंबर 2024 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (प्थज), कोलकाता के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से एक साझेदारी स्थापित की गई। एफओआर ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) के साथ भी सहयोग किया। वैश्विक नियामकीय संभावना कार्यक्रम (जीआरपीपी) के अंतर्गत, राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों ने ज्ञान साझा करने और वैश्विक प्रथाओं से परिचित होने के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा नियामक (ईईआर) और ऑस्ट्रेलियाई नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (एरेना), ऑस्ट्रेलिया, और विद्युत प्राधिकरण, न्यूजीलैंड सहित विभिन्न संस्थानों का दौरा किया।

अपनी आंतरिक पहलों के अतिरिक्त, फोरम ने सरकारी निकायों, सिस्टम ऑपरेटरों और अनुसंधान संगठनों सहित क्षेत्र के हितधारकों के साथ गहनतापूर्वक कार्य किया। इससे एफओआर को नीतिगत विकास पर जानकारीयुक्त इनपुट प्रदान करने तथा विनियामक

और नीति निर्देशों के बीच अधिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में सहायता मिली।

भविष्य की ओर देखते हुए, फोरम भारत के विद्युत क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए सामंजस्यपूर्ण नियामक प्रथाओं को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र कार्बन-मुक्ति और आधुनिकीकरण की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, फोरम भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करता रहेगा और एक अधिक लचीले, कुशल और उपभोक्ता-केंद्रित विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता रहेगा।

मैं फोरम के सभी सदस्यों, कार्य समूहों और सचिवालय का वर्ष के दौरान उनके समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने ज्ञान साझेदारों और हितधारकों को भी उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सामूहिक प्रयास से, फोरम नियामक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना जारी रखेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि विद्युत क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए उत्प्रेरक बना रहे।

(अध्यक्ष)

विनियामक फोरम

विषय

1. संक्षेपाक्षर

2. विनियामक फोरम (एफओआर) के बारे में

3. फोरम के कार्य-कलाप

4. फोरम की गतिविधियाँ

5. विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों (सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी) की वर्ष 2024-25में उपलब्धियां

6. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट

7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) के अध्यक्ष

8. एफओआर के वार्षिक लेखे

9. आरपीओ अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्ट

5

10

11

13

32

37

39

41

63

संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
ए एंड जी	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय
ए.सी	प्रत्यावर्ती धारा
ऐस	अतिरिक्त पूंजीगत व्यय
एसीओएस	आपूर्ति की औसत लागत
एईजीसीएल	असम विद्युत ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वायु	ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा नियामक
एईआरए	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण
ऐ	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
बीमार होना	एस्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
एईएमएल-डी	अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (वितरण व्यवसाय)
एपीसीपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एपीडीसीएल	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एपीईपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एपीईआरसी	आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
एपीजेनको	आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एपीएसपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एपीएसएलडीसी	आंध्र प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र
एपटेल	विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण
एपीट्रानस्को	आंध्र प्रदेश पारेषण निगम
अखाड़ा	ऑस्ट्रेलियाई नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी
एसएसएल	एईएमएल सीप्ल लिमिटेड
बी इ आर सी	बिहार विद्युत नियामक आयोग
जीवित	बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन
बीआरपीएल	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड
बीवाईपीएल	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड
सी.ए	प्रतिपूरक वनरोपण
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सीबीपी	क्षमता निर्माण कार्यक्रम
सीबीएस	सर्किट ब्रेकर
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईआरसी	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग
सीईएससी	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम (कर्नाटक)
सीजीआरएफ	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
सीओडी	वाणिज्यिक संचालन तिथि
सीपीएसयू	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीएसईआरसी	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सीएसपी	केंद्रित सौर ऊर्जा
सीएसपीडीसीएल	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीटीयू	केंद्रीय पारेषण उपयोगिता
डीजीवीसीएल	दक्षिण गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
निगम	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएनडीडीपीडीसीएल	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
डीओपीएन	विद्युत विभाग, नागालैंड
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
डीआरई	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा
डीएसएम	मांग पक्ष प्रबंधन
डीटी	वितरण ट्रांसफार्मर
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईसीआर	ऊर्जा शुल्क दर
ईडीजी	विद्युत विभाग, गोवा
ईआरसी	विद्युत नियामक आयोग
ईआरपी	उद्यम संसाधन नियोजन
ई.वी	इलेक्ट्रिक वाहन
ईडब्ल्यूईडीसी	विद्युत विंग इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़
एफसी	वन मंजूरी
एफजीडी	पलू गैस डिसल्फराइजेशन
के लियेध्के लियेआर	नियामकों का फोरम
एफपीपीएस	ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार
वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
जीसीवी	सकल कैलोरी मान
जीईआरसी	गुजरात विद्युत नियामक आयोग
गेस्कम	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
उपहार पीसीएल	गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीआईएस	गैस इंसुलेटेड स्विचगियर
जी एन ए	सामान्य नेटवर्क एक्सेस
जीओएपी	आंध्र प्रदेश सरकार
जीओआई	भारत सरकार
जीआरपीपी	वैश्विक नियामक संभावित कार्यक्रम
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीडब्ल्यू	गीगावाट
एचईआरसी	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग
हेस्कॉम	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
एचपीईआरसी	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
एचआरईसीएस	हुक्केरी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति
एचवीडीसी	उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा
एचवीडीएस	उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली
आईडीसी	निर्माण के दौरान ब्याज
आईआईटी	भारतीय विद्युत नियामक संस्थान प्रौद्योगिकी
आईओडब्ल्यूसी	कार्यशील पूंजी पर ब्याज
आईपीजीसीएल	इंद्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
आईएसटीएस	अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेबीवीएनएल	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग
जेआईएल	जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
जेएनपीए	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण
जेपीडीसीएल	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जेएसईआरसी	झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
किलो कैलोरी	किलोकैलोरी
केईआरसी	कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग
केपीडीसीएल	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
केपीटीसीएल	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केआरसी इन्फ्रा	केआरसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
केएसईबी लिमिटेड	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
केएसईआरसी	केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग
के.वी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यूएच	किलोवाट-घंटा
एलएडीएफ	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि
एलडीसी	भार प्रेषण केंद्र
एलडीसीडी	भार प्रेषण केंद्र विकास
एलओए	निर्णय पत्र
एलपीडीडी	लघु विद्युत वितरण विभाग
एलपीएस	विलंब भुगतान अधिभार
एमएडीसी	महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी लिमिटेड
एमसीबी	लघु सर्किट ब्रेकर
एमसीएलआर	सीमांत निधि लागत आधारित ऋण दर
एमईआरसी	महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग
मेस्कॉम	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
एमजीवीसीएल	मध्य गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
एमआईटीएल बिडकिन	महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड – बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र
एमआईटीएल शेंद्रा	महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड – शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र
माइंडस्पेस	माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओईएफ एवं सीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओपी	ऊर्जा मंत्रालय
एमपीडीसीएल	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एमपीईआरसी	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
एमएसईआरसी	मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग
एमएसईजेड	मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई) लिमिटेड
एमयूएल	डर्भ्य यूटिलिटीज लिमिटेड
मेगावाट	मेगावाट
एमडब्ल्यूएच	मेगावाट-घंटा
एन ए बी एल	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन बोर्ड
एनएपीएएफ	मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक
एनएपीएलएफ	मानक वार्षिक संयंत्र भार कारक
एनबीपीडीसीएल	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एनसीईएफ	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष
एनसीईटी	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
एनडीएमसी	नई दिल्ली नगर परिषद
एनएचआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र
एनपीसी	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
एनपीटीआई	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
एनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
एनटीपी	राष्ट्रीय टैरिफ नीति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
ओ एंड एम	परिचालन एवं रखरखाव

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओईआरसी	ओडिशा विद्युत नियामक आयोग
ओपेक्स	परिचालन व्यय
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीजीवीसीएल	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएलआई	कार्यनिष्पादन संबंध प्रोत्साहन
पोसोको	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीपीए	बिजली खरीद करार
पीपीसीएल	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीपीपी	जन-निजी भागीदारी
पीआरएएस	प्राथमिक आरक्षित सहायक सेवा
पीएसडीएफ	पावर सिस्टम विकास निधि
पीएसईआरसी	पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग
पीएसएम	भुगतान सुरक्षा तंत्र
पीएसपी	पंप संग्रहण संयंत्र
पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
क्यूसीबीएस	गुणवत्ता और लागत आधारित चयन
आरसीओ	नवीकरणीय उपभोग दायित्व
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र
आरईआईए	नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी
आरईआरसी	राजस्थान विद्युत नियामक आयोग
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र
आरओई	इक्विटी पर प्रतिफल
आरओई	रन-ऑफ-रिवर
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय दायित्व
एसबीपीडीसीएल	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एससीएडीए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण
एससीईडी	सुरक्षा बाध्य आर्थिक प्रेषण
एसईबी	राज्य विद्युत बोर्ड
एसईसीआई	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
एसईआरसी	राज्य विद्युत नियामक आयोग
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केंद्र
एसएनए	निपटान नोडल एजेंसी
एसओपी	निष्पादन मानक
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
टी एंड डी	पारेषण एवं वितरण
टीएएनजीईडीसीओ	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड
टैंट्रांस्को	तमिलनाडु पारेषण निगम लिमिटेड
टीबीसीबी	शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली
टीईआरसी	त्रिपुरा विद्युत नियामक आयोग
टेरी	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान
टीजीएनपीडीसीएल	तेलंगाना उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
टीजीएसपीडीसीएल	तेलंगाना दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
टीएनईआरसी	तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग
टीएनपीडीसीएल	तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
टीपीसी-डी	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण)
टीपीसीओडीएल	टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
टीपीडीडीएल	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
टीपीएल	टोरेंट पावर लिमिटेड
टीपीएनओडीएल	टीपी उत्तरी ओडिशा वितरण लिमिटेड
टीपीएसओडीएल	टीपी दक्षिणी ओडिशा वितरण लिमिटेड
टीपीडब्ल्यूओडीएल	टीपी पश्चिमी ओडिशा वितरण लिमिटेड
टीएसईसीएल	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
टीएसईआरसी	तेलंगाना राज्य विद्युत नियामक आयोग
टी.डब्ल्यू.एच	टेरावाट-घंटा
यूईआरसी	उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग
यूजीवीसीएल	उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
यूएचबीवीएनएल	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स
यूपीसीएल	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूपीईआरसी	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
डब्ल्यूबीईआरसी	पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक

1

विनियामक फोरम (एफओआर) के बारे में

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की संकल्पना वर्ष 1990 के दशक के पूर्वार्ध में हुई, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली विद्युत पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) समिति ने वर्ष 1994 में “सार्वजनिक और निजी उपादेयताओं की टैरिफ नीतियां विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र पेशेवर टैरिफ बोर्ड” के गठन की सिफारिश की थी। समिति ने दोहराया कि टैरिफ बोर्ड प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए उपयुक्त बिजली टैरिफ विकसित करने के मामले में अपने साथ उच्च स्तरीय व्यावसायिकता लाने में सक्षम होंगे। वर्ष 1996 में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में एक विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को दोहराया गया था। विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना जो इस सम्मेलन में विकसित हुई, में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति बनी कि राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) में सुधार लाना और उनका पुनर्गठन नितांत आवश्यक है और इन्हें एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए तथा इस दिशा में एक कदम के रूप में विद्युत विनियामक आयोग सृजित करने की बात पर सहमति बनी। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हुए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1998 का अधिनियम टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1998 का अधिनियम केंद्र और राज्यों में तर्कसंगत बिजली दर, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों आदि के लिए ईआरसी का प्रावधान करता है। वर्ष 1998 अधिनियम को तब से विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में, 2003 अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2003 अधिनियम की शुरुआत के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को बिजली बाजार के विकास और सलाहकार कार्य की भूमिका निर्दिष्ट करते हुए विद्युत विनियामक आयोगों के कार्य बढ़ा दिये गये। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) का गठन 1998 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। हालाँकि, कुछ एसईआरसी/जेईआरसी जैसे मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी), जेईआरसी- (मणिपुर और मिजोरम), जेईआरसी (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश) और जेईआरसी (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) का गठन वर्ष 2003 अधिनियम के लागू होने के उपरांत किया गया था। इस फोरम का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय की 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा बिजली क्षेत्र के लिए तैयार किये गए नियमों के साथ तालमेल बैठाना था।

फोरम का गठन

- 1) यह फोरम केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्ष से मिलकर बनता है। केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष एफओआर का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय आयोग का सचिव फोरम का पदेन सचिव होता है। केंद्रीय आयोग इस फोरम को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। इस फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित होगा।
- 2) केंद्रीय आयोग का सचिव फोरम का पदेन सचिव होगा।
- 3) केंद्रीय आयोग फोरम को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।
- 4) फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

फोरम के कार्य-कलाप

यह फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

1) डेटा संग्रह और विश्लेषण-

क. केंद्रीय आयोग और राज्य आयोगों की दर-सूची (टैरिफ) के आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण, अधिनियम और टैरिफ नीति के प्रावधानों से अंतर, यदि कोई हो, पर प्रकाश डालना, क्या टैरिफ आदेश और सही समय पर किए गए हैं, और क्या टैरिफ सभी विवेकसम्मत लागत प्रदर्शित करते हैं, और क्या देय सब्सिडी को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया गया है और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार उसका भुगतान किया गया है;

2) सब्सिडी लेखांकन -

क. देश में प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का यह उल्लेख करते हुए त्रैमासिक विवरणियां तैयार करना कि क्या वितरण कंपनियां सब्सिडीकृत श्रेणी के अंतर्गत उपभोग की गई ऊर्जा और देय प्रति यूनिट सब्सिडी के सटीक लेखाओं के आधार पर हर तिमाही में सब्सिडी की मांग करती हैं, और क्या उक्त सब्सिडी का भुगतान, देय और प्रदत्त सब्सिडी में अंतराल के साथ-साथ अन्य सुसंगत विवरण अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत किया जाता है।

ख. देय सब्सिडी की संगणना विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी और यह विवरण फोरम द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति तिथि से तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

3) नवीकरणीय खरीद अनुपालन की निगरानी-

क. प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव खपत और खुली पहुंच के माध्यम से बिजली खरीदने वाले उपभोक्ता द्वारा लक्ष्यों का अनुपालन नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की खरीद जो केंद्र सरकार या राज्य आयोग द्वारा निर्धारित हो, जो भी अधिक हो, के लिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम, दिशानिर्देश प्रावधानों के अनुसार करेगा।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा से खरीद के लक्ष्यों के अनुपालन के लिए डेटा और उसके विश्लेषण से युक्त वार्षिक प्रतिवेदन आगामी वित्तीय वर्ष के 31 मई तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

4) विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामंजस्य।

5) लाइसेंसधारियों के कार्य निष्पादन मानक निर्धारित करना जो अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित हैं।

6) फोरम के सदस्यों के बीच सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुद्दों पर सूचना साझा करना।

7) विद्युत क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर आंतरिक या आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसंधान कार्य करना।

8) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और विद्युत क्षेत्र में दक्षता लाने, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपाय विकसित करना।

9) ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो केंद्र सरकार समय-समय पर फोरम को निर्दिष्ट करे।

फोरम का वित्तपोषण

केंद्रीय आयोग, फोरम का सचिवालय होने के नाते, फोरम के कार्यक्रमलाप संचालित करने के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान एकत्रित कर सकता है। केंद्रीय आयोग फोरम के कार्यक्रमलापों का अलग लेखा-जोखा रखेगा।

मिशन कथन

विनियामक फोरम की संकल्पना भारत में विद्युत क्षेत्र में हिस्सेदारी रखने वाले सभी लोगों के स्वतंत्र विनियमन के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मिशन के उद्देश्य से गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के अनुसरण में, फोरम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- 1) विद्युत क्षेत्र में विनियमन का सामंजस्य
- 2) संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- 3) भारत के विद्युत क्षेत्र में विनियामक सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को फोरम प्रदान करना
- 4) उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों का कार्यान्वयन करते हुए विद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की पहल को सुविधाजनक बनाना।

2

फोरम की गतिविधियाँ

क. विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष 2024-25 के दौरान छह बैठकें आयोजित कीं और इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनी। एफओआर की इन छह बैठकों में से एकविशेष बैठकें थी।

1. नई दिल्ली में दिनांक 5 अप्रैल, 2024 को आयोजित एफओआर की 90वीं बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमोदित किया गया।
- सांविधिक लेखा परीक्षक और कर सलाहकार की एक और वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक नए जीएसटी सलाहकार की नियुक्ति के लिए उचित प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में अवगत कराया गया।
- केईआरसी के उस प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें मॉडल संसाधन पर्याप्तता विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इसमें विभिन्न वितरण लाइसेंसधारियों वाले राज्य और वितरण लाइसेंसधारियों के साथ उन उपभोक्ताओं के लिए एक समान खुदरा आपूर्ति शुल्क पर विचार किया गया जिनके पास संविदा माँग वाली खुली पहुंच है। फोरम ने इन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार और इसे उपयुक्त सुझावों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति पर गठित कार्य समूह को भेज दिया।
- अतिरिक्त अधिभार की गणना के लिए एक समान पद्धति की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया। फोरम ने इस मामले को नियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह को भेज दिया।
- जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए सीपीईएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर चर्चा हुई। फोरम ने कहा कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती कर सकते हैं और सीपीईएस अधिकारी आवश्यकतानुसार आवेदन कर सकते हैं।
- पम्प भंडारण संयंत्र (पीएसपी) और भंडारण के साथ संकेन्द्रित सौर ऊर्जा (सीएसपी) पर टीईआरआई द्वारा दी गई प्रस्तुति के नोट्स लिए गए तथा सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाओं और दीर्घकालिक बोली विंडो सहित इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई।
- राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा लाइसेंस/याचिका शुल्क पर प्राप्त जीएसटी नोटिस के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग इस मामले को आगे के संदर्भ के लिए समेकन और संचलन हेतु एफओआर सचिवालय को भेज सकते हैं।

2. पुणे, महाराष्ट्र में दिनांक 8 जून, 2024 को आयोजित एफओआर की 91वीं बैठक



इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण हेतु प्रणाली संचालन में विशेष रूप से अंतर-राज्यीय उत्पादन केंद्रों के लिए अंतर-राज्यीय उत्पादन केंद्रों की तरह न्यूनतम 55 प्रतिशत टर्नडाउन स्तर पर संचालन की आवश्यकता परलचीलेपन की आवश्यकता पर चर्चा की गई। फोरम ने इस मामले को आगे की जाँच के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति पर कार्य समूह को भेजने का निर्णय लिया और ग्रिड-इंडिया से संबंधित अध्ययन आरंभ करने का अनुरोध किया।
- नियमों और विनियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। फोरम ने कैप्टिव पावर प्लांट्स पर एफओआर मॉडल विनियमों को सर्वोच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2023 के निर्णय के अनुरूप बनाने की सिफारिश की और उपभोक्ता अधिकार नियमों और विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों में आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव रखा, जिनमें (i) स्मार्ट मीटर कार्यान्वयन की समय-सीमा में छूट, (ii) मौजूदा मीटरों की रेट्रोफिटिंग, (iii) सीजीआरएफ संरचना में लचीलापन, और (iv) एलपीएस नियमों के तहत "व्यापारी" को एक चूककर्ता इकाई के रूप में शामिल करना सम्मिलित हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति और विनियामक मामलों पर कार्य समूह के अद्यतन को नोट किया गया और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) पर एफओआर मॉडल विनियमों को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया, जिसमें वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, बिहाइंड-द-मीटर सिस्टम और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग के प्रावधान शामिल हैं।
- भारत में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) में तेजी लाने पर प्रस्तुति पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि मॉडल डीएसएम विनियमों को अद्यतन करने के लिए इस मामले को डिस्कॉम की व्यवहार्यता पर एफओआर कार्य समूह को भेजा जाना चाहिए।

- दीर्घकालिक खरीद के लिए ट्रेडिंग मार्जिन के संबंध में टीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार-विमर्श किया गया तथा एसईसीआई से भविष्य की बैठकों में जोखिम मूल्यांकन पर प्रस्तुति देने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
- ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए लागू टैरिफ के संबंध में सीएसईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि एफओआर सचिवालय द्वारा तुलनात्मक विश्लेषण तैयार किया जाएगा, जिसे उचित कार्रवाई के लिए सभी एसईआरसी को भेजा जा सकता है।

3. हैदराबाद, तेलंगाना, में दिनांक 29 जुलाई, 2024 को आयोजित एफओआर की 92वीं बैठक



इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के क्रियान्वयन में विद्युत क्रय लागत की समय पर वसूली और एफपीपीएस के सही-सही आकलन से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। फोरम ने लेखापरीक्षित खातों की उपलब्धता में देरी पर ध्यान दिया और सही-सही आकलन की समय-सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाने की सिफारिश की, साथ ही विद्युत मंत्रालय को उपयुक्त संशोधन का सुझाव भी दिया।
- विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार पूर्व भुगतान सुविधाओं वाले स्मार्ट मीटरों की अनिवार्य स्थापना से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। फोरम ने अपने पूर्व निर्णय की पुष्टि की कि नियमों के सामंजस्य पर कार्यदल की सिफारिशों को विद्युत मंत्रालय को भेजा जाए ताकि समय-सीमा को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।
- 150 किलोवाट तक के एलटी कनेक्शनों के संदर्भ पर विचार किया गया और तकनीकी व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया गया। इस बात पर सहमति हुई कि विद्युत मंत्रालय के साथ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) सचिवों की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और सिफारिशों के लिए नियमों के सामंजस्य

पर गठित कार्य समूह को भी भेजा गया।

- दीर्घकालिक संविदाओं में लागू ट्रेडिंग मार्जिन पर केएसईआरसी के संदर्भ पर चर्चा की गई, जहाँ पीएसएम लागत उत्पादकों द्वारा वहन की जाती है। अतः फोरम ने कि विद्युत मंत्रालय मानक बोली दिशानिर्देशों की समीक्षा और सीईआरसी ट्रेडिंग मार्जिन प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए अध्ययन आरंभ करने की सिफारिश की।
- 10 किलोवाट तक की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की तकनीकी व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया गया। उच्च प्रवेश क्षेत्रों से संबंधित चिंताओं पर ध्यान दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को इन्वर्टर आवश्यकताओं और रिएक्टिव पावर सपोर्ट सहित तकनीकी मानकों और समाधानों के सुझाव के लिए सीईए को भेजा जाए।
- कार्य समूह द्वारा अंतिम रूप दिए गए मॉडल आपूर्ति कोड पर विचार किया गया और उसे अंगीकृत किया गया, जिसमें सदस्यों ने कार्य समूह, तकनीकी विशेषज्ञों और एफओआर सचिवालय के प्रयासों की सराहना की।
- जलविद्युत एवं पम्प भंडारण पर कार्यदल ने चल रहे अध्ययनों के निष्कर्ष और स्थिति प्रस्तुत की; फोरम ने सुझाव दिया कि इनपुट संकलित किए जाएं और उन्हें अगली बैठक में साझा किया जाए।
- नियमों के सामंजस्य पर गठित कार्यदल ने उपभोक्ता अधिकार, अतिरिक्त अधिभार और एमवाईटी विनियमों पर सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिन्हें विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा नीति एवं विनियामक मामलों पर गठित कार्यदल ने मॉडल डीआरई विनियमों, आरपीओ अध्ययनों और राज्य जीएनए विनियमों को अद्यतन किया। फोरम ने क्षतिपूर्ति के साथ तापीय संयंत्रों के लिए न्यूनतम टर्नडाउन स्तरों पर प्रस्ताव को भी स्वीकार किया।

4. इंदौर, मध्य प्रदेश में दिनांक 13 सितंबर, 2024 को आयोजित एफओआर की 93वीं बैठक



इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएस) के टू-अप के संबंध में विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के

नियम 14 के कार्यान्वयन में एमपीईआरसी द्वारा उजागर की गई कठिनाइयों को नोट किया गया और सिफारिश की गई कि टू-अप प्रक्रिया को 30 नवंबर तक अनुमति दी जाए। फोरम ने निर्णय लिया कि नियमों में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय को उपयुक्त अनुशंसाएँ दी जा सकती हैं।

- विद्युत मंत्रालय की दिनांक 23.05.2022 की अधिसूचना के अनुसार पूर्व भुगतान सुविधाओं वाले स्मार्ट मीटरों की स्थापना हेतु समय-सीमा के कार्यान्वयन में एमपीईआरसी द्वारा उठाई गई चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। फोरम ने निर्णय लिया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55(1) के दूसरे प्रावधान के अनुरूप उपयुक्त संशोधन हेतु विद्युत मंत्रालय को एफओआर सचिवालय अपनी पूर्व अनुशंसा भेज सकता है।
- 150 किलोवाट तक के एलटी कनेक्शन प्रदान करने में आने वाली तकनीकी चुनौतियों के संबंध में सीएसईआरसी के संदर्भ पर चर्चा की गई। फोरम ने निर्णय लिया कि विद्युत मंत्रालय के साथ सचिवों की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और इस मामले को नियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह को भी भेजा गया।
- केएसईआरसी द्वारा दीर्घकालिक संविदाओं में लागू ट्रेडिंग मार्जिन के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया, जहाँ भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) प्रदान करने की लागत उत्पादकों द्वारा वहन की जाती है। फोरम ने विद्युत मंत्रालय को मानक बोली दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने का निर्णय लिया और सुझाव दिया कि सीईआरसी इस विषय पर अपने नियमों की समीक्षा करने पर भी विचार कर सकता है।
- उच्च सौर प्रवेश वाले क्षेत्रों में 10 किलोवाट तक की रूफटॉप सौर प्रणालियों की तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में केएसईआरसी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर चर्चा की गई। फोरम ने संभावित इन्वर्टर मानकों और गतिशील प्रतिक्रियाशील ऊर्जा समर्थन सहित उचित समाधान के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष इस मामले को उठाने का निर्णय लिया।
- एफओआर कार्य समूह द्वारा विकसित मॉडल आपूर्ति संहिता अंगीकृत की गई।
- जलविद्युत विकास एवं पम्प भंडारण पर कार्य समूह की अद्यतन स्थिति को नोट किया गया और हुई प्रगति की सराहना की गई। यह निर्णय लिया गया कि डेवलपर्स से प्राप्त फीडबैक और प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी को संकलित करके अगली एफओआर बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
- नियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह की सिफारिशों को स्वीकार किया गया और निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त अधिभार से संबंधित उपभोक्ता अधिकार नियमों और विद्युत संशोधन नियमों में संशोधन के संबंध में विद्युत मंत्रालय को उपयुक्त सिफारिशें दी जाएँ। फोरम ने अतिरिक्त अधिभार की गणना हेतु प्रस्तावित पद्धति को भी मंजूरी दी और टैरिफ डिजाइन में एसीओएस के $\pm 20\%$ अनुपालन पर जोर दिया।
- नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति एवं नियामक मामलों पर कार्य समूह की प्रगति को नोट किया गया, जिसमें मॉडल डीआरई विनियमों में संशोधनों के मसौदे को अंतिम रूप देना, 12 राज्यों में आरपीओ अध्ययन और मॉडल राज्य जीएनए विनियमों के मसौदे का विकास शामिल है। फोरम ने राज्य आयोगों से अध्ययनों को समय पर पूरा करने के लिए आँकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

5. गुवहाटी, असम में दिनांक 10 जनवरी, 2025 को आयोजित एफओआर की 94वीं बैठक



इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- ईआरसी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (सीबीपी) की रूपरेखा का अनुमोदन किया गया।
- नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए बाधाओं और उपचारात्मक उपायों के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट पर अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई तथा निर्णय लिया गया कि नवीकरणीय ऊर्जा कार्य समूह की सिफारिशों के बाद मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- प्री-पेड मीटरिंग के लिए छूट व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया और राज्यों में छूट प्रावधानों में भिन्नताओं पर ध्यान दिया गया। फोरम ने निर्णय लिया कि संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग मौजूदा प्रथाओं के आधार पर अपना निर्णय ले सकते हैं।
- आरएलडीसी वेबसाइटों पर शेड्यूलिंग डेटा तक पहुंच को सक्षम करने के संबंध में केएसईआरसी के संदर्भ पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि सीईआरसी एसईआरसी के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता पहुंच के माध्यम से डोमेन रिपोर्ट तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।
- रायगढ़-पुगलुर-त्रिशूर एचवीडीसी प्रणाली से जुड़े उच्च पारेषण शुल्क के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और नोट किया गया कि सीईआरसी पूंजीगत लागत प्रभाव को कम करने के लिए पीएसडीएफएनसीईएफ के माध्यम से अनुदान निधि के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए पीजीसीआईएल को लिखेगा।
- नियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि इसे ईआरसी को टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा।
- आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए आईआईएफटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें मामला-दर-मामला वित्तीय प्रस्तावों को

एफओआर/सीईआरसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- “डिस्कॉम की व्यवहार्यता पर कार्य समूह की अंतिम रिपोर्ट अंगीकृत की गई, व्यापक सिफारिशों की सराहना की गई और निर्णय लिया गया कि इसे उचित कार्रवाई के लिए विद्युत मंत्रालय और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को भेजा जाए। फोरम ने भविष्य के कार्यों के लिए असम विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में सह-चयनित करने का भी निर्णय लिया।
- जलविद्युत और पम्प स्टोरेज विकास पर कार्य समूह से प्राप्त अद्यतन जानकारी पर ध्यान दिया गया और निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट को सभी ईआरसी को टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा तथा एक विशेष एफओआर बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

6. सीईआरसी, नई दिल्ली में दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- विभिन्न ईआरसी को प्रभावित करने वाले जीएसटी संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और पाया गया कि सीईआरसी सहित नौ राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को जीएसटी नोटिस प्राप्त हुए हैं। फोरम ने पाया कि ईआरए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय एक प्रासंगिक मिसाल पेश कर सकता है। फोरम ने न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने और समाधान हेतु माननीय वित्त मंत्री के साथ संभावित बैठक की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संयंत्र (आईएसटीएस) से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विलंबित कमीशनिंग के प्रभाव के संबंध में बीईआरसी के प्रतिनिर्देश पर चर्चा की गई। फोरम ने पाया कि मध्यस्थ खरीदार परिसमाप्त क्षतिपूर्ति राशि अपने पास रख लेते हैं, जिससे डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ पड़ता है। फोरम ने विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को यह अनुशंसा करने का निर्णय लिया कि वे बोली दिशानिर्देशों में संबंधित खंड पर पुनर्विचार करें ताकि डिस्कॉम के साथ ऐसी क्षतिपूर्ति राशि साझा की जा सके।
- आरपीओ अनुपालन और सब्सिडी लेखांकन पर सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित एजेंडा मद नोट की गई।

7. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28 फरवरी, 2025 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

इस बैठक के दौरान फोरम द्वारा:

- “ग्रिड स्थिरता के लिए जलविद्युत के विकास में तेजी लाने” पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। एचपीईआरसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य समूह ने कई परामर्शों और पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) के साइट दौरों के आधार पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए।
- सतत ऊर्जा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जल विद्युत को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की और जल विद्युत को दीर्घकालिक विकल्प के रूप में विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- चर्चा के पश्चात, फोरम ने जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने और उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। यह सुझाव दिया गया कि जलविद्युत परियोजनाओं में पंपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट ऊर्जा को बिजली की खपत न माना जाए, जिससे जलविद्युत परियोजनाओं को बिजली शुल्क

और उपकर से छूट मिल सके और परिचालन लागत कम हो। इसके पश्चात, फोरम ने जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने और उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। यह सुझाव दिया गया कि जलविद्युत परियोजनाओं में पंपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट ऊर्जा को बिजली की खपत न माना जाए, जिससे जलविद्युत परियोजनाओं को बिजली शुल्क और उपकर से छूट मिल सके और परिचालन लागत कम हो सके। इसके पश्चात, आगे फोरम ने जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने और उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। यह सुझाव दिया गया कि जलविद्युत परियोजनाओं में पंपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट ऊर्जा को बिजली की “खपत” न माना जाए, जिससे जलविद्युत परियोजनाओं को बिजली शुल्क और उपकर से छूट मिल सके और परिचालन लागत कम हो। इसके अलावा, निजी निवेश को आकर्षित करने और परियोजना की पूंजीगत लागत को कम करने के लिए भूमि अधिग्रहण लागत कम करने, सरकारी भूमि को नाममात्र दरों पर पट्टे पर देने और स्टांप शुल्क में छूट जैसे उपायों को लागू करने का सुझाव दिया गया।

- इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि पीएसपी विकास के लिए विश्वसनीय ठेकेदारों की पहचान करने हेतु एक सरकारी नेतृत्व वाली नोडल एजेंसी नियुक्त की जाए, जिससे डेवलपर्स के लिए सुव्यवस्थित सहयोग सुनिश्चित हो सके। वित्तीय उपायों पर भी चर्चा की गई, जिसमें ऋण ब्याज दरों को कम करना और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण-से-इक्विटी अनुपात को 80:20 तक संशोधित करना शामिल है, जिससे उत्पादन लागत में 10-20 प्रतिशत की कमी आ सकती है।
- जलविद्युत और पीएसपी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया गया।
- निर्णय लिया गया कि सुझावों को शामिल करने के पश्चात एफओआर सचिवालय इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर इसे विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करे।

क) कार्य समूह

वर्ष के दौरान, एफओआर कार्यसमूहों/समितियों ने मौजूदा नियामक मुद्दों के साथ-साथ उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु विभिन्न गतिविधियाँ संचालित कीं। इन कार्यसमूहों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

1) आरई से संबंधित नीति और संबंधित मामले:

क) नीति और नियामक मामलों से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के विभिन्न उभरते मुद्दों से निपटने के लिए 26 जून 2023 को आयोजित नियामकों के फोरम (एफओआर) की 86वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य समूह का गठन किया गया।

ख) इसकी अवधारणा के पश्चात से नौ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें अंतर-राज्यीय हरित ऊर्जा खुली पहुंच में बैंकिंग के कार्यान्वयन पहलू, आरपीओ ढांचे पर गैर-जीवाश्म ईंधन दायित्वों के निहितार्थ और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) विनियमन के मॉडल को अद्यतन करने पर प्रमुख निर्णय लिए गए।

2) जलविद्युत के विकास में तेजी लाना, विशेष रूप से ग्रिड स्थिरता के लिए पंप स्टोरेज

क) देश के भीतर पम्प भंडारण सहित जल विद्युत संसाधनों के विकास में बाधा डालने वाले उभरते मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए गठित किया गया।

(ख) जल विद्युत विकास में उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श हेतु नौ बैठकें आयोजित की गईं। तदनुसार, भारत भर में जल विद्युत विकास हेतु सिफारिशों के साथ जल विद्युत पर पहली रिपोर्ट जारी की गई है।

3) नियमों का सामंजस्यीकरण:

क) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे विभिन्न नियमों तथा आयोगों द्वारा जारी किए गए विनियमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाई के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त 2023 को आयोजित एफओआर की 87वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य समूह का गठन किया गया।

(ख) बैठक के दौरान सीजीपी और एमवाईटी विनियमों पर मौजूदा मॉडल विनियमों से संबंधित कई मामलों पर चर्चा की गई तथा उन्हें अद्यतन किया गया।

4) डिस्कॉम की व्यवहार्यता:

क) नियामकों के फोरम ने 13 अक्टूबर 2023 को आयोजित अपनी 88वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश ईआरसी (एचपीईआरसी) से प्राप्त प्रति निर्देश के आधार पर डिस्कॉम की दीर्घकालिक स्थिरता के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया, जिसमें बताया गया कि डिस्कॉम की स्थिरता उनके निरंतर वित्तीय घाटे के कारण चिंताजनक है।

(ख) उपर्युक्त के दृष्टिगत, कार्य समूह का गठन किया गया और उसने डिस्कॉम की व्यवहार्यता पर मुद्दों पर चर्चा करके तथा उनके समाधान के लिए सिफारिशें करके अपनी रिपोर्ट तैयार की।

5) स्थायी तकनीकी समिति

क) राज्य स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे के कार्यान्वयन हेतु 18 नवंबर 2015 को सीईआरसी के तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, विनियामक फोरम (एफओआर) की 87वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति और नियामक मामलों पर कार्य समूह के गठन के परिणामस्वरूप, स्थायी तकनीकी समिति का पुनर्गठन आवश्यक है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति और नियामक मामलों पर कार्य समूह के साथ इसका कोई संबंध न हो।

ख) एसटीसी के उद्देश्य इस प्रकार हैं

- (i) राज्य स्तर पर पवन और सौर उत्पादन स्टेशनों के पूर्वानुमान, समय-निर्धारण और विचलन निपटान पर ढांचे की तैनाती और कार्यान्वयन।
- (ii) राज्य स्तर पर सहायक सेवा और रिजर्व के लिए एक ढांचा विकसित करना।
- (iii) राज्यों के भीतर स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी) और प्राथमिक नियंत्रण का कार्यान्वयन।
- (iv) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति में अधिदेशित उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) ढांचे का राज्य स्तर पर शुरुआत/कार्यान्वयन।

ख . एफओआर- कार्य समूह अध्ययन

वितरण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, तथा वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति और परिचालन दक्षता, इस क्षेत्र की समग्र व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है। गत कुछ वर्षों में, विद्युत वितरण क्षेत्र की व्यावसायिक व्यवहार्यता और स्थायित्व में सुधार के लिए विभिन्न सुधार लागू किए गए हैं। 2003 के विद्युत अधिनियम ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और एक ही आपूर्ति क्षेत्र में कई लाइसेंसधारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से एक नियामक ढाँचा प्रस्तुत करके इन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन उद्देश्यों के अनुरूप, एफओआर ने वर्ष के दौरान संबंधित कार्य समूहों द्वारा तैयार किए गए तीन अध्ययनों को निम्नलिखित सिफारिशों के साथ अंतिम रूप दिया:

1) “राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा अधिसूचित आपूर्ति संहिताओं में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने” पर एफओआर रिपोर्ट।

29 जुलाई 2024 को आयोजित नियामकों के फोरम की 92वीं बैठक में रिपोर्ट की सिफारिशों का समर्थन किया गया, जो इस प्रकार हैं:

क) आपूर्ति संहिता अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप होनी चाहिए। अधिनियम के सभी प्रावधानों को आदर्श आपूर्ति संहिता में समाहित किया जाना चाहिए। हालांकि, इन प्रावधानों के अतिरिक्त, आपूर्ति संहिता में अन्य प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं, ताकि लाइसेंसधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के संबंध में उचित निर्देश दिए जा सकें, जैसे कि आपूर्ति प्रणाली और उपभोक्ताओं के वर्गीकरण, नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन, मीटरिंग, कनेक्शन काटना और पुनः कनेक्शन आदि।

(ख) लाइसेंसधारी तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों पर एक अलग अध्याय होना चाहिए, जैसा कि अधिनियम तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नियमों में परिकल्पित है तथा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिदेशों और विनियमों के अनुपालन पर एक अलग अध्याय प्रदान किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कनेक्शन प्राप्त करने हेतु सीईए के विभिन्न विनियमों को समझना आसान हो सके। यह अध्याय वितरण लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की व्यवस्था करते समय उनके द्वारा पालन किए जाने वाले विनिर्देशों और मानकों की जांच करने में भी सहायता करेगा।

घ) एफओआर द्वारा प्रकाशित 2011 के मॉडल आपूर्ति संहिता में दिए गए प्रावधान के अनुसार, “बिजली की चोरी और अनधिकृत उपयोग” पर अध्याय को आपूर्ति संहिता में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में विशिष्ट प्रावधान अधिनियम की धारा 135 बी (बिजली की चोरी), 136 (विद्युत लाइनों और उपकरणों की चोरी) और 137 (चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड) के तहत पहले से ही निर्धारित हैं। तथापि, बिजली की चोरी या अनधिकृत उपयोग के लिए खपत के आकलन की गणना में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति संहिता में एक कार्यप्रणाली प्रदान की जा सकती है।

ड) चूंकि सभी राज्य/संयुक्त आयोग कार्यनिष्पादन मानक (एसओपी) पर अलग-अलग विनियम प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए आपूर्ति संहिता में एसओपी के अनुपालन में चूक के प्रावधानों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

च) अधिनियम के विनियमन 42 के उप विनियमन 3 के तहत परिभाषित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(सीजीआरएफ) की स्थापना और कार्यों को आपूर्ति संहिता में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यधसंयुक्त आयोगों के पास पहले से ही शिकायत निपटान और सीजीआरएफ और लोकपाल पर अलग-अलग विनियम हैं।

क) आपूर्ति संहिता की व्यापक संरचना निम्नानुसार है

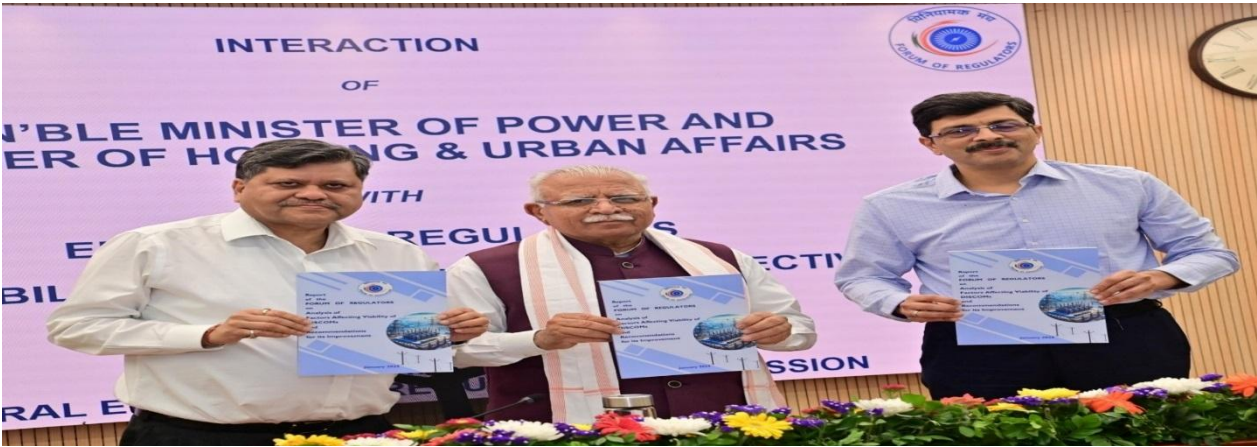
- (i) संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता और प्रारंभ
- (ii) परिभाषाएँ और व्याख्याएँ
- (iii) वितरण लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं के अधिकार और दायित्व
- (iv) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों का अधिदेश और अनुपालन, आपूर्ति की प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण – जिसमें आपूर्ति की प्रणाली, आपूर्ति का वर्गीकरण, उपभोक्ताओं का वर्गीकरण और आपूर्ति के लिए शुल्क संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- (v) नए कनेक्शन जारी करने और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन की प्रक्रिया – जिसमें आपूर्ति प्रदान करने की शर्तों, बिजली सेवाओं के लिए प्रक्रिया, अस्थायी आपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, मौजूदा कनेक्शन में संशोधन की प्रक्रिया, कनेक्शन का हस्तांतरण और सेवाओं के रूपांतरण के प्रावधान शामिल हैं।
- (vi) मीटरिंग– मीटर की आवश्यकता, मीटर और एमसीबीधसीबी की आपूर्ति और स्थापना, मीटर की रीडिंग, मीटर का परीक्षण और मीटर के प्रतिस्थापन पर प्रावधान शामिल हैं
- (vii) उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच
- (viii) बिलिंग
- (ix) विद्युत संयंत्रों, लाइनों या मीटरों से छेड़छाड़, संकट या क्षति
- (x) कनेक्शन काटना और कनेक्शन पुनः जोड़ना
- (xi) सामान्य प्रावधान – हार्मोनिक डंपिंग, उपभोक्ता की स्थापना में जनरेटर और लाइसेंसधारी की आपूर्ति प्रणाली के साथ समानांतर संचालन, फ्रेंचाइजी का प्राधिकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करना

2) “डिस्कॉम की व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण और इसके सुधार के लिए इसकी सिफारिशें” पर एफओआर रिपोर्ट

10 जनवरी 2025 को आयोजित नियामकों के फोरम की 94वीं बैठक में रिपोर्ट की सिफारिशों का समर्थन किया गया, जो इस प्रकार हैं:

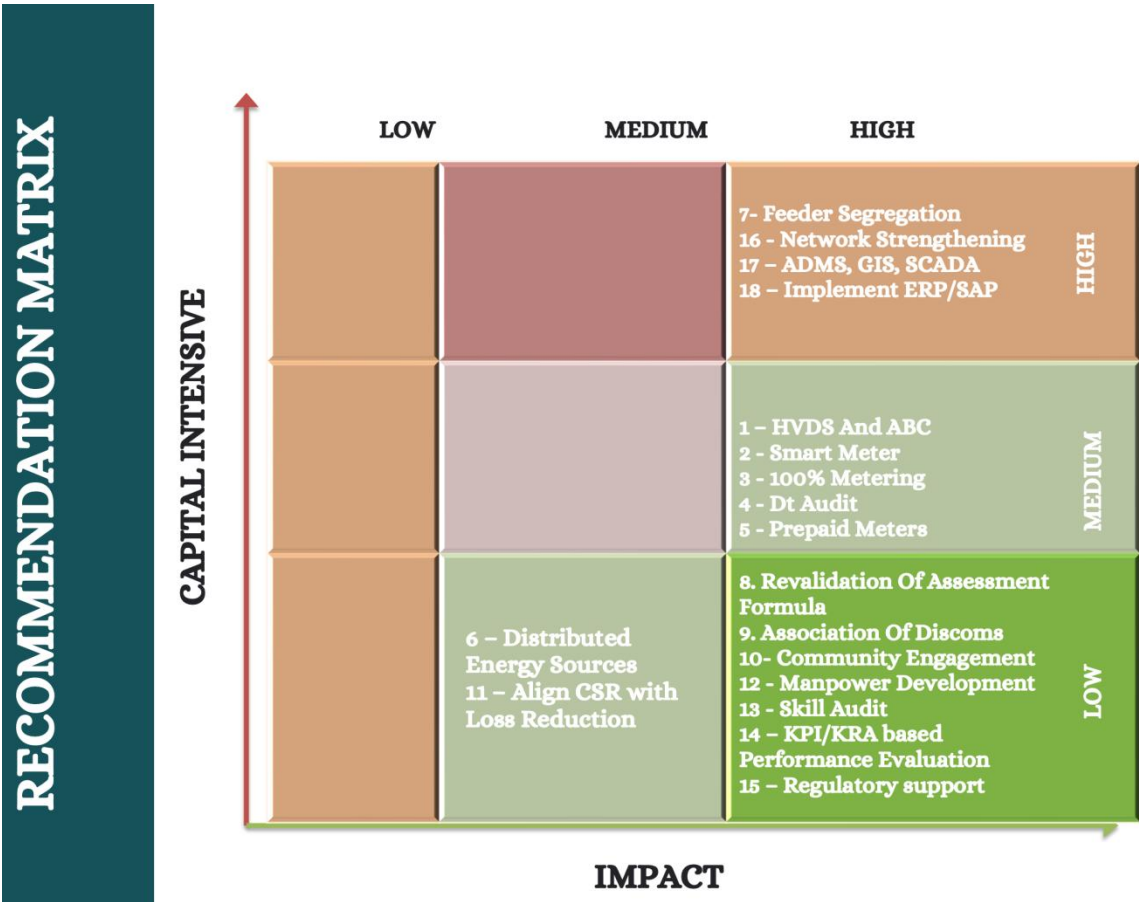
क) सिफारिश मैट्रिक्स

अध्ययन में किए गए विश्लेषण के आधार पर, वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय और परिचालन व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए विस्तृत सिफारिशों के कई सेट बनाए गए हैं। वितरण उपयोगिता की वर्तमान स्थिति के आधार पर इन सिफारिशों को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। प्राथमिकता तय करते समय, निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:



- 1. पूंजी तीव्रता
- 2. परिचालन दक्षता और स्थिरता पर प्रभाव

रिपोर्ट में अपनी प्रमुख सिफारिशें अनुशंसा मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:



रेखाचित्र 1:सिफारिश मैट्रिक्स

हालाँकि, रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि चूँकि प्रत्येक वितरण उपयोगिता अपने संचालन में विशिष्ट होती है और उसकी चुनौतियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए सभी सिफारिशें सभी पर लागू नहीं होतीं। कई प्रमुख मानकों

पर उपयोगिता की विशिष्ट वर्तमान स्थिति के आधार पर, उपरोक्त पहलों को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है।

तालिका 1 –सिफारिशें

S. No.	List of Recommendations
1	एचवीडीएस और एरियल बंच कंडक्टरों का कार्यान्वयन
2	उच्च हानि वाले क्षेत्रों/उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटरिंग आरंभ करना दृ बेहतर विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स उपकरण लागू करना
3	100 प्रतिशत कनेक्शन मीटर से किए जाएंगे
4	डीटी स्तरीय ऊर्जा लेखा परीक्षा
5	कम बिलिंग दक्षता वाले क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर और स्वचालित मीटर रीडिंग
6	वितरित ऊर्जा प्रणालियों को सुविधाजनक बनाना
7	फीडर पृथक्करण – (जहां भी उच्च कृषि भार/उपभोक्ता हो)
8	जहां भी बिलिंग मूल्यांकन के आधार पर की जा रही है, वहां मूल्यांकन फार्मूले का पुनः सत्यापन।
9	वितरण उपयोगिताओं के एक संघ की स्थापना – ज्ञान साझाकरण और नीति वकालत को सुविधाजनक बनाना
10	सामुदायिक सहभागिता – उपभोक्ता जागरूकता अभियान
11	हानि न्यूनीकरण रणनीतियों के साथ सीएसआर के अनुरूप तालमेल बनाना
12	जनशक्ति क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करना
13	जनशक्ति कौशल लेखा परीक्षा और युक्तिकरण/पुनर्नियोजन
14	केपीआई/केआरए आधारित कर्मचारी जवाबदेही और प्रोत्साहन
15	टैरिफ संशोधन – क्रॉस सब्सिडी कटौती – ज़च्छ्झत्। आधारित कर्मचारी लाभ योजना के लिए विनियामक समर्थन
16	नेटवर्क सुदृढीकरण – लाइनों और ट्रांसफार्मरों के ओवरलोडिंग को कम करना
17	उन्नत वितरण प्रबंधन, जीआईएस और एससीएडीए प्रणालियों की स्थापना
18	ईआरपी का कार्यान्वयन, आईटीएआई सक्षम सेवाओं की खोज/डिजिटल परिवर्तन

रिपोर्ट में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि कई मापदंडों पर वितरण उपयोगिताओं की प्रगति के आधार पर, उपरोक्त सिफारिशों की प्राथमिकता बदल सकती है, और इसलिए, उपरोक्त सिफारिशों को प्रत्येक वितरण उपयोगिता के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त सिफारिशों वाली रिपोर्ट माननीय विद्युत मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री द्वारा 16 अप्रैल, 2025 को जारी की गई।

3) "जलविद्युत के विकास में तेजी लाना, विशेष रूप से ग्रिड स्थिरता के लिए पंप स्टोरेज' पर एफओआर रिपोर्ट

अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों को 28 फरवरी 2025 को आयोजित "ग्रिड स्थिरता के लिए जल विद्युत के विकास में तेजी लाना" (वर्चुअल) पर विशेष एफओआर बैठक में अनुमोदित किया गया, जो इस प्रकार हैं:

1) नीतिगत सुधार

- एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली: सभी परियोजना-संबंधी अनुमोदनों को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र/राज्य स्तर पर सशक्त समितियों की स्थापना।
- परिवेश पोर्टल को सरल बनाएं: पूर्ण डेटा प्रस्तुत करने से पहले सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान करना; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इसमें सहायक भूमिका निभानी चाहिए।
- छोटे बांध-टो पावरहाउसों के लिए छूट: 15 मेगावाट तक की ई-प्लो परियोजनाओं के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं।
- प्रतिपूरक वनरोपण (सीए): सीए के लिए निम्नीकृत वन भूमि की अनुमति देना वन विभागों को सीए विवरण भरना; भूमि बैंक बनाना।
- भूमि अधिग्रहण: राज्य नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना; सीए भूमि गणना से नदी घाटियों को बाहर रखा जाएगा।
- वहन क्षमता अध्ययन: अनिवार्य आवश्यकता में ढील दी जाएगी; यदि आवश्यक हो तो हाइड्रो समितियों को इसे पूरा करने का अधिकार दिया जाएगा।
- एफआरए और कैट एनओसी: वास्तविक समय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन को केंद्रीकृत करना राज्य स्तरीय अनुमोदन के लिए समयसीमा निर्धारित करना।
- ग्राम सभा एनओसी: देरी से बचने के लिए परियोजना आवंटन चरण में वन अधिकारों का निपटारा करना।
- चरण-1 एफ.सी. से पहले फॉर्म में लचीलापन: एफ.सी. अनुमोदन से पहले ऑनलाइन फॉर्म में अपडेट की अनुमति।
- ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी को श्वेत श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करना: गैर-प्रदूषणकारी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- मंजूरी की हस्तांतरणीयता: ईसी, एफसी और डीपीआर सहमति नए डेवलपर्स को हस्तांतरित की जानी चाहिए।
- विशेष जल विद्युत कानून: परमाणु ऊर्जा के समान ऊर्जा सुरक्षा में जल विद्युत की भूमिका को मान्यता देना।
- निःशुल्क बिजली संबंधी दायित्व तय करना: मूल समझौता ज्ञापनों का कड़ाई से पालन करना; 15 वर्षों में धीरे-धीरे निःशुल्क बिजली को स्थगित करना; पीएसपी को निःशुल्क बिजली से छूट देना।
- टैरिफ मूल्यहास सुधार: निम्न मूल्यहास दर अवधि को 15 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा लाभार्थी की सहमति से कम दरों की अनुमति दी जाएगी।
- ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी के लिए एलएडीएफ माफ करना: इसके बजाय, एक्स-बस पावर से 1: राजस्व हिस्सेदारी की अनुमति देना।
- सौर/पवन के समान पीएसपी को वित्तपोषित करना: पीएफसी, आरईसी और आईआरईडीए से समान वित्तपोषित शर्तें प्रदान करना।
- आरईसी गुणकरु आरपीओ अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रो/पीएसपी के लिए गुणक (2x-4x) लागू करना।
- आईएसटीएस छूट को 2025 से आगे बढ़ाना: नए हाइड्रो और पीएसपी के लिए 2030 तक विस्तार की सिफारिश करना।

2) पूर्व-योजना चरण

- एसपीवी सृजित करना (यूएमपीपी की भांति): एसपीवी को डीपीआर से लेकर परियोजना हस्तांतरण तक का काम संभालना चाहिए।
- फास्ट-ट्रैक मंजूरी: राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे अधिनियम मॉडल का पालन करना।
- एसपीवी और सीईए द्वारा केंद्रीकृत पूर्वयोजना: मंजूरी के पश्चात प्रतिस्पर्धी टैरिफ खोज सुनिश्चित करना।
- पीएम गति शक्ति के माध्यम से निगरानी: केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से हाइड्रोथीएसपी प्रगति पर नजर रखना।
- समयसीमा के साथ जांचसूची: समयसीमा के साथ एजेंसी-वार जिम्मेदारियों को परिभाषित करना।
- निजी परीक्षण एजेंसियां: मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को अनिवार्य परियोजना परीक्षण करने की अनुमति देना।
- क्षेत्रवार निदेशालय: जांच दक्षता में सुधार के लिए सीईए और अन्य एजेंसियों का विकेंद्रीकरण।

3) संविदाकारों का चयन

- क्यूसीबीएस मॉडल अंगीकृत करना: गुणवत्ता और लागत के आधार पर मूल्यांकन करना; मानदंड के रूप में निष्पादन समय को शामिल करना।
- अनुभव और तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करना। पूर्व हाइड्रो/पीएसपी अनुभव वाले लोगों को प्राथमिकता देना।
- वित्तीय क्षमता का आकलन करना: प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन बांड शामिल करना।
- समय पर कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना: समय-सारिणी का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- संविदा निगरानी को सुदृढ़ करना: वास्तविक समय की निगरानी के लिए डिजिटल उपकरण, ड्रोन और ऑडिट का उपयोग करना।
- विवादों के लिए अधिकार प्राप्त समिति: मुकदमेबाजी में देरी के बिना मुद्दों का शीघ्र समाधान करना।
- सक्षम संविदाकारों को सूचीबद्ध करना: योग्य संविदाकारों का समूह बनाना; भारत में ओईएम विनिर्माण में सहायता करना।

4) संविदाकारों का चयन

- क्यूसीबीएस मॉडल अंगीकृत करना: गुणवत्ता और लागत के आधार पर मूल्यांकन करना; मानदंड के रूप में निष्पादन समय को शामिल करना।
- अनुभव और तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करना। पूर्व हाइड्रो/पीएसपी अनुभव वाले लोगों को प्राथमिकता देना।
- वित्तीय क्षमता का आकलन करना: प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन बांड शामिल करना।
- समय पर कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना: समय-सारिणी का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- संविदा निगरानी को सुदृढ़ करना: वास्तविक समय की निगरानी के लिए डिजिटल उपकरण, ड्रोन और ऑडिट का उपयोग करना।
- विवादों के लिए अधिकार प्राप्त समिति: मुकदमेबाजी में देरी के बिना मुद्दों का शीघ्र समाधान करना।
- सक्षम संविदाकारों को सूचीबद्ध करना: योग्य संविदाकारों का समूह बनाना; भारत में ओईएम विनिर्माण में सहायता करना।

5) टैरिफ का अवधारण

- **टैरिफ विनियमन लचीलापन:** चालू पीएसपी में लंबी अवधि की तैयारी को लेखाबद्ध करना।
- **परियोजना की अवधि 50 वर्ष तक बढ़ाना:** टैरिफ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयोगी जीवन बढ़ाना।
- **बुनियादी ढांचे पर व्यय की सीमा बढ़ाना:** स्थानीय विकास के लिए 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट या वास्तविक राशि की अनुमति देना।
- **श्री-पार्ट पीएसपी टैरिफ:** टैरिफ की संरचना इस प्रकार है:
 - निश्चित लागत (उपलब्धता-आधारित),
 - ऊर्जा शुल्क (शीर्ष रूपांतरण के लिए),
 - सहायक सेवा शुल्क (सिस्टम ऑपरेटर के लिए)।
- **अनुसूचीकरण और मुआवजा ढांचा:** मुआवजा नियमों के साथ डेवलपर, डिस्कॉम और सिस्टम ऑपरेटर की भूमिकाओं को स्पष्ट करना।

6) फास्ट-ट्रैक परियोजना विकास

- **संविदात्मक एवं जोखिम प्रबंधन:** जोखिम शमन उपायों को सक्रिय रूप से परिभाषित करना।
- **मजबूत निगरानी:** डिजिटल उपकरण, मील का पत्थर समीक्षा, वास्तविक समय डेटा सिस्टम को नियोजित करना।
- **एआई और पूर्वानुमान विश्लेषण:** जोखिमों की शीघ्र पहचान करना (जैसे, निर्माण, भूवैज्ञानिक)।
- **केंद्रीकृत डेटा भंडार:** वास्तविक समय प्रगति, कार्यक्षेत्र परिवर्तन और अनुमोदन को ट्रैक करना।

7) हाइड्रो/पीएसपी का मुद्रीकरण

- **सहायक सेवाएं प्रदान करना:** पीआरएस, एसआरएस, आवृत्ति नियंत्रण, वोल्टेज समर्थन, ब्लैक स्टार्ट आदि का मुद्रीकरण करना।
- **जल पर्यटन को बढ़ावा देना:** जलाशयों के आसपास इको-पर्यटन को प्रोत्साहित करना; गैर-टैरिफ आय को लाभार्थियों के साथ 50:50 अनुपात में साझा करना।
- **गाद निष्कर्षण का व्यवसायीकरण:** औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग के लिए तलछट का उपयोग करना।

8) अन्य सिफारिशें

- **विद्युत शुल्क छूट:** शुल्क से बचने के लिए पीएसपी में इनपुट ऊर्जा को गैर-उपभोग के रूप में मानना।
- **भूमि अधिग्रहण लागत कम करना:** सरकारी भूमि को सस्ते दामों पर पट्टे पर देय स्टाम्प शुल्क माफ करना।
- **नोडल एजेंसी द्वारा संविदाकार की पहचान:** डेवलपर्स को विश्वसनीय संविदाकारों से जुड़ने में सहायता करना।
- **कम ब्याज दरें:** सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसपी के लिए डी:ई अनुपात को 80:20 तक समायोजित करना।
- **विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना:** डोमेन विशेषज्ञता के साथ हाइड्रो/पीएसपी-संबंधित विवाद समाधान में तेजी लाना।

घ. क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

विनियामक फोरम (एफओआर) की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक विद्युत नियामक आयोगों (ईआरसी) के कर्मियों का क्षमता निर्माण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में फोरम द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

1. 20 से 21 फरवरी 2025 के दौरान एनपीटीआई परिसर, फरीदाबाद में “उपभोक्ता हितों की सुरक्षा” पर सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कार्यक्रम में 28 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम के दौरान शामिल किए गए प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

- उपभोक्ता हितों का संरक्षण
- उपभोक्ता सशक्तिकरण और शिकायत निवारण तंत्र
- उपभोक्ता शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया – एक आदर्श तंत्र
- ग्राहक सेवा प्रथाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
- डिस्कॉम वित्त में अंतर को कम करना

2. 14 से 20 सितंबर 2024 तक मैड्रिड, स्पेन में “स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाना” विषय पर आयोग सचिवों के लिए तकनीकी अध्ययन दौरा

कार्यक्रम में 15 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम के दौरान शामिल किए गए प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

- स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए विनियम और नीतियां
 - सभी स्तरों पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की मांग बढ़ाना।
 - विनियामक, अनुमति और स्थान निर्धारण सुधारों के माध्यम से प्रवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करना
 - नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश और विनिर्माण में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक बाजार निश्चितता स्थापित करना
 - एक सुदृढ़, स्थिर और विविध नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल का विकास करना
- स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता:
 - सब्सिडी, प्रोत्साहन और कार्बन मूल्य निर्धारण की भूमिका
 - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में बाजारों की भूमिका
 - बिजली बाजार मांग और परिवर्तनशील नवीकरणीय उत्पादन की अन्तरालता के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं

- भविष्य के विद्युत क्षेत्र में पारेषण और बुनियादी ढांचा

- विद्युत ग्रिड में निवेश करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विश्वसनीय, सुरक्षित, स्वच्छ और नवीकरणीय भविष्य के लिए डिजाइन किया गया है।
- डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा और आधुनिक विद्युत ग्रिड के लिए अन्य तैयारियाँ
- एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अन्तरालों का संतुलन

- परिवर्तन में सहायता के लिए अन्य उपकरण:

- ऊर्जा दक्षता और मांग-पक्ष प्रबंधन की भूमिका और इसका विस्तार कैसे किया जाए।
- सुरक्षित, लचीली स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना।

3. 30-31 जनवरी, 2025 और 3-4 फरवरी 2025 के दौरान सिडनी (ऑस्ट्रेलिया), वेलिंगटन (न्यूजीलैंड) में "बाजार परिचालन, नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च वोल्टेज बिजली संचरण, ऊर्जा संक्रमण के लिए नीतिगत मुद्दे, शुद्ध शून्य रणनीति, आदि पर अध्ययन" विषय पर राज्य आयोग के अध्यक्षों के लिए अध्ययन दौरा

कार्यक्रम में 19 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम के दौरान शामिल किए गए प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

- नेटवर्क विनियमन
- थोक और खुदरा बाजार की निगरानी
- खुदरा मूल्य निर्धारण (डिफॉल्ट बाजार प्रस्ताव)
- अनुपालन और प्रवर्तन कार्य
- उपभोक्ता-वितरक विवादों में लोकपाल की भूमिका
- ऑस्ट्रेलिया के कोयला-से-स्वच्छ संक्रमण लक्ष्य
- नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार और पूर्व-व्यावसायिक परिनियोजन के लिए वित्तपोषण
- अति-निम्न-लागत वाले सौर विकास लक्ष्य
- खुला ज्ञान साझाकरण फोरम
- सौर सेल दक्षता को 23 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने की रणनीति
- ग्रिड सुरक्षा चुनौतियाँ, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के साथ
- ऑस्ट्रेलिया के विद्युत परिवर्तन का इतिहास
- नेटवर्क योजना, 24x7ग्रिड संचालन, आपदाओं (जंगल की आग, तूफान) पर प्रतिक्रिया
- ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक्स वाहन बेड़ा (60 बैटरी ईवी)
- अरीनासमर्थित बीईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- बड़े पैमाने पर ईवी संक्रमण की व्यवहार्यता पर चर्चा

- न्यूजीलैंड के बिजली बाजार की निगरानी
- बाजार स्थिरता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को आकार देने में भूमिका
- न्यूजीलैंड के ऊर्जा विनियमन में प्रमुख अभिनेता (वाणिज्य आयोग, गैस उद्योग कंपनी, आदि)
- चुनौतियाँ: वहीनीयता, नवाचार, रुकावट
- ट्रांसमिशन परिचालन और आरई एकीकरण
- न्यूजीलैंड की विद्युत संरचना का अवलोकन (एकाधिकार+ प्रतिस्पर्धी तत्व)
- स्थापित क्षमता, उत्पादन मिश्रण (82 प्रतिशत आरई), और पारेषण विनियमन
- ऊर्जा नीति को आकार देने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग
- स्थिरता, सुरक्षा और नवाचार के लिए वकालत
- भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऊर्जा बाजार संबंधी अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान।

3

विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों (सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी) की वर्ष 2024-25 में उपलब्धियां

क. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण, प्रक्रिया, ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करना और अन्य संबंधित मामले, अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र की फीस और प्रभार और अन्य संबंधित मामले, विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, व्यवसाय का संचालन और परामर्शदाताओं की नियुक्ति आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन तैयारधजारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान, आयोग ने विभिन्न संस्थाओं को कुल 23 ट्रेडिंग लाइसेंस और 113 ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किए। ये स्वीकृतियाँ बाजार में भागीदारी को सुगम बनाने, बिजली व्यापार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और देश भर में ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार को सक्षम बनाने के लिए आयोग के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

ख. राज्य और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

1) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्रभार और बैंकिंग, ट्रांसमिशन लाइसेंस, मांग पक्ष प्रबंधन आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन तैयारधजारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

2) अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ विनियमन, मांग पक्ष प्रबंधन, वितरण लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, नियम व शर्तें तथा अन्य संबंधित मामलों और नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ निर्धारण के नियम व शर्तें आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

3) असम विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता, खुली पहुंच के लिए विद्युत ग्रिड संहिता नियम एवं शर्तें, शुल्क भुगतान आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

4) बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहु-वर्षीय वितरण शुल्क, बहु-वर्षीय पारेषण शुल्क और एसएलडीसी शुल्क, नेट और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सोलर ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण

अनुबंध-1 में दिया गया है।

5) छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तों और संबंधित मामलों, विद्युत वितरण में निष्पादन मानकों और विद्युत आपूर्ति संहिता से संबंधित विनियमों में संशोधन/संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

6) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम और लोकपाल की स्थापना के लिए दिशा-निर्देशों, विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग और हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तों आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

7) गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहु-वर्षीय टैरिफ, नेट मीटरिंग रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम, विद्युत आपूर्ति कोड और संबंधित मामले, आपूर्ति प्रदान करने में किए गए व्यय को वसूलने के लिए लाइसेंसधारी की शक्ति और अन्य विविध शुल्क, हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तों आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

8) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच, संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा, बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अंतर्गत उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और वितरण तथा खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु नियम व शर्तों, विद्युत आपूर्ति संहिता आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

9) हिमालचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामलों, रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड-इंटरएक्टिव सिस्टम, बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली, अल्पकालिक खुली पहुंच और बिजली आपूर्ति कोड आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

10) झारखंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने रूफटॉप सोलर पीवी विनियम, ग्रुप एवं वर्चुअल नेट मीटरिंग, कैप्टिव पावर सत्यापन और विद्युत आपूर्ति कोड एवं शुल्क, जुर्माना एवं प्रभार विनियमन आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

11) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं केन्द्र शासित प्रदेश)

वर्ष के दौरान, आयोग ने वितरण लाइसेंसधारियों के लिए कार्यनिष्पादन मानक, नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद, उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

12) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख)

वर्ष के दौरान, आयोग ने ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और संबंधित मामलों, विद्युत आपूर्ति संहिता, संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

13) कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने शुल्क, मेरिट ऑर्डर डिस्पैच और बिजली खरीद लागत के अनुकूलन, पीयर-टू-पीयर सौर ऊर्जा लेनदेन के कार्यान्वयन, सौर या सौर के बिना रूफटॉप एयरो टरबाइन के कार्यान्वयन और बहु-वर्षीय ट्रांसमिशन, वितरण और खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

14) केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने कठिनाइयों के निवारण, नवीकरणीय ऊर्जा और नेट मीटरिंग तथा न्यायनिर्णयन प्रक्रिया आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

15) मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम व शर्तें, उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम व शर्तें, सहायक सेवाएं, विद्युत गुणवत्ता और हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस प्रभार और बैंकिंग प्रभार के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ता विनियमन 2023 आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

16) महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ, कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, व्यवसाय का लेन-देन और शुल्क और प्रभार, संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा, ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, सौर और पवन उत्पादन के लिए पूर्वानुमान, समय-निर्धारण और विचलन निपटान, मांग लचीलापन और मांग पक्ष प्रबंधन – कार्यान्वयन रूपरेखा, लागत प्रभावशीलता आकलन और मूल्यांकन, विद्युत आपूर्ति कोड और विद्युत गुणवत्ता और उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल आदि सहित वितरण लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन के मानक से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में प्रदान किया गया है।

17) मणिपुर विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ, संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा, सौर और पवन उत्पादन के लिए पूर्वानुमान, समय-निर्धारण और विचलन निपटान तथा कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें आदि से संबंधित

विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

18) मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इससे संबंधित मामलों, विद्युत आपूर्ति संहिता, संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

19) मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने अनुपालन लेखापरीक्षा, ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन, राज्य सलाहकार समिति के गठन आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

20) नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने लाइसेंसधारी के वितरण और पारेषण, रूफटॉप सोलर ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नेटवर्क मीटरिंग आदि के लिए प्रदर्शन के मानकों से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

21) ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने उत्पादन शुल्क निर्धारण, संसाधन पर्याप्तता की रूपरेखा और एकीकृत खदान से कोयले के इनपुट मूल्य निर्धारण हेतु नियम व शर्तों से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

22) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने व्यवसाय के संचालन, कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों, उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें, विद्युत आपूर्ति संहिता, प्रदर्शन के मानक और संबंधित मामलों आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

23) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें 2025, राजस्थान विद्युत ग्रिड संहिता विनियमन 2024, सेवा (आठवां संशोधन) विनियमन 2024, तथा ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियां (द्वितीय संशोधन) विनियमन 2024 से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों एवं आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

24) सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने (ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रिब्यूटेड सोलर पीवी सिस्टम) (संशोधन), संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा, विद्युत आपूर्ति संहिता आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी

किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

25) तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामलों, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

26) तेलंगाना राज्यविद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण अनुबंध-में दिया गया है।

27) त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने सकलधनेट मीटरिंग के अंतर्गत ग्रिड-इंटरैक्टिव सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रणाली से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-८ में दिया गया है।

28) उत्तर प्रदेशविद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने वितरण एवं पारेषण टैरिफ के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ और ओपन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तों से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

29) उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम व शर्तों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य शर्तों आदि से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

30) पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष के दौरान, आयोग ने शुल्क (संशोधन) विनियमन, 2025 से संबंधित विनियमों में संशोधन विरचित/जारी किए। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियमों और आदेशों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

4

राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट

राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति सभी को समान, किफायती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने, बिजली विक्रेता और व्यापारी के विरुद्ध उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और इस क्षेत्र के सतत विकास पर जोर देती है। एफओआर की सभी गतिविधियाँ इन्हीं मूल सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। एफओआर का एक परिभाषित उद्देश्य “उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और विद्युत क्षेत्र में दक्षता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपाय विकसित करना है।”

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फोरम द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

- 1) 90वीं बैठक के दौरान, फोरम ने वितरण लाइसेंसधारी के साथ संविदात्मक माँग वाले एकसमान खुदरा शुल्कों और खुली पहुँच वाले उपभोक्ताओं के संदर्भ में आदर्श संसाधन पर्याप्तता विनियमों को संशोधित करने पर विचार-विमर्श किया। इस मामले को आगे की जाँच के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति पर कार्य समूह को भेज दिया गया।
- 2) फोरम ने अतिरिक्त अधिभार की गणना के लिए एक सामान्य कार्यप्रणाली की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया तथा मामले को नियमों और विनियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह को भेज दिया।
- 3) 91वीं बैठक के दौरान, फोरम ने कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों पर एफओआर मॉडल विनियमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2023 के निर्णय के अनुरूप बनाने की सिफारिश की। फोरम ने यह भी प्रस्ताव दिया कि विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों के तहत चूककर्ता संस्थाओं की परिभाषा को संशोधित कर उसमें व्यापारियों को भी शामिल किया जाए और आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में मौजूदा मीटरों को रेट्रोफिट करने की सिफारिश की।
- 4) आरई नीतियों पर कार्य समूह ने मॉडल डीआरई विनियमों और वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग के कार्यान्वयन पहलुओं को अद्यतन किया।
- 5) 92वीं बैठक के दौरान, फोरम ने एफपीपीसीए टू-अप से संबंधित विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 14 के कार्यान्वयन चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय को सिफारिशें की जाएं।
- 6) इसी बैठक में, फोरम ने स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटरों की स्थापना के लिए समयसीमा को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की तथा विद्युत अधिनियम की धारा 55 के साथ उपयुक्त संरक्षण के लिए विद्युत मंत्रालय को पूर्व थ्व सिफारिशें भेजने पर सहमति व्यक्त की।
- 7) 92वीं बैठक के दौरान, फोरम ने 150 किलोवाट तक के एलटी कनेक्शनों के संबंध में सीएसईआरसी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की और निर्णय लिया कि मामले को जांच के लिए नियमों के सामंजस्य पर कार्य समूह को भेजा जाए।
- 8) इसी बैठक में फोरम ने 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सौर कनेक्शनों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में केएसईआरसी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार किया तथा प्रभावी समाधान के लिए इस मामले को सीईए के समक्ष उठाने का निर्णय लिया।
- 9) 92वीं बैठक के दौरान, फोरम ने दीर्घकालिक अनुबंधों में लागू ट्रेडिंग मार्जिन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया, जहाँ

भुगतान सुरक्षा तंत्र (चैड) की लागत उत्पादकों द्वारा वहन की जाती है। यह निर्णय लिया गया कि दिशानिर्देशों और विनियमों की समीक्षा के लिए विद्युत मंत्रालय और ब्ल्क को सिफारिशें की जाएँ।

- 10) फोरम ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद आदर्श आपूर्ति संहिता को भी अंतिम रूप दिया और अपनाया।
- 11) 94वीं बैठक में, फोरम ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति पर कार्य समूह से नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं और समाधानों के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त की तथा कार्य समूह की सिफारिशों के बाद अध्ययन को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की।
- 12) इसी बैठक में फोरम ने प्रीपेड मीटरिंग के लिए छूट तंत्र पर चर्चा की और निर्णय लिया कि संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग मौजूदा प्रथाओं के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।
- 13) 94वीं बैठक के दौरान, फोरम ने आरएलडीसी से शेड्यूलिंग डेटा तक पहुंच के संबंध में केएसईआरसी के संदर्भ पर चर्चा की और सीईआरसी ने एसईआरसी के लिए ऐसी पहुंच को सुविधाजनक बनाने पर सहमति व्यक्त की।
- 14) फोरम ने रायगढ़-पुगलुर-त्रिशूर एचवीडीसी प्रणाली पर उच्च आईएसटीएस शुल्क के संबंध में केएसईआरसी के संदर्भ पर भी चर्चा की और सहमति व्यक्त की कि सीईआरसी संभावित पीएसडीएफएनसीईएफ वित्तपोषण सहायता के लिए पीजीसीआईएल और विद्युत मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।
- 15) 94वीं बैठक में, फोरम ने "डिस्कॉम की व्यवहार्यता" पर कार्य समूह की अंतिम रिपोर्ट को अपनाया और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे विद्युत मंत्रालय और सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को भेजने का निर्णय लिया।
- 16) 18 अक्टूबर 2024 की विशेष बैठक में, फोरम ने बीईआरसी के संदर्भ के आधार पर, आरई परियोजनाओं के विलंबित कमीशनिंग के लिए डेवलपर्स से वसूले गए परिसमाप्त नुकसान में डिस्कॉम को हिस्सा देने के लिए एसबीडी खंडों में संशोधन की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

टैरिफ नीति और राष्ट्रीय विद्युत नीति में रेखांकित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोरम के सदस्य ईआरसी की उपलब्धियां इस रिपोर्ट में नीचे दी गई हैं:

- 1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ (अनुबंध-II)
- 2) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की समयसीमा (अनुलग्नक-III)
- 3) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल का कामकाज (अनुबंध-IV)

5

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) के अध्यक्ष

विनियामक फोरम के सदस्य (31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
1	श्री जिष्णु बरुआ	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
विनियामक फोरम के सदस्य		
2	श्री पी. वेंकट राम रेड्डी (सदस्य-वित्त/प्रभारी अध्यक्ष)	आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी)
3	श्री आर के जोषी	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)
4	श्री कुमार संजय कृष्ण	असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी)
5	श्री आमिर सुभानी	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)
6	श्री हेमन्त वर्मा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीएसईआरसी)
7	न्यायमूर्ति (श्री) उमेश कुमार	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)
8	श्री अनिल मुकीम	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी)
9	श्री नंद लाल शर्मा	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)
10	श्री डी.के. शर्मा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एचपीईआरसी)
11	रिक्त	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी)
12	श्री आलोक टंडन	गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
13	श्री रफी अंब्राबी	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
14	श्री पी. रवि कुमार	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)
15	श्री टी.के. जोस	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी)
16	श्री गोपाल श्रीवास्तव (कार्यवाहक अध्यक्ष)	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी)
17	श्री संजय कुमार	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी)
18	श्री रेंगथनवेला थांगा	मणिपुर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएनईआरसी)
19	श्री चंदन कुमार मंडल	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी)
20	श्री बेंजामिन एल. ट्लुमटिया	मिजोरम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमजेडईआरसी)
21	श्री खोसे सेल	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी)
22	श्री गजेन्द्र महापात्रा (पदेन अध्यक्ष)	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी)

23	श्री विश्वजीत खन्ना	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी)
विनियामक फोरम के सदस्य		
24	डॉ. राजेश शर्मा	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)
25	श्री के.बी. कुंवर	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसएसईआरसी)
26	श्री आर. मणिवन्नन	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी)
27	न्यायमूर्ति (डॉ.) देवराजू नागार्जुन	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टीएसईआरसी)
28	रिक्त	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टीईआरसी)
29	श्री अरविंद कुमार	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)
30	श्री मदन लाल प्रसाद	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यूईआरसी)
31	डॉ. एम.वी. राव	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)



V.K. KHOSLA & CO.
Chartered Accountants

सेवा में,
सचिव,
विनियामक फोरम,
सचिवालय: मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर,
नई दिल्ली - 110029.

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सेवाओं (क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाओं के लिए) के लिए वर्ष के दौरान विनियामक फोरम द्वारा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु. 1.00 करोड़ की वित्तीय सहायता की राशि में से रु. (-) 58.33 की शेष अव्ययित निधियां, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगे ले जाई गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया है:

- क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलनपत्र के मामलों में और
- ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 002283एन

Kam Khosla



(कमल खोसला)
साझेदार
सदस्यतासं. : 095944
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 24 जुलाई, 2025
यूडीआईएन: 25095944BMJJUS8522

316-318 Second Floor, LSC Block-A6, DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi-110063
Mob. : 9810268150, 9311905894 E-mail : amit@vkkhoslaco.com; kam_khosla@yahoo.co.in

विनियामक फोरम			
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र			
(राशि - रु. में)			
कोरपस/पूँजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूँजी निधि	1	3,70,10,643	3,70,10,643
रिज़र्व एवं अधिशेष	2	2,45,82,279	3,07,68,293
निश्चित की गई/ बंदोबस्त निधियां	3	(58)	25
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	34,49,622	75,99,282
कुल		6,50,42,486	7,53,78,243
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	1,07,390	1,70,647
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	6,49,35,096	7,52,07,596
कुल		6,50,42,486	7,53,78,243
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन

Handwritten signature

(कमल खोसला)

(साइनेदार)

एम.सं.: 095944



आंतरिक वित्तीय सलाहकार

Handwritten signature

सचिव

Handwritten signature

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन सं.: 25095944BMJJUS8522

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि - रु. में)			
आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
फीस/अंशदान	7	3,00,00,000	3,00,00,000
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	81,29,189	8,00,00,125
अर्जित ब्याज	8	49,45,455	47,77,565
अन्य आय		17,590	18,037
कुल (क)		4,30,92,234	4,27,95,727
व्यय			
स्थापना व्यय	10	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	3,84,57,437	4,18,60,602
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		81,29,189	80,00,125
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		-	-
मूल्यहास (अनुसूची 5 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		56,712	92,824
पूर्व अवधि व्यय		-	-
कुल (ख)		4,66,43,339	4,99,53,552
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क-ख)		(35,51,104)	(71,57,824)
कर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)		-	-
कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)		-	-
सामान्य रिज़र्व को/से अंतरण		(35,51,104)	(71,57,824)
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन




आंतरिक वित्तीय सलाहकार


सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 24 जुलाई, 2025
यूडीआईएन सं.: 25095944BMJJUS8522

(राशि - रु. में)

विनियामक फोरम				
31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां				
		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष
अनुसूची 1 - कोरपस/पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष		3,70,10,643		3,70,10,643
जोड़: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान		-	-	-
जोड़/(घटा):आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		-	-	-
वर्ष के अंत में शेष		3,70,10,643		3,70,10,643
अनुसूची 2 - रिज़र्व एवं अधिशेष:		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष
1. रिज़र्व पूंजी:				
अंतिम खाते के अनुसार		-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		-	-	-
2. पूनर्मूल्यन रिज़र्व:				
अंतिम खाते के अनुसार		-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		-	-	-
3. विशेष रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार		-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		-	-	-
4. सामान्य रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार		3,07,68,293	3,79,26,117	
घटा: व्यय का आय पर आधिक्य		(35,51,104)	(71,57,824)	
घटा: वर्ष के दौरान काटना		(26,34,910)	-	
(अर्थात् निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए कर का समायोजन)				
कुल		2,45,82,279		3,07,68,293

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन



स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 14 जुलाई, 2025

यूडीआईएन सं.: 25095944 BM JTOS8522

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फॉरम			
31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ			
(राशि - रु. में)			
अनुसूची 3 - निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियाँ	निधि-वार ब्रेक-अप		पूर्ववर्ती वर्ष (146)
	योजना निधि		
क) निधियों का आरंभिक शेष		25	
ख) निधियों में परिवर्धन:			
i. दान/अनुदान	1,00,00,000		
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	39,840	1,00,39,840	80,24,772
iii. राज्य एजेंसियों से प्राप्त रिफंड			
कुल (क+ख)		1,00,39,865	80,24,626
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय			
i. प्रजीगत व्यय			
- नियत आस्तियाँ	-	-	-
- अन्य	-	-	-
कुल (i)			
ii. राजस्व व्यय			
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	-	-	-
- किराया	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	81,29,189	81,29,189	80,00,125
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		19,10,735	24,476
कुल (ii + iii)		1,00,39,924	80,24,601
कुल (ग) = (i + ii + iii)		1,00,39,924	80,24,601
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		(59)	25
नोट			
1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर सगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।			
2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।			

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-002283एन
(कमल-खोसला)
(साइनेदर)
एम.सं.-095944

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 29 जुलाई, 2025
यूडीआईएन सं.: 25095944BMJJUS8522

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम			
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां			
		(राशि - रु. में)	
		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान			
क - चालू देयताएं			
1. स्वीकृतियां			
2. विविध ऋणदाता :			
क) माल के लिए			
ख) अन्य			
3. प्राप्त अग्रिम			
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याज:			
क) जमानती ऋण/उधार			
ख) गैर-जमानती ऋण/उधार			
5. सांविधिक देयताएं :			
क) अतिदेय			
ख) अन्य			
6. अन्य चालू देयताएं			
कुल (क)			
ख - प्रावधान			
1. करायान के लिए			50,73,620
(ii) पूर्ववर्ती वर्ष			50,73,620
(iii) चालू वर्ष			
2. ग्रेचुअटी			
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन			
4. संचयित अवकाश नकदीकरण			
5. व्यापार वारंटियां/दावे			
6. अन्य:			
(i) प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस		24,500	24,500
(ii) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय		2,95,564	2,94,086
(iii) प्रतिदेय यात्रा व्यय (फोरम की निधि)		22,51,529	
(iv) प्रतिदेय कार्यालय व्यय		1,974	1,374
(v) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय		42,100	31,000
(vi) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय		64,805	65,227
(vii) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)		4,03,009	
(viii) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस		12,372	12,043
(ix) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस		17,26,136	17,26,136
(x) सीजीएसटी+एसजीएसटी+आईजीएसटी पर प्रतिदेय टीडीएस		2,84,228	3,59,626
(xi) प्रतिदेय वेबसाइट व्यय		69,541	11,670
		34,49,622	25,25,662
कुल (ख)			
कुल (क) + (ख)		34,49,622	75,99,282
		34,49,622	78,99,282

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन



आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 14 जुलाई, 2025
यूडीआईएन सं.: 25095944BMJTJ0S8522

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनात्मक के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 5 - अचल आस्तियां	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक			
		वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में	
क. अचल आस्तियां													
1. भूमि:													
क) पूर्ण स्वामित्व													
ख) पट्टे पर													
2. भवन:													
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर													
ख) पट्टे वाली भूमि पर													
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर													
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर													
3. संयंत्र और मशीनरी और उपकरण	85,917	-	32,073	53,844	47,206	5,177	-	27,301	25,082	28,762	38,711		
4. वाहन													
5. फर्नीचर, फिक्सचर													
6. कार्यालय उपकरण	25,840	-	12,150	13,690	21,832	368	-	10,377	11,823	1,867	4,008		
7. कंप्यूटर/साहायक उपकरण	10,53,990	-	5,21,870	5,32,120	9,26,062	51,167	-	5,21,870	4,55,359	76,761	1,27,928		
8. विद्युत अधिष्ठापन													
9. लाइब्रेरी की पुस्तकें													
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति													
11. अन्य निवत आस्तियां													
चालू वर्ष का कुल	11,65,747	-	5,66,093	5,99,654	9,95,100	56,712	-	5,59,548	4,92,264	1,07,390	1,70,647		
पूर्ववर्ती वर्ष	11,31,853	33,894	-	11,65,747	9,02,276	92,824	-	-	9,95,100	1,70,647	1,70,647		
ख. पूंजीगत अधिनिर्मित उत्पादन													
कुल	11,65,747	-	5,66,093	5,99,654	9,95,100	56,712	-	5,59,548	4,92,264	1,07,390	1,70,647		
उपरोक्त सहित अवकाश आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।													

उपरोक्त सहित अवकाश आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।

इससे संबंधित तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

समूची सेवाकार

एफ.आर.नं.: 00228332



[Signature]

अंतरिक वित्तीय सहायकार

[Signature]

सचिव

Place: New Delhi

तिथि: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन सं.: 25095944BMJTJUS8522

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		(राशि - रु. में)	
अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क - चालू आस्तियां			
1. माल सूची :			
क) स्टोर और स्पेयर्स		-	-
ख) खुले औजार		-	-
ग) बिक्री के लिए माल		-	-
तैयार माल		-	-
अर्धनिर्मित उत्पादन		-	-
कच्चा माल		-	-
2. विविध देनदार:			
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज		-	-
घटाए: वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाले गए		-	-
ख) अन्य		-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		24	24
4. बैंक शेष :			
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :			
- चालू खातों पर		-	-
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)		-	-
(i) नियत जमा		3,70,10,644	3,70,10,644
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी जमा		2,02,55,000	2,31,60,000
- बचत खातों पर		-	-
(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 000068)		64,413	50,289
(ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 1708 - एमओपी)		3,32,006	6,06,751
		5,76,62,063	6,08,27,684
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ :			
चालू खातों पर		-	-
जमा खातों पर		-	-
बचत खातों पर		-	-
5. डाकघर बचत खाते			
कुल (क)		5,76,62,087	6,08,27,708

जारी....2...

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन



स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 24 जुलाई, 2025
स्थान : नई दिल्ली

प्री अड्रेशन सं: 25095944BMJJUS8522


आंतरिक वित्तीय सलाहकार


सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

		(राशि - रु. में)	
		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)			
ख - ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ			
1. ऋण :			
क) स्टाफ			
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयाँ			
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)			
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशिवाँ :			
क) पूंजीगत लेखा पर			
ख) पूर्व भुगतान			
ग) अन्य			
(i) प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)			
पूर्ववर्ती वर्ष			
घटाएँ: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए			
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस):			
पूर्ववर्ती वर्ष			
चालू वर्ष			
(iii) आत्म मूल्यांकन कर:			
पूर्ववर्ती वर्ष			
(iv) प्राप्य बैठक व्यय			
(v) पूर्वदत्त व्यय			
(vi) प्रशिक्षण अग्रिम (फोरम की निधि)			
(vii) जीएसटी (इनपुट) :			
चालू वर्ष			
जोड़: अग्रिम कर:			
पूर्ववर्ती वर्ष			
चालू वर्ष			
जोड़: प्राप्य जीएसटी (आउटपुट):			
चालू वर्ष			
जोड़: प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस:			
पूर्ववर्ती वर्ष			
चालू वर्ष			
3. प्रोद्भूत आय:			
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर			
ख) निवेशों पर - अन्य			
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर			
घ) अन्य (रु. की अप्रामा देय आय सम्मिलित है)			
4. प्राप्ति योग्य द्रावे			
कुल (ख)			
कुल (क+ख)			

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड क.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002283एन



स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 25 जुलाई, 2025
यूडीआईएन सं.: 25095944BMJJUS8522

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम		
31 मार्च, 2025 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां		
अनुसूची -7. फीस/अभिदान	(राशि - रु. में)	
	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	3,00,00,000	3,00,00,000
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्शकारी शुल्क	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
i) आरटीआई शुल्क	-	-
कुल	3,00,00,000	3,00,00,000
नोट: प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाएं		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन



[Signature]

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

[Signature]

सचिव

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन सं.: 25095944BMJJUS8522

विनियामक फोरम		
31 मार्च, 2025 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां		
अनुसूची -8- अर्जित ब्याज	(राशि - रु. में)	
	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में	49,43,910	47,76,036
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) संस्थानों में	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में	1,545	1,529
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) डाकघर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर :		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज	-	-
कुल	49,45,455	47,77,565
नोट - स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन

(कमल खोसला)
(साइनेडर)
एम.सं.: 095944



आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन सं.: 25095944BMJJUS8522

विनियामक फोरम		
31 मार्च, 2025 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां		
	(राशि - रु. में)	
अनुसूची -9- अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वाधिकृत आस्तियाँ	7,255	-
ख) अनुदानों से अर्जित, या निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय	10,355	18037
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	-	-
कुल	17,610	18,037
अनुसूची -10- स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	-	-
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	-	-
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

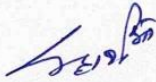
इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन


(कमल खोसला)
(साइनेडर)
एम.सं. : 095944


आंतरिक वित्तीय सलाहकार


सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 14 जुलाई, 2025

यूडीआईएन सं.: 25095944BMJTUS8522

विनियामक फोरम		
31 मार्च, 2025 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां		
अनुसूची -11- अन्य प्रशासनिक खर्च	चालू वर्ष	(राशि - रु. में) पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	38,02,673	35,39,946
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	-	-
घ) विद्युत एवं शक्ति	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	4,700	-
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया, दरें एवं कर	-	-
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,69,611	1,36,478
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	4,976	4,328
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	1,54,63,063	1,42,59,056
ण) अभिदान व्यय	-	-
त) फीस पर व्यय	-	-
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	34,490	2,450
द) आतिथ्य व्यय	-	-
ध) व्यावसायिक प्रभार	9,89,010	8,53,797
न) अशोध संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) अपलिखित अशोध शेष	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन एवं प्रचार (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	-	-
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	1,79,53,293	2,29,70,410
कक) सचिवीय व्यय	-	-
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
i) अन्य व्यय (अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान का निवल)	29,415	56,994
ii) वेबसाइट व्यय	6,206	15,093
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	-	-
iv) अपील के लिए फीस	-	-
कुल	3,84,57,437	4,18,60,602

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन



(कमल खोसला)
(साईनदार)

एम.सं.: 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन सं.: 250959448MJJVS8522

विनियामक फोरम

अनुसूची 12 एवं 13: (31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना;
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना;
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउट सोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना;
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना; और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय से निर्दिष्ट करती है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन


(कमल खोसला)
साझेदार

सदस्यता सं.: 095944

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन: 25095944BMJJUS8522

विनियामक फोरम (एफओआर)


आंतरिक वित्तीय सलाहकार


सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (पिछले पृष्ठ से जारी)

1. लेखांकन की पद्धति

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखाबहियों में की जाती है।

3. नियत आस्तियां और मूल्यहास

नियत आस्तियों पर मूल्य हास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4. अनुदान

क्षमता निर्माण और परामर्श के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। अव्ययित अनुदान वापस किया गया है या देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. उत्तरवर्ती घटना को समायोजित करना
कर से संबंधित मामले

(क) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए जांच मूल्यांकन

(i) आयकर छूट की अनुपस्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016-17 (वित्त.व. 2015-16) के लिए ₹.25,03,750/- का कर और ₹.21,70,000/- का जुर्माना लगाया है। एफओआर ने कर का भुगतान किया है और जुर्माने के विरुद्ध सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफओआर नं. 002283एन

FRN 2283 N
(कमल खोसला)

साझेदार

सदस्यता सं.: 095944

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 14 जुलाई, 2025

यूडीआईएन: 25095944BMJJUS8522

विनियामक फोरम (एफओआर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (पिछले पृष्ठ से जारी)

- (ii) दिनांक 31.07.2019 को केविआ एवं एफओआर के उच्चतर अधिकारियों ने, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष से भेंट की जहाँ एफओआर के लिए छूट के अनुरोध से संबंधित मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। तथापि, अध्यक्ष, सीबीडीटी को ज्ञात हुआ कि एफओआर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किए जाने के लिए कोई समुचित आधार नहीं है। अध्यक्ष, एफओआर/केविआ की ओर से दिनांक 11.09.2019 का अर्धशासकीय पत्र अध्यक्ष, सीबीडीटी को सकारात्मक निर्णय और एफओआर को छूट प्रदान किए जाने के अनुरोध के साथ भेजा गया। तथापि, कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः भविष्य में एफओआर को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किया जाना निश्चित नहीं है।
- (iii) वित्त मंत्रालय ने 18 मार्च, 2020 को अपनी अधिसूचना द्वारा एक नई योजना अर्थात् "विवाद से विश्वास योजना 2020" आरंभ की है। आरंभ की गई योजना, प्रत्यक्ष करों के मामले में विवादों के समाधान के लिए है। उक्त योजना के अनुसार, विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज से संबंधित कोई भी अपील (31 जनवरी, 2020 को लंबित) का निपटान 31 मार्च, 2020 को या इस से पूर्व विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज, जैसा भी मामला हो, के 25% (और इस के बाद 30 जून, 2020 को या इससे पूर्व 10% का अतिरिक्त भुगतान द्वारा) के भुगतान द्वारा किया जा सकता है। तथापि, अब इस योजना को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई, 2020 एवं 15 मई, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त योजना का लाभ उठाया जाए और नि.व. 2016-17 के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने (उपर्युक्त मद (iv) में संदर्भित है) का भुगतान किया जाए और मामले को समाप्त किया जाए। तदनुसार, वित्त. व. 2020-21 के दौरान, एफओआर सचिवालय ने रु.5,42,500/- की राशि का भुगतान कुल जुर्माना राशि के 25% के लिए किया और आयकर प्राधिकारियों के अधीन इस मामले की समाप्ति के दिनांक 15 जून, 2021 का अंतिम आदेश विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

विनियामक फोरम (एफओआर)

सनदी लेखाकार

एफओआरएन: 002283एन

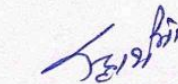

(कमल खोसला)
साझेदार

सदस्यता सं.: 095944

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 14 जुलाई, 2025

यूडीआईएन: 25095944BMJTUS8522



आंतरिक वित्तीय सलाहकार



सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (पिछले पृष्ठ से जारी)

6. आकस्मिक देयताएं

- (i) वित्तीय वर्षों 2005-06 से 2014-15 के लिए आयकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है और ब्याज/जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण और उपबंध नहीं किया गया है जो कि आयकर छूट प्राप्त नहीं होने की दशा में हो सकते हैं।
- (ii) पूर्व वर्षों के लिए सेवाकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

एफओआर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अतः कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है/उपबंध नहीं किया गया है।

8. ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश

ऑटोस्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश ऑटोस्वीप/फ्लेक्सी डिपॉजिट में सावधि जमा और अल्पकालिक जमा को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

9. वस्तु एवं सेवा कर

- (i) यह पाया गया है कि बहियों और जीएसटी पोर्टल के अनुसार जीएसटी खाता-बहियों के बीच कुछ समाधान अंतर हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। हमारे सत्यापन के अनुसार, बहियों और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही के बीच रु. 54,977/- का अंतर है, जिसमें से रु. 57,822/- मई, 2023 में की गई लिपिकीय त्रुटि के कारण है, और शेष रु. 46,912/- पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए समाधान नहीं की गई राशि है।
- (ii) प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस से संबंधित रु. 16,984 की राशि का समाधान रिपोर्टिंग की तारीख को नहीं हुआ है और वह समाधान के अध्यधीन है।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

विनियामक फोरम (एफओआर)

सनदी लेखाकार

एफओआर नं.: 002283एन

FRN 2283 N
(कमल खोसला) LHI

साझेदार

सदस्यता सं.: 095944

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन: 25095944BMJTUS8522

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (पिछले पृष्ठ से जारी)

10. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनःव्यवस्था की गई।

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन


(कमल खोसला)
साझेदार

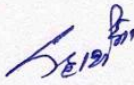
सदस्यता सं. 095944

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन: 25095944BMJJUS8522

विनियामक फोरम (एफओआर)


आंतरिक वित्तीय सलाहकार


सचिव

विनियामक फोरम 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान					
प्राप्ति	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24	भुगतान	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24
1. आवधिक आय:			1. निर्धारित को रिपोर्ट:		
(क) भुगतान	23.75	23.75	भारत सरकार - विद्युत मंत्रालय - कोकन निधि (समाप्त निर्माण एवं परामर्श के लिए)	19,10,740.00	73,83,880.00
(ख) वैक					
(i) भुगतान खाता:					
भुगतान बैंक और डीएम - कोकन निधि (समाप्त निर्माण एवं परामर्श के लिए)	2,32,10,289.00	2,91,48,499.38			
भुगतान बैंक और डीएम - कोकन निधि (समाप्त निर्माण एवं परामर्श के लिए)	6,06,781.40	60,748.33			
(ii) समाप्त वर्ष (कोकन निधि)	3,70,10,644.00	3,70,10,643.73			
2. निर्धारित से रिपोर्ट:			2. अन्य:		
भारत सरकार - विद्युत मंत्रालय - कोकन निधि (समाप्त निर्माण एवं परामर्श के लिए)	1,00,00,000.00	80,00,000.00	(क) वैक एवं संगोष्ठी व्यय	1,53,07,737.00	1,37,52,406.00
			(ख) व्यवसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	8,85,753.00	7,29,323.00
			(ग) भुगतान निर्माण एवं परामर्श:		
			- कोकन निधि	1,52,98,755.00	1,44,89,380.00
			- कोकन निधि	81,28,866.00	6,40,405.00
			(घ) प्रशासनिक व्यय:		
			- बैंक प्रभार (कोकन निधि)	-	146.32
			- बैंक प्रभार (कोकन निधि)	317.73	305.93
			- भुगतान एवं लेन-देन सागरी व्यय	35,01,077.00	32,27,464.00
			- भुगतान एवं लेन-देन सागरी व्यय	1,69,611.00	1,36,478.00
			- व्यवसायिक प्रभार	59,000.00	21,000.00
			- वाहन चार्ज	4,976.00	4,328.00
			- वेल्डिंग व्यय	-	5,203.00
			- अन्य व्यय:		
			- ई-टीएस फंडल करने हेतु व्यय	295.00	277.00
			- कार्यालय व्यवस्थापन परीक्षा व्यय	31,486.00	55,687.00

इससे संबंधित तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी. के. कोसला एच. के.
सचिवी सेवाकार

एच.आर.ए. 06/12/2024

(कमल कोसला)
(साक्षर)
एम.सी. 06/12/24

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 06 जुलाई, 2025

मुद्रांकन सं.

25095944BMJJVS8522

अतिरिक्त विधीय सहायकार

सचिव

विनियामक फोरम 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान					
प्राप्ति	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24	भुगतान	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24
6. अन्य प्राप्ति					
- अवशिष्ट की बिल्ली (ऑफिस उपकरण)	13,800.00	-			
- प्रशिक्षण अग्रिम (एफओआर निधि)	-	23,54,362.00			
- प्रशिक्षण अग्रिम (एफओआर की निधि)	-	15,00,000.00			
- प्राप्य सदस्यता फीस	-	8,00,000.00			
- प्राप्य सदस्यता व्यय	1,10,930.00	-			
- बैंक के लिए अग्रिम	8,49,138.00	15,69,569.00			
- जीएसटी (इनपुट) दावा	-	28,29,220.00			
- प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	-	2,37,018.00			
- विज्ञापन, सौमित्र एवं व्यवसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	11,93,279.00	26,92,266.00			
- सीजीएसटी, एलजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	2,73,804.00	5,92,050.00			
- प्राप्य टीडीएस	97,16,515.00	4,50,863.00			
- व्यवसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	71,749.00	-			
- केनरा बैंक के साथ एकत्री से उपयोजित ब्याज	4,80,953.00	-			
- प्राप्य बीएसटी (अउटपुट)	54,80,000.00	54,00,000.00			
- आसकर रिफंड से ब्याज	10,335.00	18,037.00			
कुल	12,34,25,169.21	12,81,85,002.46	कुल	12,34,25,169.21	12,81,85,002.46

इससे संबंधित तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी. के. कोसला एडव. के.
समिती सेवाकार
एक आरएन. 00222/2024
22/08/2024
(कैमल कोसला)
(साक्षी)
एम.सं. : 0959666

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2025
पुडीआईएन सं. : 25095944BMJTUS8522



अंतरिम वित्तीय सलाहकार

सचिव

विनियामक फोरम

वि.व. 2024-2025 के लिए सरकारी वित्तीय सहायता के लेखा का विवरण

(राशि रु.में)

विवरण	वि.व. 2024-2025	वि.व. 2023-2024
आरंभिक शेष	25	60,748
जोड़:	39,840	24,772
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = रु. शून्य)	1,00,00,000	80,00,000
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि		
कुल (क)	1,00,39,865	80,85,520
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	75,72,590	74,20,308
क्षमता निर्माण	5,56,280	6,40,405
बैंक प्रभार	318	306
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस	39,840	24,476
अव्ययित वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस	18,70,895	-
कुल (ख)	1,00,39,923	80,85,495
कुल (क-ख)	(58)	25
अगले वर्ष के लिए अयोचित शेष राशि	(58)	25

इससे संबंधित तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी. के. खोसला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002283एन

साइनेचर
सदस्यता सं.: 095944

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 24 जुलाई, 2025

यूडीआईएन: 25095944BMJJVS8522

7

आरपीओ अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्ट

8 सितंबर 2022 के “विनियामक फोरम (संशोधन) नियम, 2022” के अनुसार, एफओआर को केंद्र सरकार या राज्य आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, जो भी अधिक हो, उस को इकाई जिसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिजली की खरीद का दायित्व दिया गया है को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिजली की खरीद के लक्ष्यों पर अनुपालन पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी/कार्य सौंपा गया है।

विनियामक फोरम (संशोधन) नियम का प्रासंगिक संशोधन नियम नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:—

“....

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 166 की उप-धारा (2) और (3) के साथ पठित धारा 176 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनियामक फोरम नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

....

ग) नवीकरणीय खरीद अनुपालन की निगरानी – (प) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, कैंपेस उपभोग और खुली पहुंच के माध्यम से बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं द्वारा, नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए केंद्र सरकार या राज्य आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन, जो भी अधिक हो, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार।

नवीकरणीय ऊर्जा से खरीद के लक्ष्यों के अनुपालन के लिए डेटा और उसके विश्लेषण से युक्त एक वार्षिक रिपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष की 31 मई तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, एफओआर ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा अधिसूचित नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) के साथ-साथ संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी के माध्यम से संबंधित संस्थाओं से राज्य ईआरसी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के संबंध में आरपीओ डेटा एकत्र करने के लिए एक मानकीकृत प्रारूप विकसित और प्रसारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करना और आरपीओ अनुपालन के व्यवस्थित मूल्यांकन को सुगम बनाना था। इसके परिणामस्वरूप, मणिपुर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आँकड़े प्राप्त हो गए हैं। विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ ईआरसी ने आरसीओ (बीईई लक्ष्य) और संबंधित ईआरसी द्वारा निर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्यों, दोनों के संबंध में आँकड़े उपलब्ध कराए, जबकि कुछ ने दोनों लक्ष्यों में से किसी एक के संबंध में स्थिति प्रस्तुत की। इसके अलावा, कुछ प्रस्तुतियों में यह पाया गया कि डेटा में सभी संबंधित संस्थाएं सम्मिलित नहीं थीं।

राज्य/संयुक्त आयोगों से प्राप्त आरसीओ/आरपीओ डेटा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरपीओ स्थिति का सारांश अनुबंध-V के रूप में संलग्न है।

वर्ष के दौरान सीईआरसी/एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी महत्वपूर्ण विनियम और आदेश

1. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम का नाम	अधिसूचना की तारीख
1	केंद्रीय विद्युत विनियामकआयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024	15.03.2024
2	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 का विस्तार	28.03.2024
3	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024	23.05.2024
4	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024	12.06.2024
5	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024	19.06.2024
6	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024	12.07.2024
7	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024	05.08.2024
8	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	23.10.2024
9	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 के विनियम 8 के खंड 8 की प्रयोज्यता की अवधि के लिए विस्तार	29.11.2024
10	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	17.12.2024
11	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025	07.01.2025
12	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025।	07.01.2025
13	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की शर्तें और नियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025	04.02.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश (स्वतः संज्ञान वाले)	जारी करने/निपटान की तारीख
1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को प्रभावी करने में कठिनाइयों को दूर करना (तीसरा आदेश)।	22.12.2024
2	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संशोधित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन में, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए, जिसका टैरिफ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, उत्पादन कंपनियों द्वारा उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण हुए	29.11.2024

क्र.सं.	आदेश (स्वतः संज्ञान वाले)	जारी करने/निपटान की तारीख
	व्यय की टैरिफ के माध्यम से वसूली के लिए स्वतः संज्ञान याचिका संख्या 6धएसएम2021 के दिनांक 13 अगस्त, 2021 के आदेश में निर्धारित तंत्र का संशोधन।	
3	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (एच) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के विनियम 31 के अधीन, विद्युत प्रणाली पर जोखिमों को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय करके, मौसमी विविधताओं के कारण उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण अवधि के दौरान विद्युत प्रणाली के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय एकीकृत संचालन की योजना बनाना, जिसमें विद्युत की मांग तेजी से बढ़ जाती है।	07.10.2024
4	विद्युत बाजार विनियम, 2021 के विनियम 27(1) के अनुसार आयोग द्वारा विद्युत एक्सचेंजों को निर्देश।	13.08.2024
5	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 8 के अधीन नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ का निर्धारण।	02.08.2024
6	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 के अधीन पंजीकृत विद्युत एक्सचेंजों को आयोग द्वारा निर्देश।	23.05.2024
7	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन न करना। एस्सार इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	03.04.2024
8	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2023 के विनियम 30 के खंड (2) और (3) के अधीन विद्युत प्रणाली पर जोखिम को कम करने के उपाय।	29.03.2025
9	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के विनियम 31 के अधीन, विद्युत प्रणाली पर जोखिमों को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय करके, मौसमी बदलावों के कारण उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण अवधि के दौरान विद्युत प्रणाली के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय एकीकृत संचालन की योजना बनाना, जिसमें विद्युत की मांग तेजी से बढ़ती है। राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र।	03.03.2025
10	डीएसएम विनियम, 2024 के अनुसरण में विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) पूल खाते में विरासत बकाया की वसूली – के संबंध में।	08.01.2025
11	आयातित कोयले के लिए छह-मासिक वृद्धि दरों से मासिक वृद्धि दरों में परिवर्तन के लिए कार्यप्रणाली।	02.01.2025

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
1	खवड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। खवड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.12.2024
2	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 सहपठित धारा 79 के अधीन याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा 'कर्नाटक में तुमकुर-II आरईजेड के एकीकरण हेतु पारेषण योजना' के कार्यान्वयन हेतु सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा देय पारेषण शुल्क को अपनाने की मांग की गई है। तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.12.2024
3	भड़ला-III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। भड़ला-III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.12.2024
4	खवड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण शुल्क अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। खवड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.12.2024
5	ब्यावर – मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन।	19.12.2024

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
	ब्यावर – मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
6	राजस्थान IVसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। राजस्थान IVसीपावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.12.2024
7	राजस्थान IVए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। राजस्थान IVए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.12.2024
8	राजस्थान IVई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। राजस्थान IVई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.12.2024
9	दिनांक 13.2.2021 के आशय पत्र और 17.12.2020 के बोली दस्तावेज के साथ पठित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(च) के अधीन याचिका, जिसके द्वारा इस आयोग से प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ताओं पर कथित निश्चित क्षति के आरोप में उठाए गए गलत मुआवजा बिलों/कर चालानों को रद्द करने और उक्त प्रतिवादी को ऐसे निश्चित क्षति पर आईजीएसटी लगाने, लागू विलंब भुगतान अधिभार के साथ अवैध रूप से रोके गए भुगतान और अन्य परिणामी राहतों के साथ रोकने के निर्देश की मांग की गई है। 1. जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, 2. टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	25.11.2024
10	खवड़ा IV– ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशतपूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। खवड़ा IV– ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.11.2024
11	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित पवन सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं (ट्रेंच-VII) के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11.11.2024
12	भारत में कहीं भी 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए हाइब्रिड पावर जनरेटरों के चयन के संबंध में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका (एनटीपीसी-ट्रेंच-V) बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) आधार पर। एनटीपीसी लिमिटेड	01.11.2024
13	सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड	25.10.2024
14	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28.7.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी 1500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं (ट्रेंच XIII) के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25.10.2024
15	भारत में कहीं भी टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अधीन 1500 मेगावाट आईएसटीएस से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (सौर-1) की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित टैरिफ अंगीकृत करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। एसजेवीएन लिमिटेड	25.10.2024
16	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.07.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी 1500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं (ट्रेंच XIV) के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15.10.2024
17	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से	03.10.2024

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
	जुड़ी और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 26.7.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 1175 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं (ट्रेंच-XVI) के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	
18	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.07.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा अनुवर्ती संचार/अधिसूचनाओं के माध्यम से व्याख्यायित और आशोधित किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड	23.09.2024
19	विद्युत मंत्रालय के दिनांक 03.08.2017 के मानक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 05.03.2019 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (ट्रेंच-III) के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़े 1000 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) पावर स्टेशनों के लिए उपयोग शुल्क अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। एनएचपीसी लिमिटेड	04.09.2024
20	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र विस्तार योजना-XVI (एनईआरईएस-XVI) के लिए ट्रांसमिशन योजना के विकास और संचालन के संबंध में टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अनुसरण में खोजे गए ट्रांसमिशन टैरिफ को अपनाने की मांग वाली याचिका। एनईआरईएस-गुटपावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21.08.2024
21	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित की जा रही है महाराष्ट्र के कल्लम क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र नेटवर्क विस्तार योजना के ट्रांसमिशन शुल्क को अपनाने की मांग की गई है। कल्लम ट्रांसको लिमिटेड	09.08.2024
22	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.8.2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण शक्ति के साथ बंडलिंग के माध्यम से ताप/जल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन और समय-निर्धारण सुगम बनाने हेतु योजना के अधीन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अधीन भारत में 100 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु पवन ऊर्जा डेवलपर्स के चयन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	01.08.2024
23	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.8.2022 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण शक्ति के साथ बंडलिंग के माध्यम से तापीय/जल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन और समय-निर्धारण सुगम बनाने हेतु योजना के अधीन भारत में आईएसटीएस-कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से 1200 मेगावाट विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। एनटीपीसी लिमिटेड	01.08.2024
24	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, 1500 मेगावाट तक की अतिरिक्त क्षमता के 'ग्रीनशू विकल्प' के साथ बिल्ड-ओन ऑपरेट (बीओओ) आधार पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ आईएसटीएस-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं से 1500 मेगावाट की फर्म और डिस्पैचेबल बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। एसजेवीएन लिमिटेड	01.08.2024
25	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.8.2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएसटीएस-संबद्ध पवन सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं से 1080 मेगावाट विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका। एनटीपीसी लिमिटेड	24.07.2024
26	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) सहपठित धारा 79(1)(ट) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के अधीन याचिका, जिसमें निर्धारित चालू करने की तिथि के विस्तार और किसी भी प्रकार के बलपूर्वक उपाय पर रोक लगाने के संबंध में उचित राहत की मांग की गई है। खंडूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.07.2024

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
27	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित 'धुले 2 गीगावाट आरईजेड से विद्युत निकासी हेतु पारेषण योजना' के पारेषण शुल्क को अपनाने की मांग की गई है। धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.07.2024
28	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, बीबीएमबी अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 18 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटो वोल्टेइक (पीवी) परियोजना की संचयी क्षमता के लिए दिनांक 3.8.2017 के मानक बोली दिशानिर्देशों और उनके संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुसार टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	10.07.2024
29	कोप्पल II xMxII ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वाधीन/अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। कोप्पल IIxMxII ट्रांसमिशन लिमिटेड	09.07.2024
30	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता की परियोजना के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 (ऋणदाता के लाभ के लिए कार्यरत सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में) के पक्ष में याचिकाकर्ता की सभी परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित के निर्माण हेतु अनुमोदन की मांग की गई है। खावड़ा II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.06.2024
31	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित 'पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना XXXIII (WRES&XXXIII): भाग सी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम' के ट्रांसमिशन शुल्क को अपनाने की मांग की गई है। ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	04.06.2024
32	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (ट्रेंच-XII) के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	01.06.2024
33	सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.05.2024
34	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (ग) और (घ) सहित धारा 79 के साथ पठित धारा 63 के अधीन याचिका, जिसमें मध्य प्रदेश के राजगढ़ (1000 मेगावाट) एसईजेड-चरण II में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा देय ट्रांसमिशन शुल्क को अपनाने की मांग की गई है। पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.05.2024
35	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशतपूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.05.2024
36	हल्वाद ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। हल्वाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.05.2024
37	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशतपूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए आवेदन। बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.05.2024
38	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 3.8.2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (ट्रेंच-XI) के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका, जिसमें बाद में संशोधन/स्पष्टीकरण भी शामिल है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	13.05.2024

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
39	करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.04.2024
40	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 690 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं (ट्रेंच-XIV) के टैरिफ को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 08.12.2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार अंगीकृत करने के लिए याचिका। ये दिशानिर्देश समय-समय पर संशोधित किए गए हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनुवर्ती संचार/अधिसूचनाओं के माध्यम से व्याख्या कर संशोधित किए गए हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25.04.2024
41	नीमराना II कोटपूतली ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण शुल्क अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। नीमराना II कोटपूतली ट्रांसमिशन लिमिटेड	03.04.2024
42	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21.08.2023 के दिशानिर्देशों, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी 1000 मेगावाट पवन, सौर, हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। एनटीपीसी लिमिटेड	24.03.2025
43	बीकानेर ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। पावरग्रिड बीकानेर प्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.03.2025
44	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28.7.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अधीन भारत में कहीं भी 1200 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (सोलर-2) की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। एसजेवीएन लिमिटेड	20.03.2025
45	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28.07.2023 को जारी दिशा-निर्देशों और उसके संशोधनों के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 3000 मेगावाट की आईएसटीएस ग्रिड-कनेक्टेड सौर फोटो वोल्टेइक परियोजनाओं के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। एनएचपीसी लिमिटेड	20.03.2025
46	खावड़ा पीएस1 और 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। खावड़ा पीएस1 और 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.03.2025
47	बाड़मेर ८ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। बाड़मेर ८ ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.03.2025
48	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 26.7.2023 के दिशानिर्देशों, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भारत में 600 मेगावाट आईएसटीएस-संबद्ध पवन ऊर्जा परियोजनाओं (पवन-1) की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। एसजेवीएन लिमिटेड	18.03.2025
49	इंदिरा सागर पावर स्टेशन (आईएसपीएस) के संबंध में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान उत्पादन केंद्र के नियंत्रण से परे कारणों से वार्षिक स्थिर लागत के पचास प्रतिशत की तुलना में ऊर्जा प्रभार में कमी की वसूली के लिए सीईआरसी (शुल्क की निबंधन व शर्त) विनियम, 2019 के विनियम 44 (7) और (8) के अधीन आवेदन। एनएचडीसी लिमिटेड	18.03.2025

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
50	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (घ) के साथ पठित धारा 62, और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15 (1) (ए) और विनियम 23 के साथ पठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढीकरण योजना (पूर्व में ताला अनुपूरक योजना) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन संयुक्त परिसंपत्ति के लिए 2019-24 के लिए पारेषण शुल्क के सही निर्धारण और 2024-29 की शुल्क अवधि के लिए पारेषण शुल्क के निर्धारण का अनुमोदन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	18.03.2025
51	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु सौर दिशानिर्देशों, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 28.07.2023 और उसके संशोधनों के अनुसार, 1500 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। एनटीपीसी लिमिटेड	18.03.2025
52	खावड़ा वी-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। खावड़ा वी-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.03.2025
53	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 के अधीन, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबंधित मामले), विनियम, 2020 के विनियम 20(3) के साथ पठित, अंतर-राज्यीय व्यापार लाइसेंस के निरसन हेतु आवेदन। ईकेआई पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	16.03.2025
54	याचिकाकर्ता, एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.08.2023 को जारी 'ग्रिड से जुड़ी पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश के अधीन अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी पवन-सौर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं से 1500 मेगावाट की खरीद के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए वर्तमान याचिका दाखिल की है। एनटीपीसी लिमिटेड	13.03.2025
55	जाम खंभालिया ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। पावरग्रिड जाम खंभालिया ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.03.2025
56	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन 600 मेगावाट/1200 मेगावाट ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) के साथ 1200 मेगावाट अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अपनाने और भारत सरकार के सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (एसईसीआई-आईएसटीएस-XV) के माध्यम से चयन करने के लिए याचिका।	06.03.2025
57	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आईएसटीएस से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं (एसईसीआई-एफडीआई-IV) से 630 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल पावर के लिए टैरिफ अपनाने और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 09.06.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।	03.03.2025
58	पावरग्रिड कुरावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती राजस्थान प्टएच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। पावरग्रिड कुरावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05.03.2025
59	बीकानेर बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। बीकानेर बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05.03.2025
60	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी और भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 14.10.2020 के	24.02.2025

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
	दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित, सुनिश्चित अधिकतम विद्युत आपूर्ति (ट्रेंच-VI) वाली 1200 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका। ये दिशानिर्देश समय-समय पर संशोधित किए गए हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनुवर्ती संचार/अधिसूचनाओं के माध्यम से व्याख्या कर संशोधन किए गए हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	
61	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 9.6.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 3000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। एनटीपीसी लिमिटेड	24.02.2025
62	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79 (1)(च) के अधीन याचिका, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1/टीएएनजीईडीसीओ के बीच निष्पादित दिनांक 10.12.2013 के परिशिष्ट के साथ पठित दिनांक 23.08.2013 के विद्युत क्रय अनुबंध के अनुच्छेद(अनुच्छेदों) 3.1, 3.4.3, 4.7 और 9 के दाखिले में आने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के कारण निर्धारित डिलीवरी तिथि के विस्तार का दावा करने के लिए। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	24.02.2025
63	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन 1200 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं (ट्रांच-VIII) के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका, जो अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी हैं और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	18.02.2025
64	जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.01.2025
65	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 3.8.2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिसमें बाद में संशोधन/स्पष्टीकरण भी शामिल है, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी 900 मेगावाट सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (ट्रेंच-XI) के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	31.01.2025
66	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा धारा 79(1)(ट) के साथ पठित के धारा 63के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को लागू विनियमों के अनुसार पूरा करने हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अधीन ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं से 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की दीर्घकालिक खरीद हेतु टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खोजा गया है। सीईएससी लिमिटेड	31.01.2025
67	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.7. 2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी 450 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं (ट्रेंच XVI) के टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	31.01.2025
68	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन 1990 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) पावर स्टेशन (ट्रेंच-III) के लिए उपयोग शुल्क अंगीकृत करने के लिए याचिका, जो अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ा है और जिसका चयन विद्युत मंत्रालय के दिनांक 03.08.2017 के मानक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 05.03.2019 को केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम योजना चरण-II के अधीन एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। 1. एनटीपीसी लिमिटेड, 2. एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	22.01.2025
69	नवीनल ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क को अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। नवीनल ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.01.2025

क्र.सं.	आदेश (अंगीकरण)	जारी करने/निपटान की तारीख
70	भड़ला-III और बीकानेर-III ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में ट्रांसमिशन शुल्क अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन। पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.01.2025
71	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ-आधारित वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली (ईएसएस-I) प्रक्रिया के अधीन भारत में 500 मेगावाट/1000 मेगावाट घंटे की स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की पायलट परियोजनाओं के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	02.01.2025

क्र.सं.	आदेश (विधि)	जारी करने/निपटान की तारीख
1	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और (च) के अधीन दिनांक 2.2.2007 के विद्युत क्रय करार और दिनांक 5.12.2018 के पूरक विद्युत क्रय करार के अनुसार अड़ानी पावर लिमिटेड के कानून में परिवर्तन संबंधी दावों और परिणामी राहतों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु याचिका। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	30.12.2024
2	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन विद्युत (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 के नियम 3 और हरियाणा डिस्कॉम के साथ दिनांक 7.8.2008 (बाद में समय-समय पर संशोधित) के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 और टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ दिनांक 20.01.2009 (बाद में समय-समय पर संशोधित) के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ याचिका, कानून में बदलाव की घोषणा और हरियाणा में स्थित झज्जर पावर लिमिटेड की 1,320 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में वृद्धि के कारण परिणामी राहत की मांग करती है। झज्जर पावर लिमिटेड	18.11.2024
3	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच निष्पादित पीपीए के अनुच्छेद 12.4 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका, डीवीसी और एनवीवीएन के बीच 6.9.2018 के पीएएस के अनुसरण में डीवीसी के साथ बैंक-टू-बैंक आधार पर डीवीसी के उत्पादन स्टेशनों से बीपीडीबी को 300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए हुई। दामोदर घाटी निगम	14.11.2024
4	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 और 79 के अधीन, दिनांक 31.8.2015 के पारेषण सेवा करार की अप्रत्याशित घटना (अनुच्छेद 11) और विधि परिवर्तन (अनुच्छेद 12) के अधीन राहत के लिए याचिका, जो वेमागिरी से आगे पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। पावरग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	17.10.2024
5	डीवीसी और एमपीपीएमसीएल दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बीच दिनांक 14.5.2007 के पीपीए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन से 100 मेगावाट बिजली के एकतरफा आत्मसमर्पण के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका	03.10.2024
6	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 79(1)(च) के अधीन 2 ग 500 एमवीए, 400/220 केवी दरभंगा सब-स्टेशन और ट्रिपल स्नोबर्ड के साथ मुजफ्फरपुर-दरभंगा 400 केवी डी/सी लाइन के 31.03.2017 से 15.04.2017 तक माने गए वाणिज्यिक संचालन की तारीख से माने गए ट्रांसमिशन शुल्क की वसूली के लिए याचिका, जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अधीन स्थापित 'पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-ट' का हिस्सा है, जो बिहार राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित 220 केवी डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण वसूल नहीं हो पाई। दरभंगा-मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	30.09.2024
7	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका जिसमें सौर सेल और मॉड्यूल के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने के कारण कानूनी घटनाओं में बदलाव के वित्तीयध्वावसायिक प्रभाव की भरपाई के लिए उचित समायोजन/मुआवजा प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र की मांग की गई है। रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड	02.08.2024

8	भारत सरकार की शक्ति नीति के अधीन कोयला लिंकेज आवंटन के कारण, टैरिफ में छूट और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पीपीए में संशोधन के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका। केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	15.07.2024
9	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, धारा 63 और धारा 79 के अधीन, वैधानिक ढाँचे और दिनांक 27.12.2016 को एनईआर- II ट्रांसमिशन लिमिटेड और उसके दीर्घकालिक ट्रांसमिशन ग्राहकों के बीच हुए ट्रांसमिशन सेवा करार के अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 12 के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ कानून में बदलावों के कारण मुआवजे का दावा करने और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण परियोजना के संबंधित तत्वों की निर्धारित कमीशनिंग तिथि में विस्तार की मांग करने हेतु याचिका। एनईआर- II ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.05.2024
10	ट्रांसमिशन सेवा करार दिनांक 23.4.2019 के अनुच्छेद 11, 12 और 16 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिकाजिसमें परियोजना के सीओडी को प्राप्त करने के लिए समय अवधि के विस्तार और अप्रत्याशित घटना और कानून की घटनाओं में बदलाव के कारण मुआवजे और अन्य परिणामी राहता के साथ सीईआरसी शेयरिंग विनियम, 2020 के विनियम 13(12) के संदर्भ में, प्रतिवादी संख्या 1 से द्विपक्षीय आधार पर, 4.9.2021 से 3.10.2021 तक ट्रांसमिशन टैरिफ/शुल्क की वसूली से संबंधित है। बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.05.2024
11	ट्रांसमिशन ग्राहकों के बीच हुए ट्रांसमिशन सेवा करार दिनांक 4.3.2016 के अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 और 79 (1)(च) के अधीन वैधानिक ढाँचे और को गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड और उसके दीर्घकालिक, कानून में बदलाव के कारण मुआवजे और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण परियोजना के संबंधित तत्वों की निर्धारित कमीशनिंग तिथि में विस्तार की मांग के लिए याचिका। गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.05.2024
12	याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच दिनांक 18.11.2019 को हुए विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और (ट) के अधीन याचिका जिसमें कानून में बदलाव, जैसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि, और उसके परिणामस्वरूप राहत प्रदान करने की मांग की गई है। अयाना रिन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड	19.05.2024
13	दिनांक 21.01.2020 को 300 मेगावाट आईएसटीएस से जुड़ी पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजना के विकास के लिए याचिकाकर्ताओं और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुए विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12.2 और अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका, जिसमें कानून में बदलाव के कारण हुए अतिरिक्त व्यय के लिए राहत की मांग की गई है। अडाणी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर थ्री लिमिटेड	19.05.2024
14	अधिसूचना संख्या 8/2021- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से माल और सेवा कर की दर 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ने के कारण कानून की घटनाओं में बदलाव के वित्तीय/व्यावसायिक प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए उचित समायोजन/मुआवजे की मांग के लिए, मेसर्स ऑस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राइवेट लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 30.10.2019 के पावर परचेज एग्रीमेंट के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	19.05.2024
15	(i) 'कानून में बदलाव' के अनुमोदनय और (ii) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2021 - एकीकृत कर (दर) दिनांक 30.09.2021 के प्रख्यापन के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए परिणामी राहत हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के साथ पठित धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका जो मेगा सूर्य ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 31.05.2020 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों (सौर सेल और मॉड्यूल सहित) पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में वृद्धि से संबंधित है। मेगा सूर्य ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	19.05.2024
16	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के साथ पठित धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच दिनांक 18.12.2013 और 19.12.2013 को हुए विद्युत क्रय करार से संबंधित 'कानून में परिवर्तन की स्थिति' के कारण मुआवजे की मांग की गई है। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड	19.05.2024
17	याचिकाकर्ता तथा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.03.2021 को निष्पादित विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 और अनुच्छेद 12 के अधीन	19.05.2024

	याचिका, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर की दर बढ़ाने और मूल सीमा शुल्क लगाने संबंधी कानून में बदलाव के कारण राहत की मांग की गई है। राइजिंग सन एनर्जी (के) प्राइवेट लिमिटेड	
18	दिनांक 10.01.2018 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 11, 12 और 16 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग), 79(1)(घ), 79(1)(च) और 79(1)(के) के अधीन याचिका में परियोजना के सीओडी की घोषणा, समयावधि में विस्तार, अप्रत्याशित घटना और कानूनी घटनाओं में बदलाव के कारण मुआवजा, और अन्य परिणामी राहत की मांग की गई है। फतेहगढ़-भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.05.2024
19	दिनांक 28.06.2018 को संपन्न विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 11 और 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन, याचिकाकर्ता और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच परियोजना की एससीडी से 12 महीने से अधिक की देरी के कारण अप्रत्याशित घटनाओं के कारण पीपीए को समाप्त करने के लिए याचिका। अडानी विंड एनर्जी कच्छ वन लिमिटेड	12.05.2024
20	कुछ घटनाओं को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में घोषित करने और अल्ट्रा जेर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 31.08.2020 को निष्पादित विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में प्रतिपूर्ति के साथ-साथ वहन लागत और वहन लागत पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिएमाननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीनयाचिका। अल्ट्रा जेर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड	11.05.2024
21	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीनयाचिका जिसमें याचिकाकर्ताओं और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में एम.के. रंजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक वाली रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.04.2021 के आदेश, जिसके अधीन कुछ निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार ग्रेट-इंडियन बस्टर्ड के प्राथमिकता वाले और संभावित आवासों में सभी मौजूदा और भविष्य की ओवरहेड कम और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों को अनिवार्य रूप से भूमिगत बिछाया जाना आवश्यक है, के कारण कानून में परिवर्तन के वित्तीय/व्यावसायिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए उचित समायोजन/मुआवजे की मांग की गई है। मेसर्स एज्योर पावर मेपल प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एज्योर पावर फोर्टी वन प्राइवेट लिमिटेड	03.05.2024
22	विद्युत अधिनियम, 2003 की 79(1)(ख), 79(1)(च) और 79(1)(ट) सहित धारा 79 के अधीन याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के साथ दिनांक 16.09.2021 को किए गए विद्युत क्रय करार (पीपीए) को बिना किसी वित्तीय दायित्व और उसके परिणाम के समाप्त करने की मांग की गई है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी सेवन लिमिटेड	01.05.2024
23	31 दिसंबर 2019 को अडानी सोलर एनर्जी जैसलमेर वन प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले एसबीई रिन्यूएबल्स टेन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच 450 मेगावाट आईएसटीएस से जुड़ी पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजना के विकास के लिए हुए विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12.2 के साथ पठितविद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन,याचिका दाखिल की गई है। इसमें कानून में बदलाव और वहन लागत सहित मुआवजा देने की मांग की गई है। अडानी सोलर एनर्जी जैसलमेर वन प्राइवेट लिमिटेड	01.05.2024
24	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका, जिसमें सौर सेल और मॉड्यूल के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने के कारण कानूनी घटनाओं में बदलाव के वित्तीय/व्यावसायिक प्रभाव की भरपाई हेतु उचित समायोजन/मुआवजा प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र की मांग की गई है। रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड। आदेश तिथि:- 02.08.2024	30.04.2024
25	एनटीपीसी लिमिटेड और तेलंगाना राज्य वितरण कंपनी लिमिटेड के बीच निष्पादित विद्युत उपयोग समझौतों के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (क) के अधीन याचिका, सीपीएसयू योजना चरण-५ किश्त ५ के अधीन 20 मेगावाट गांधार और 56 मेगावाट कवास सौर पीवी पावर परियोजनाओं के संबंध में कानून में बदलाव की घटना के बराबर माल और सेवा कर की दर में बदलाव के कारण लागत में वृद्धि के कारण मुआवजे की मांग की गई है, जिनकी कुल परियोजना क्षमता 76 मेगावाट है और टैरिफ को सीईआरसी द्वारा याचिका संख्या 174/एटी/2021 में दिनांक 13.12.2021 के आदेश के माध्यम से अपनाया गया था।	29.04.2024

26	दिनांक 25.06.2019 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(बी), धारा 79(1)(एफ) और धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका, इस माननीय आयोग से उचित आदेशनिर्देशधोषणा जारी करने की मांग करती है कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2/2020-सीमा शुल्क (एसजी) दिनांक 29.07.2020 के अनुसार सौर कोशिकाओं के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाना, चाहे मॉड्यूल या पैनलों में असंबल किया गया हो या नहीं, कानून में बदलाव की घटना है और इस माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या536/एमपी/2020 में दिनांक 20.08.2021 के अपने आदेश के अनुसार तय की गई कार्यप्रणाली के अनुरूप वर्तमान याचिका के साथ प्रस्तुत मुआवजे की मात्रा और तंत्र (ब्याज सहित) के अनुमोदन की मांग की गई है। मेसर्स ईडन रिन्यूएबल साइट प्राइवेट लिमिटेड	16.04.2024
27	रिट याचिका संख्या 200910/2024, बसप्पा उर्फ चंद्रशेखर और 4 अन्य द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय, कलबुर्गी बेंच के समक्ष दाखिल की गई।	12.04.2024
28	याचिकाकर्ता और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 07.10.2022 को संपन्न हुए पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 12.3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका जिसमें खंडूखाल और रामपुरा के लिए सर्किल रेट में वृद्धि के आधार पर निर्माण लागत में वृद्धि के कारण कानून में परिवर्तन के अनुमोदन की मांग की गई है। खंडूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	05.04.2024
29	पूर्वी क्षेत्र में 765 केवी सुदृढीकरण (ईआरएसएस-XVIII) से संबंधित दिनांक 17.11.2016 के पारेषण सेवा करार की अप्रत्याशित घटना (अनुच्छेद 11) और विधि परिवर्तन (अनुच्छेद 12) के अधीन राहत के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 और 79 के साथ पठित के अधीन याचिका। पावरग्रिड मेदिनीपुर-जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.03.2025
30	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुँच) विनियम, 2022 के लागू प्रावधानों और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 65-68 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79 के अधीन, कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में गडग ८ सबस्टेशन पर याचिकाकर्ता को दी गई 160 मेगावाट कनेक्टिविटी के संबंध में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध राहत की मांग की गई है। मेसर्स हलवद रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	27.03.2025
31	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(च) के अधीन याचिका, इस आयोग द्वारा याचिका संख्या 193/एटी/2024 में दिनांक 2.8.2024 के आदेश द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अनुसरण में दाखिल की गई, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि (प) याचिकाकर्ता की दिनांक 17.9.2023 की बोली 30.6.2024 को समाप्त हो गई है और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ पीपीए निष्पादित करने की अपेक्षा नहीं है, और (पप) प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता द्वारा बयाना राशि के रूप में जमा की गई बैंक गारंटी वापस करने के निर्देश दिए जाएं। मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	24.03.2025
32	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ट) के साथ पठित धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका, याचिकाकर्ता और पीटीसी के बीच दिनांक 01.11.2013 को निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध (पीटीसी-पीपीए) के दाखिले में और पीटीसी द्वारा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) के साथ निष्पादित बैक-टू-बैक विद्युत क्रय करार (जिसे दिनांक 01.11.2013 को क्रेता पीपीए कहा गया है) की शर्तों के अनुसार, भारतीय विद्युत व्यापार निगम के माध्यम से राजस्थान डिस्कॉम को आपूर्ति की गई विद्युत के लिए पीओसी शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु बकाया राशि के भुगतान के लिए। मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड	24.03.2025
33	परिशिष्ट संख्या 1 दिनांक 20.12.2013 के साथ पठित केस-1 दीर्घकालिक विद्युत क्रय अनुबंध दिनांक 27.11.2013 के अनुच्छेद 14.3.1 के साथ पठितविद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और धारा 79(1)(च) के अधीनयाचिका जिसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गलत तरीके से काटी गई राशि को लागू वहन लागत के साथ वापस करने की मांग की गई है, जो धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर के ताड़ाली में स्थित अपने 2 ग 300 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन की यूनिट 2 से 100 मेगावाट अनुबंधित क्षमता की आपूर्ति के लिए देय शकानून में बदलाव मुआवजे के लिए है। धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	22.03.2025

34	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 65 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन इस आयोग के न्यायिक, सामान्य विनियामक और अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, प्रतिवादियों के विरुद्ध घाटे का भुगतान जारी करने और इस आयोग द्वारा याचिका संख्या 72/MP/2020 में दिनांक 30.06.2023 के आदेश के अधीन अनुमत विधिक क्षतिपूर्ति में परिवर्तन के लिए विलंब भुगतान अधिभार के लिए निर्देश प्राप्त करने हेतु याचिका। अजानी सोलर एनर्जी जोधपुर (चार) प्राइवेट लिमिटेड	23.03.2025
35	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड और टैजेटको के बीच परिचालन अवधि के दौरान दिनांक 27.11.2013 को हुए पीपीए के प्रावधानों के अनुसार 'कानून में बदलाव' से उत्पन्न मुआवजे और परिणामी राहतों के दावों के न्यायनिर्णयन हेतु याचिका – अपील संख्या 77/2019 में दिनांक 11.10.2022 का एपीटीईएल निर्णय। मेसर्स केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	22.03.2025
36	79 पीपीए के अनुच्छेद 13 और 17 दिनांक 22.4.2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा के अधीन याचिका जिसमें निर्माण अवधि के दौरान कानूनी घटनाओं में बदलाव के कारण मुंद्रा यूएमपीपी की पूंजीगत लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप टैरिफ में वृद्धि की मांग की गई है – याचिका संख्या 141/एमपी/2016 में आयोग के दिनांक 31.8.2017 के आदेश के विरुद्ध अपील संख्या 385/2017] 383/2017] 401/2017, 404/2017 और 40/2018 में एपीटीईएल के दिनांक 25.10.2024 के फैसले का कार्यान्वयन। सीजीपीएल	12.03.2025
37	सीईआरसी (व्यावसायिक संहिता) विनियम, 1999 के विनियम 111 और दिनांक 08.12.2021 के पीपीए के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और (च) के अधीन, कानून में बदलाव के अनुमोदन और कानून में बदलाव के कारण मुआवजे की मात्रा और तंत्र के निर्धारण के लिए याचिका। मेसर्स टी.पी. सौर्य लिमिटेड	20.02.2025
38	दिनांक 29.01.2019 को सीताक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच संपन्न विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका, जिसमें कानून में बदलाव के कारण टैरिफ में क्षतिपूर्ति संशोधन की मांग की गई है। सीताक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड	19.02.2025
39	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2023 के अध्याय 2 और दिनांक 25.11.2021 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और (च) के अधीन, याचिका जिसमें अधिसूचना संख्या 88/2021- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12% करने के कारण कानूनी घटनाओं में हुए बदलाव के वित्तीय व्यावसायिक प्रभाव की भरपाई के लिए उचित समायोजन/मुआवजा और उसके परिणामस्वरूप राहत प्रदान करने की मांग की गई है। मेसर्स बीमपाउ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	29.01.2025
40	याचिकाकर्ता और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बीच निष्पादित दिनांक 7.8.2008 (संशोधन करार दिनांक 17.9.2008 और 27.5.2022 के अनुसार संशोधित) के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका साथ ही, याचिकाकर्ता और टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के बीच दिनांक 20.1.2009 (संशोधन करार दिनांक 21.10.2010 द्वारा संशोधित) के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 17, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधिनियमन के कारण कानून में परिवर्तन की स्वीकृति और परियोजना के संचालन और रखरखाव के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा वहन लागत सहित किए गए अतिरिक्त व्यय के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। झज्जर पावर लिमिटेड	22.01.2025

41	'कानून में परिवर्तन' की घटना 'कानून में परिवर्तन' अर्थात, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2021 को जारी अधिसूचना संख्या 8/2021- केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की दर 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ने के वित्तीय/व्यावसायिक प्रभाव के कारण सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ निष्पादित विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में कानून में परिवर्तन के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका मेसर्स मोरजर विंडफार्म डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	03.01.2025
----	--	------------

2) आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	विनियम 3/2024- एपीईआरसी ग्रीन एनर्जी खुली पहुंच चार्जस और बैंकिंग विनियम 2024	01.05.2024
2	विनियम 2024/5+ टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली विनियम 2024 के अधीन अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विकास के लिए एपीईआरसी सीमा	16.05.2024
3	विनियम 2024/4: एपीईआरसीपारेषण लाइसेंस विनियम 2024	17.05.2024
4	विनियम संख्या 2024/6: एपीईआरसी (लाइसेंसधारियों का कार्य निष्पादन मानक) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2024	28.08.2024
5	विनियम 2024/7: एपीईआरसी मांग पक्ष प्रबंधन विनियम 2024	25.11.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	ओ.पी. संख्या 1/2024-एचएनपीसीएल के लिए टैरिफ निर्धारण के विषय में	02.04.2024
2	ओपी संख्या 3/2024 -एसईसीआई, एपीडीआईएसकॉम और गोएपी के बीच 25 वर्षों के लिए 17000 एमयू की वार्षिक अधिकतम मात्रा के साथ 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के संबंध में दिनांक 01.12.2021 के त्रिपक्षीय बिजली बिक्री करार के अनुमोदन के विषय में	12.04.2024
3	ओपी संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25 और 26/2019- उक्त 21 पीपीए के संबंध में टैरिफ के निर्धारण की मांग के विषय में	19.04.2024
4	ओपी.सं. 46/2017 में आरपी संख्या 2/2021- ओपी संख्या 46/2017 में आयोग के दिनांक 22.10.2020 के आदेश की समीक्षा की मांग के विषय में	18.06.2024
5	ओ.पी. संख्या 33/2019 और 35/2018 (भाग) में आरपी संख्या 3/2021 - आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) - आरटीपीपी-IV के संशोधित और पुनः घोषित पीपीए को सहमति देने के विषय में 2019 के ओ.पी. संख्या 33 और वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आरटीपीपी-IV के टैरिफ के निर्धारण के संदर्भ में ओ.पी. संख्या 35/2018 (भाग) में आयोग के आदेश दिनांक 31.12.2020 की समीक्षा की मांग के विषय में	18.06.2024
6	वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए एमवाईटी ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश	06.08.2024
7	5वीं नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के लिए एसएलडीसी शुल्क पर एमवाईटी आदेश	27.08.2024
8	01.04.2024 से 31.03.2029 तक परिवर्तनीय लागत वाले मौजूदा बायोमास, औद्योगिक अपशिष्ट और खोई आधारित संयंत्रों के निर्धारण के लिए 2024 का स्वतः संज्ञान आदेश संख्या 01	05.09.2024
9	5वीं नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के लिए एपी जेनको का एमवाईटी आदेश	09.09.2024
10	आरपीपीओ/आरईसी के अधीन बिजली खरीद की संयुक्त लागत का निर्धारण	26.09.2024
11	वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 5वीं नियंत्रण अवधि के लिए व्हीलिंग व्यवसाय के	27.09.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	लिए एमवाईटी आदेश	
12	ओ.पी. संख्या 16/2024 – खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र से 6.25 मेगावाट विद्युत की खरीद के लिए दिनांक 15.03.2024 के निरंतरता करार के अनुमोदन के विषय में	01.10.2024
13	ओ.पी. संख्या 58/2023 – जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (गुंटूर) लिमिटेड द्वारा मौजूदा बिजली संयंत्र से एपीडिस्कॉम्स को दिनांक 06.02.2016 के विद्युत क्रय करार के अधीन अतिरिक्त 5 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा क्षमता से उत्पन्न बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण के विषय में	06.10.2024
14	ओ.पी. संख्या 28/2024 – एपीट्रांसको द्वारा एचटी एससी संख्या एसकेएल-139 और यूनिट एचटी एससी संख्या एसकेएल-423 पर लगाए गए लाइन और बे रखरखाव शुल्क के दावे के विवाद के विषय में	14.10.2024
15	ओ.पी. संख्या 28/2024 – एपीट्रांसको द्वारा एचटी एससी संख्या एसकेएल-139 और यूनिट एचटी एससी संख्या एसकेएल-423 पर लगाए गए लाइन और बे रखरखाव शुल्क के दावे के बारे में विवाद के विषय में	14.10.2024
16	वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन एफपीपीसीए के विषय में सामान्य आदेश	25.10.2024
17	ओ.पी.सं. 21/2024 – 5वीं नियंत्रण अवधि 2024-2029 के लिए 2*800 मेगावाट स्टेज-I एसडीएसटीपीएस के लिए अतिरिक्त पूंजीगत लागत और टैरिफ के निर्धारण और 4वीं नियंत्रण अवधि 2019-2024 में 10.03.2023 के सीओडी से 31.03.2024 तक 1*800 मेगावाट स्टेज-II एसडीएसटीपीएस के लिए पूंजीगत लागत और टैरिफ के निर्धारण के विषय में, और 5वीं नियंत्रण अवधि 2024-2029 के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एपीपीडीसीएल) द्वारा आंध्र प्रदेश में वितरण लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की गई बिजली के लिए और पीपीए के अनुमोदन के विषय में	28.10.2024
18	डिस्कॉम और एपी जेनको के बीच पूंजीगत लागत और टैरिफ का निर्धारण (डॉ. एनटीपीपीएस-वी)	28.10.2024
19	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एफपीपीसीए टू-अप के विषय में सामान्य आदेश	29.11.2024
20	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क और क्रॉस सब्सिडी अधिभार पर जारी आदेश	20.02.2025

3) अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसी की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया) विनियम, 2024	07.05.2024
2	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारी के लिए प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2024	07.05.2024
3	1. अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल विनियम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024 2. अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए) के लिए निबंधन और शर्तें और शुल्क की गणना के लिए पद्धति) (पहला संशोधन) विनियम, 2024	16.05.2024
4	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2024	16.05.2024
5	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा) विनियम, 2024	16.05.2024
6	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 (द्वितीय संशोधन)	27.06.2024
7	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024।	03.07.2024
8	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2024	03.07.2024

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
9	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024	10.12.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	एपीडीओपी याचिका संख्या टीपी-01/2024 के संबंध में 21-02-2024 को पारित टू अप आदेश की समीक्षा के लिए शुद्धिपत्र।	05.04.2024
2	बिजली विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और मेसर्स कांगटेंग हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय करारके अनुमोदन के लिए याचिका।	12.06.2024
3	मेसर्स देवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच पीपीए के पहले संशोधन के लिए याचिका।	13.06.2024
4	वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश, विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के संबंध में याचिका संख्या टीपी-03/2024 में आदेश दिनांक 26.07.2024	26.07.2024
5	एपीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम 2024, विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के विनियम 3.6.4(10) के अनुपालन में 150 किलोवाट भार तक विद्युतीकृत क्षेत्रों में नए सेवा कनेक्शन शुल्क के अनुमोदन के लिए हेतु आवेदन।	26.07.2024
6	याचिका संख्या एमपी-06/2024 में दिनांक 26.07.2024 का आदेश जिसमें ऐथर अलॉयज एलएलपी द्वारा नई विद्युत संयोजन हेतु जनहित एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुरक्षा जमा से संबंधित आपूर्ति संहिता के अनुबंध 10.10 के साथ पठित विनियम 3.21.4(1) में छूट देने की मांग की गई है।	26.07.2024
7	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ से निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम 7 के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक मेगावाट तक की लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ के निर्धारण के संबंध में याचिका संख्या टीपी-09/2024 में आदेश दिनांक 23.08.2024	23.08.2024
8	याचिका संख्या एमपी-07/2024 में दिनांक 08.10.2024 का आदेश जिसमें ऐथर अलॉयज एलएलपी, बिजली विभाग, अरुणाचल प्रदेश और उद्योग विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नई विद्युत संयोजन हेतु जनहित एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुरक्षा जमा से संबंधित आपूर्ति संहिता के अनुबंध 10.10 के साथ पठित विनियम 3.21.4(1) में छूट देने की मांग की गई है।	08.10.2024
9	बिजली विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और मेसर्स हलाईपानी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच ड्राफ्ट पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के अनुमोदन के लिए याचिका के संबंध में याचिका संख्या एमपी-08/2024 में आदेश दिनांक 25.10.2024	25.10.2024
10	बिजली विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और मेसर्स श्री सालासर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच बिजली बिक्री करार (पीएसए) के अनुमोदन के लिए याचिका के संबंध में याचिका संख्या एमपी-09/2024 में आदेश दिनांक 26.11.2024	26.11.2024
11	एचपीडीसीएपीएल द्वारा दाखिल सुंबाचू एसएचपी 3 मेगावाट, जेमिथांग के लिए पूंजीगत लागत और टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी 08/2024 के संबंध में आदेश दिनांक 16.12.2024	16.12.2024
12	डीएचपीडी द्वारा दाखिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा और टैरिफ आदेश के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी-11/2024 के संबंध में आदेश दिनांक 31.12.2024	31.12.2024
13	डीएचपीडी द्वारा दाखिल एंगोंग नाला एमएचएस 4.5 मेगावाट के लिए पूंजीगत लागत और स्तरीकृत टैरिफ के अनुमोदन के लिए 2024 की याचिका संख्या टीपी 12/2024 के संबंध में आदेश दिनांक 31.12.2024	31.12.2024
14	डीएचपीडी द्वारा दाखिल नूराणांग पीएच-ए एसएचपी 1 मेगावाट के लिए पूंजीगत लागत और स्तरीकृत टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी 13/2024 के संबंध में आदेश दिनांक 31.12.2024	31.12.2024
15	डीएचपीडी द्वारा दाखिल कोलोरियांग 1 मेगावाट में पेयू एमएचएस के लिए पूंजीगत लागत और स्तरीकृत	31.12.2024

	टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी 14 / 2024 के संबंध में आदेश दिनांक 31.12.2024	
16	डीएचपीडी द्वारा दाखिल खजालोग एमएचएस 1.5 मेगावाट के लिए पूंजीगत लागत और स्तरीकृत टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी 15 / 2024 के संबंध में आदेश दिनांक 31.12.2024	31.12.2024
17	डीएचपीडी द्वारा दाखिल मुक्तो एसएचपी 6 मेगावाट के लिए पूंजीगत लागत और स्तरीकृत टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी 16 / 2024 के संबंध में आदेश दिनांक 31.12.2024	31.12.2024
18	डीएचपीडी द्वारा दाखिल सबबंग एसएचपी 3 मेगावाट के लिए पूंजीगत लागत और स्तरीकृत टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी 17 / 2024 के संबंध में आदेश दिनांक 31.12.2024	31.12.2024
19	देवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एपीआर और ट्रांसमिशन शुल्क के लिए याचिका संख्या टीपी 07 / 2024 पर आदेश	04.03.2025
20	7-5 मेगावाट (3 ग 2.5 मेगावाट) खांगटेंग एचईपी 7-5 मेगावाट के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका संख्या टीपी-10 / 2024 पर आदेश	07.03.2025
21	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर और टैरिफ के अनुमोदन के साथ-साथ एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए बिजनेस प्लान और एआरआर के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या टीपी 01 / 2024 पर आदेश। एवं याचिका सं. एमपी-10 / 2025 पर आदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2024 के विनियम 3.6.4(10) के अनुपालन में 150 किलोवाट भार तक विद्युतीकृत क्षेत्रों में नए सेवा कनेक्शन शुल्क के अनुमोदन के संबंध में याचिका सं. एमपी-04 / 2024 पर माननीय आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2024 की समीक्षा करनेका अनुरोध किया गया है।	26.03.2025

4) असम विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	असम विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर पीवी सिस्टम) विनियम, 2019, (पहला संशोधन), 2024	29.06.2024
2	असम विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (सप्तम संशोधन) विनियम, 2024	05.11.2024
3	असम विद्युत विनियामक आयोग (फीस आदि का भुगतान) विनियम, 2024	29.11.2024
4	एईआरसी (खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2024	04.12.2024
5	असम विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024।	18.12.2024
6	असम विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024	18.12.2024
7	असम विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर पीवी सिस्टम) विनियम, 2019, (द्वितीय संशोधन), 2024	18.12.2024
8	असम विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) दिशानिर्देश, 2024	19.12.2024
9	असम विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2024	31.12.2024
10	असम विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा), विनियम 2024	21.01.2025
11	असम विद्युत विनियामक आयोग (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की खरीद और प्रेषण) दिशानिर्देश, 2024	21.01.2025
12	असम विद्युत विनियामक आयोग (मांग प्रतिक्रिया) विनियम, 2024	21.01.2025
13	असम विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2024	24.03.2025
14	असम विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2010, (चतुर्थ संशोधन), 2024	24.03.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गयेमहत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित समग्र राजस्व अपेक्षा के अनुमोदन के लिए एपीडीसीएल द्वारा छाखिल आदेश	27.06.2024
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित समग्र राजस्व अपेक्षा के अनुमोदन के लिए एपीजीसीएल द्वारा दाखिल आदेश	27.06.2024
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित समग्र राजस्व अपेक्षा के अनुमोदन के लिए एईजीसीएल द्वारा दाखिल आदेश	27.06.2024
4	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित समग्र राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एसएलडीसी शुल्क के अनुमोदन के लिए एसएलडीसी द्वारा दाखिल आदेश	27.06.2024
5	अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि ('एससीओडी') के विस्तार के लिए माननीय आयोग के अनुमोदन के लिए माहेश्वरी माइनिंग एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिलयाचिका संख्या 04/2024 पर सुनवाई आदेश	11.07.2024
6	12 जनवरी 2022 को आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए सीमा सीमा में वृद्धि से संबंधित याचिका संख्या 03/2024 पर सुनवाई आदेश	11.07.2024
7	असम राज्य में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के ग्रिड-कनेक्टेड कैप्टिव पावर प्लांट से असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) को 12 मेगावाट बिजली की बिक्री के लिए मध्यम अवधि के विद्युत क्रय करार (पीपीए) और टैरिफ के अनुमोदन के लिए मेसर्स ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) द्वारा दाखिल याचिका संख्या 02/2024 का आदेश	02.08.2024
8	सेवा कनेक्शन शुल्क के सरलीकरण की मांग करते हुए असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) द्वारा दाखिल विविध याचिका संख्या 07/2024 पर सुनवाई आदेश	12.08.2024
9	याचिका संख्या 08/2022 के विरुद्ध एमएसएचईपी आदेश दिनांक 16/05/2024 की समीक्षा के लिए एपीजीसीएल द्वारा दाखिल याचिका संख्या 06/2024 पर आदेश	31.08.2024
10	याचिका संख्या 05/2024 - विविध याचिका के संबंध में सुनवाई आदेश, जो अमगुरी सोलर प्लांट स्थित 220 केवी स्विचिंग सबस्टेशन में स्थित 3 (तीन) संख्या बे की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु अनुमोदन तथा परिसंपत्तियों का स्वामित्व एईजीसीएल को हस्तांतरित होने के उपरांत संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क के दावा करने हेतु दिशा-निर्देशों से संबंधित है जो कि मेसर्स जैकसन पावर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वाधीन है।	02.09.2024
11	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) द्वारा दाखिल विविध याचिका संख्या 08/2024 पर आदेश, जिसमें असम विद्युत विनियामक आयोग (ईधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन) विनियम, 2024 के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त आदेश की मांग की गई है।	17.09.2024
12	असम राज्य में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के ग्रिड-कनेक्टेड कैप्टिव पावर प्लांट से असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) को 12 मेगावाट बिजली की बिक्री के लिए मध्यम अवधि के विद्युत क्रय करार (पीपीए) और टैरिफ के अनुमोदन के लिए मेसर्स ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) द्वारा दाखिल याचिका संख्या 02/2024 के लिए सुनवाई आदेश।	30.09.2024
13	असम राज्य में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के ग्रिड-कनेक्टेड कैप्टिव पावर प्लांट से असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) को 12 मेगावाट बिजली की बिक्री के लिए मध्यम अवधि के विद्युत क्रय करार (पीपीए) और टैरिफ के अनुमोदन के लिए मेसर्स ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) द्वारा दाखिल याचिका संख्या 02/2024 पर सुनवाई आदेश	28.10.2024
14	एलटीपीएस संयंत्र के लिए फॉल बैक आधार पर 0.10 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति के लिए एजीसीएल के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिए एपीजीसीएल द्वारा दाखिलयाचिका संख्या 11/2024 पर आदेश	06.11.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
15	डेवलपर मोड के अधीन एनटीपीसी से 100 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड बिजली की खरीद के लिए मंजूरी की मांग करने वाली एपीडीसीएल द्वारा दाखिल याचिका संख्या 12/2024 पर सुनवाई आदेश।	09.12.2024
16	एपीडीसीएल द्वारा विकसित किए जाने वाले 15 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट के आरएफएस, पीपीए और सीलिंग टैरिफ के अनुमोदन के लिए एपीडीसीएल द्वारा दाखिल याचिका संख्या 14/2024 पर सुनवाई आदेश	09.12.2024
17	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 के साथ पठित धारा 86 के अधीन एपीडीसीएल द्वारा दाखिल याचिका संख्या 16/2024 पर सुनवाई आदेश, जिसमें टीएचडीसीआईएल द्वारा शुरू की गई 1200 मेगावाट कलाई ५ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना से 200 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए टैरिफ अपनाने और एईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 के संदर्भ में बिजली बिक्री करार के मसौदे के अनुमोदन की मांग की गई है।	09.12.2024
18	असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एईजीसीएल) के पत्र क्रमांक एईजीसीएल/एमडी/सीजीएम (ओ एंड एम, यूएआर)/टीएसके-रुपाई टीएल/2023/8 दिनांक 19.10.2024 को एईजीसीएल की आकस्मिकता निधि का उपयोग करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन हेतु में सुनवाई का आदेश।	09.02.2025
19	आईजीसी, बालीपारा, शोणितपुर जिला, असम में एसईआईपीएल के 5 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लांट से एपीडीसीएल को बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए एपीडीसीएल द्वारा दाखिल याचिका संख्या 03/2017 पर सुनवाई आदेश	14.02.2025
20	असम विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच के निबंधन और शर्तें) विनियम 2018 और असम विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान और संबंधित मामले) विनियम 2019 के उल्लंघन में 'राज्य संस्थाओं द्वारा विचलन ऊर्जा लेखांकन और विचलन के लिए शुल्क की गणना' के लिए विस्तृत संचालन प्रक्रिया को लागू करने के लिए मेसर्स इमामी लिमिटेड द्वारा असम राज्य लोड डिस्पैच सेंटर से राहत की मांग करते हुए और असम विद्युत विनियामक आयोग (मुक्त पहुंच के निबंधन और शर्तें) विनियम 2018 और असम विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान और संबंधित मामले) विनियम 2019 के उल्लंघन में विचलन निपटान तंत्र के अधीन दिनांक 26.11.2024 के ड्राफ्ट चालान जारी करने के लिए और अंतरिम राहत के लिए मेसर्स इमामी लिमिटेड द्वारा दाखिलयाचिका एवं आईए सं 25/2024 पर सुनवाई का आदेश	19.02.2025
21	स्टार सीमेंट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका एवं आईए संख्या 13/2024 पर सुनवाई आदेश – (प) असम राज्य लोड प्रेषण केंद्र द्वारा 'राज्य संस्थाओं के लिए विचलन ऊर्जा लेखांकन एवं विचलन शुल्क की गणना' हेतु विस्तृत संचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन में, असम विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2018 तथा असम विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान एवं संबंधित विषय) विनियम, 2019 के उल्लंघन के विरुद्ध राहत की मांग तथा(पप) विचलन निपटान तंत्र (क्वअपजंपवद 'मजजसमउमदज डमबींदपेउ) के अधीन ड्राफ्ट चालान जारी करने में, असम विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2018 तथा असम विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान एवं संबंधित विषय) विनियम, 2019 के उल्लंघन के विरुद्ध राहत की मांग।	24.01.2025

5. बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (नेट और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सोलर ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018	24.07.2024
2	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय ट्रांसमिशन टैरिफ और एसएलडीसी शुल्क) विनियम, 2024	04.11.2024
3	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2024	29.11.2024
4	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच) विनियम, 2024	23.12.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	बिहार राज्य के रजौली, जिला-नवादा में स्थित फुलवारी बांध के जलाशय पर दीर्घकालिक आधार पर आरईएससीओ मोड के अधीन स्थापित किए जाने वाले ग्रिड से जुड़े 10 मेगावाट (एसी) फ्लोटिंग सौर पीवी बिजली परियोजना से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ अपनाने और ड्राफ्ट पीपीए के अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता, बीएसपीजीसीएल द्वारा दाखिल याचिका।	04.04.2024
2	सेंट्रल जेनरेटिंग स्टेशन से 30.03.2024 से 30.09.2024 तक ईआरपीसी पत्र संख्या -1797 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित 177 मेगावाट बिजली की खरीद पर मंजूरी के लिए मुख्य अभियंता (पीएमसी) बीएसपीएचसीएल द्वारा दाखिलयाचिका	04.04.2024
3	मामला संख्या 11/2019 दिनांक 22.11.2021 में लोकपाल द्वारा पारित आदेश के कारण कार्यवाही शुरू करने के लिए श्री फुलमन सिंह द्वारा दाखिल याचिका	28.05.2024
4	श्रीमती द्वारा सरस्वती बम्वाल को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन कार्यवाही शुरू करने के लिए दाखिल याचिका	28.05.2024
5	बीएसपीएचसीएल के मुख्य अभियंता (पीएमसी) द्वारा दाखिल याचिका जिसमें 15.06.2024 से 31.10.2024 की अवधि के दौरान नेपाल के हाइड्रो पावर स्टेशनों से दोनों डिस्कॉम (एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल) की ओर से बीएसपी (एच)सीएल द्वारा तीन (03) वर्षों के लिए आरटीसी आधार पर 209 मेगावाट हाइड्रो पावर की खरीद के लिए अनुमोदन मांगा गया है, जिसे व्यापारी मेसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ड्राफ्ट पीएसए के अनुमोदनके साथ 5.45रु/किलोवाट प्लस 5 पैसे/किलोवाट का ट्रेडिंग मार्जिन के टैरिफ पर पांच (05) वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।	13.06.2024
6	विद्युत अधिनियम, 2003 प्रासंगिक दिशानिर्देशों के साथ पठितबीईआरसी (मल्टी ईयर ट्रांसमिशन टैरिफ और एसएलडीसी शुल्क) विनियम, 2021, बीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2005 और बीईआरसी (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय की आय का उपचार) विनियम, 2013 के अधीन बीजीसीएल के ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के फाइबर को पट्टे पर देने के अनुमोदन के लिए बीजीसीएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक (संचालन/अनुरक्षण/वाणि.), बीजीसीएल द्वारा दाखिल याचिका	09.07.2024
7	01.07.2024 से 30.06.2025 तक एक वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के एमओपी द्वारा आवंटित फरक्का-I और II एसटीपीएस से बिहार राज्य को 302.36 मेगावाट बिजली की खरीद के अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता (विद्युत) बीएसएचपीसीएल द्वारा दाखिल याचिका	10.07.2024
8	मामला संख्या 19/2023 और 18/2023 में आयोग द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 05.01.2024 की समीक्षा के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 और बीईआरसी (कारबार का प्रचालन) विनियम, 2005 के विनियम 31 के साथ पठितविद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन मेसर्स न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स और मेसर्स भारत शुगर मिल्स द्वारा दाखिल समीक्षा याचिका	05.08.2024
9	वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के आरपीओ की उपलब्धि में शेष आरपीओ की कमी को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मांगने के विषय में बीईआरसी के समक्ष दोनों डिस्कॉम यानी एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल की ओर से मुख्य अभियंता (कॉमल), एसबीपीडीसीएल द्वारा दाखिलयाचिका	03.09.2024
10	मेसर्स हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ता के खोई-आधारित सह-उत्पादन संयंत्र से याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी वितरण लाइसेंसधारियों को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए देय टैरिफ के निश्चित शुल्क घटकों के निर्धारण के लिए पीपीए के अनुच्छेद 2.1 और 01.06.2010 के साथ पठित,विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(ठ),(क), (ख) और (ग), धारा 62(ठ)(क) और धारा 64 के अधीनदाखिल याचिका	05.09.2024
11	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 6(3), 12, 31, 36, 37, 38 और 39 उसमें जारी संशोधनों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) और 94(2) के अधीन मुख्य अभियंता (वाणिज्य), एनबीपीडीसीएल/एसबीपीडीसीएल द्वारा दाखिल याचिका जिसमें 01 मार्च 2024 को आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश,वित्तीय वर्ष-2022-23 की सत्यता, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (एपीआर), वार्षिक राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के टैरिफ का निर्धारण की समीक्षा मांग की गई है।	30.09.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
12	वित्तीय वर्ष 2010-11, वित्तीय वर्ष 2011-12, वित्तीय वर्ष 2012-13, वित्तीय वर्ष 2013-14, वित्तीय वर्ष 2014-15, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए टू-अप टैरिफ याचिका और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर के निर्धारण के लिए मुख्य अभियंता (विद्युत) बीएसपीएचपीसीएल द्वारा दाखिल याचिका	01.10.2024
13	बिजली बिक्री करार सहित दीर्घकालिक आधार पर आईएसटीएस कनेक्टेड सोलर ट्रेच-प योजना के अधीन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) से 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता (पीएमसी), बीएसपीएचसीएल द्वारा दाखिल याचिका।	23.10.2024
14	बीईआरसी के विनियम 10.2.8 (लाइसेंस की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया) विनियम, 2018 और बीईआरसी (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन विनियम 2010 और इसके संशोधन) के साथ पठित ईए, 2003 की धारा 63 और 86 (ठ) (ख) के अधीन बिहार राज्य में दीर्घकालिक आधार (यानी 25 वर्ष) पर स्थापित किए जाने वाले ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों से 112.07 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ अपनाने और ड्राफ्ट पीपीए के अनुमोदन के लिए बीएसपीजीसीएल के मुख्य अभियंता द्वारा दाखिल याचिका	23.10.2024
15	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य स्तरीकृत टैरिफ का निर्धारण	05.11.2024
16	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा (45) और (46), बिजली (उपभोक्ता का अधिकार), नियम, 2020 की धारा (36) और (39) बीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2005 और इसके आगे के संशोधन और बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 का 4.19 (ख) और एसबीपीडीसीएल और एनबीपीडीसीएल की ओर से इसके आगे के संशोधन के साथ विनियम 4.4 और के नियम 04 के (13) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए 'सेवा कनेक्शन शुल्क का निर्धारण' के लिए एसबीपीडीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) द्वारा दाखिल याचिका	10.12.2024
17	बीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 20 के साथ पठित विद्युत मंत्रालय, विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के विनियम 14 के अनुसरण में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 86 के अधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएस) के टू-अप के अनुमोदन के लिए एनबीपीडीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) द्वारा दाखिल याचिका	16.12.2024
18	पावर सेल एग्रीमेंट (पीएसए) सहित दीर्घकालिक आधार पर आईएसटीएस से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं के अधीन एसजेवीएन लिमिटेड से कुल 170 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए विनियामक अनुमोदन की मांग के लिए मुख्य अभियंता (पीएमसी), बीएसपीएचसीएल द्वारा दाखिल याचिका।	23.01.2025
19	मुख्य अभियंता (पीएमसी), बीएसपीएचसीएल द्वारा बिजली बिक्री करार (पीएसए) सहित दीर्घकालिक आधार पर ट्रेच गटप्प के अधीन आईएसटीएस से जुड़े पवन ऊर्जा परियोजनाओं के अधीन एसईसीआई लिमिटेड से कुल 100 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए विनियामक मंजूरी मांगने के लिए दाखिल याचिका	23.01.2025
20	बीईएससी, 2007 के 12.6 और बीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 39 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 में उपयुक्त संशोधन करके और स्मार्ट मीटरिंग रोल की सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.03.2024 के टैरिफ आदेश में उपयुक्त संशोधन करके एकल चरण एलटी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए पावर फैक्टर सरचार्ज को 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए स्थगित करने, वास्तविक मांग के विषय में उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर उपभोक्ता द्वारा चुनी गई मांग से परे जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए जुर्माना प्रावधान में छूट देने के लिए डिस्कॉम द्वारा दाखिल याचिका।	17.02.2025
21	बीजीसीएल के लिए जारी किए गए 'बीईआरसी (कारबार का संचालन) विनियम, 2005 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा और ट्रांसमिशन शुल्क' के लिए मामला सं. 26/2023 के अधीन टैरिफ आदेश के लिए वरिष्ठ महाप्रबंधक (संचालन एवं अनुरक्षण)/वाणिज्यिक., बीजीसीएल द्वारा दाखिल समीक्षा याचिका।	25.02.2025
22	मुख्य अभियंता, (पीएमसी) बीएसपीएचसीएल द्वारा एमओपी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसटीसी के राष्ट्रीय ई-बोली पोर्टल (डीईईपी पोर्टल) का उपयोग करके टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से 1.7.2025 से 30.9.2025 की अवधि के लिए बिहार डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक अधिकतम खपत के समय पर बिजली की खरीद पर विनियामक अनुमोदन की मांग के लिए दाखिल याचिका।	20.03.2025
23	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश और एनबीपीडीसीएल की वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28	28.03.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	की नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना	
24	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश और एसबीपीडीसीएल की वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना	28.03.2025
25	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश और एसएलडीसी की वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना	28.03.2025
26	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश और बीजीसीएल की वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना	28.03.2025
27	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश और बीएसपीटीसीएल की वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना	28.03.2025

6. छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली के लिए उत्पादन टैरिफ और संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	28.06.2024
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (चतुर्थ संशोधन) 2024	08.08.2024
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत वितरण में कार्य निष्पादन के मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	30.08.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	याचिका संख्या: 13/2024 याचिकाकर्ता: सीएसपीडीसीएल विषय: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड की आंतरिक संचालन प्रक्रिया के 'विद्युत भार प्रबंधन प्रक्रिया' में संशोधन के लिए अनुमोदन मांगने हेतु याचिका।	12.04.2024
2	याचिका संख्या:101/2023 याचिकाकर्ता: जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड विषय: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 और 86 (1) (ए) के अधीन लाइसेंस प्राप्त वितरण व्यवसाय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रू-अप के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा का निर्धारण।	10.05.2024
3	स्वतः संज्ञान याचिका संख्या:18/2023 विषय: इंद्रा-स्टेट स्तर पर पूलिंग सबस्टेशनों से जुड़े सौर, पवन, सौर-पवन हाइब्रिड उत्पादन स्टेशनों के पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग के लिए विस्तृत संचालन प्रक्रिया।	29.05.2024
4	याचिका संख्या: 05/2024 याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड विषय:वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर ट्रांसमिशन टैरिफ के प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक राजस्व अपेक्षा की अंतिम सत्यता।	01.06.2024
5	याचिका संख्या: 06/2024 याचिकाकर्ता:छत्तीसगढ़ राज्य लोड डिस्पैच सेंटर विषय:वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एआरआर के अंतिम ट्रू-अप और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एसएलडीसी शुल्क के निर्धारण के लिए याचिका।	01.06.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
6	याचिका संख्या: 09/2024 याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम टू-अप के अनुमोदन के लिए याचिका, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर का पुनरु निर्धारण, मौजूदा टैरिफ पर राजस्व का प्रक्षेपण और राजस्व अंतर के साथ शुल्क और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 64 के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण।	01.06.2024
7	याचिका संख्या:10/2024 याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पारंपरिक थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांटों के एआरआर को टू अप के लिए याचिका।	01.06.2024
8	स्वतः संज्ञान याचिका संख्या:34/2024 विषय: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित संयंत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य अधिमानी टैरिफ का निर्धारण	18.06.2024
9	याचिका संख्या:106/2023 याचिकाकर्ता: भिलाई इस्पात संयंत्र का टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप याचिका और बीएसपी टीईडी के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा बिजली आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण।	24.06.2024
10	स्वतः संज्ञान याचिका संख्या:35/2024 विषय: डीआरई विनियम 2019 में कठिनाइयों को दूर करना और आगामी आईडीआरईएस परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा बैंकिंग, लेखांकन, निपटान और व्हीलिंग के तौर-तरीकों से संबंधित इसके पश्चात के संशोधन (पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं या 27.12.2023 तक सीओडी हासिल करने वाली परियोजनाओं के अलावा, जो भी पहले हो)।	26.06.2024
11	याचिका संख्या:86/2023 याचिकाकर्ता: डी.बी. पावर लिमिटेड विषय: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क दर (परिवर्तनीय लागत) का निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऊर्जा शुल्क दर का निर्धारण	26.06.2024
12	याचिका संख्या:90/2023 याचिकाकर्ता:अडाणी पावर लिमिटेड विषय: अडाणी पावर लिमिटेड – रायगढ़ टीपीपी के 600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ए) के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क दरों का निर्धारण।	26.06.2024
13	याचिका संख्या:92/2023 याचिकाकर्ता:अडाणी पावर लिमिटेड विषय: अडाणी पावर लिमिटेड – रायपुर टीपीपी के 1370 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ए) के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क दरों का निर्धारण।	26.06.2024
14	याचिका संख्या:98/2023 याचिकाकर्ता: लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड विषय: 300 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट मेसर्स के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ए) के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क दर का निर्धारण। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, पाथडी, कोरबा, छत्तीसगढ़।	26.06.2024
15	स्वतः संज्ञान याचिका संख्या:61/2024 विषय: याचिका संख्या 70/2022 में पारित विविध एवं सामान्य शुल्क आदेश दिनांक 16.02.2022 में संशोधन।	20.09.2024

8. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम और लोकपाल की स्थापना के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2024	24.06.2024
2	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा) विनियम, 2024	25.07.2024
3	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग) (पहला संशोधन) विनियम, 2024	02.08.2024
4	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम और लोकपाल की स्थापना के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2024 के लिए शुद्धिपत्र	03.09.2024
5	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024	12.11.2024

8. गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 01.04.2025 को या उसके पश्चात पूंजीकृत संपत्तियों के लिए आरओसीई-आधारित रिटर्न तंत्र की शुरुआत। विनियमित दर आधार (आरआरबी) की शुरुआत। औसत आरआरबी के आधार पर रिटर्न की गणना जिसमें उपभोक्ता योगदान, अनुदान और संचित मूल्यहास शामिल नहीं है। - पूंजीगत व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूंजी निवेश अनुमोदन ढांचे की शुरुआत। - पूंजीकृत परिसंपत्तियों की अनिवार्य जियो-टैगिंग। एमवाईटी अनुमोदन के दौरान प्रमुख परिचालन मापदंडों के लिए प्रदर्शन प्रक्षेपवक्र की अपेक्षा। लाभ/हानि साझा करने के लिए संशोधित तंत्र। नियंत्रणीय कारकों से होने वाले लाभ को 2/3 उपभोक्ताओं के साथ साझा किया जाएगा और 1/3 लाइसेंसधारियों द्वारा रखा जाएगा। नुकसान पूरी तरह से लाइसेंसधारियों द्वारा वहन किया गया। - राष्ट्रीय नीतियों के साथ तालमेल। बिजली खरीद योजना को दीर्घकालिक डिस्कॉम संसाधन पर्याप्तता योजना और सीईए जांच के साथ जोड़ा जाएगा। एफपीपीएस को विद्युत नियम, 2022प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाएगा।	06.08.2024
2	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024	06.09.2024
3	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और संबंधित मामले) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024 - आयोग को लो टेंशन (एलटी) कनेक्शन के लिए सीमा सीमा को 100 केवीएडकेडब्ल्यू से बढ़ाकर 150 केवीए/केडब्ल्यू करने के लिए विभिन्न उपभोक्ता संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसे विद्युत आपूर्ति कोड समीक्षा पैनल को भेजा गया था। - इसके पश्चात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पहल के अधीन नए कनेक्शन जारी करने से जुड़े सुधारों को शुरू करने के लिए डिस्कॉम को सुविधा प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से संचार हुआ। - इसके परिणामस्वरूप, आयोग ने एलटी उपभोक्ताओं को अपने एलटी कनेक्शन की सीमा सीमा को 100 केवीए/केडब्ल्यू से बढ़ाकर 150 केवीए/केडब्ल्यू करने का विकल्प देकर जीईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और संबंधित मामले) विनियम, 2015 में संशोधन किया।	23.09.2024
4	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति और अन्य विविध शुल्क प्रदान करने में किए गए व्यय की	23.09.2024

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
	वसूली के लिए लाइसेंसधारक की शक्ति (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024	
5	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2024	23.09.2024
6	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025	28.03.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	गुजरात राज्य के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं से वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य लोगों द्वारा बिजली की खरीद के लिए टैरिफ ढांचा।	31.08.2024
2	गुजरात राज्य के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं से वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य द्वारा बिजली की खरीद के लिए टैरिफ ढांचा।	31.08.2024
3	त्फोरमचवपदजउमदज श्री पी.ए. वाघेला को 08/03/2025 से प्रभावी 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए विद्युत लोकपाल, अहमदाबाद के रूप में नियुक्त किया गया	05.03.2025
4	त्फोरमचवपदजउमदज श्री एस.एच. उपाध्याय को विद्युत लोकपाल, राजकोट के रूप में 08/03/2025 से प्रभावी 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया	05.03.2025
5	गुजरात राज्य के लिए बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं और खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं से वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य द्वारा बिजली की खरीद के लिए टैरिफ का निर्धारण।	21.03.2025
6	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	01.06.2024
7	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	01.06.2024
8	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	01.06.2024
9	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	01.06.2024
10	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और टॉरेंट पावर लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण – वितरण अहमदाबाद	01.06.2024
11	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और टॉरेंट पावर लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण – वितरण सूरत	01.06.2024
12	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूटिंग और टॉरेंट पावर लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण – वितरण दहेज	01.06.2024
13	एमपीएसईजेड यूटिलिटीज लिमिटेड (एमयूएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	01.06.2024
14	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड (गिफ्ट पीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	01.06.2024
15	एस्पेन पार्क इंफ्रा वडोदरा प्राइवेट लिमिटेड (एआईवीपीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रूइंग और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	01.06.2024
16	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ट्रूइंग और चौथी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30) के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण और दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण।	31.03.2025
17	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ट्रूइंग और चौथी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30) के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण और मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण।	31.03.2025
18	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ट्रूइंग और चौथी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष	31.03.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	2029-30) के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण और पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण।	
19	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टूइंग और चौथी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30) के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण।	31.03.2025
20	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सही, वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टोरेंट पावर लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण – वितरण अहमदाबाद	29.03.2025
21	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सही, वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टोरेंट पावर लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण – वितरण सूरत	29.03.2025
22	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टूइंग और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए बहु-वर्षीय एआरआर के अनुमोदन और टोरेंट पावर लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण – वितरण दहेज	29.03.2025
23	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू अप और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए बहु-वर्षीय एआरआर के अनुमोदन और एमपीएसईजेड यूटिलिटीज लिमिटेड (एमयूएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण	29.03.2025
24	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टूइंग, वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और एस्पेन पार्क इफ्रा वडोदरा प्राइवेट लिमिटेड (एआईवीपीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण	23.04.2025
25	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू अप और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए बहु-वर्षीय एआरआर के अनुमोदन और गिपट पावर कंपनी लिमिटेड (गिपट पीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ का निर्धारण	31.03.2025
26	वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) के लिए	31.03.2025
27	जुबिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जेआईएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ का निर्धारण	31.03.2025

9. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच) विनियम, 2023, (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025	25.02.2025
2	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा) विनियम, 2024	11.11.2024
3	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के अधीन उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024	22.10.2024
4	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टैरिफ और अन्य नियामक मुद्दों की स्थापना के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021, (पहला संशोधन) विनियम, 2024	19.07.2024
5	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (नेट मीटरिंग/ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सोलर ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2021, (पहला संशोधन) विनियम, 2024	15.07.2024
6	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (फोरम और लोकपाल विनियम, 2020 (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024	06.09.2024
7	इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टैरिफ और अन्य विनियामक मुद्दे स्थापित करने की शर्तें) विनियम, 2021, (पहला संशोधन) विनियम, 2024	01.08.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1.	यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के टू-अप, वित्तीय वर्ष 2025-29 के लिए व्यवसाय योजना, वित्तीय वर्ष 2025-29 के लिए कैपेक्स योजना, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्य-वर्ष प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 की कुल राजस्व अपेक्षा का निर्धारण	28.03.2025

10. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024	20.05.2024
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024	12.06.2024
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (छठा संशोधन) विनियम, 2024	05.08.2024
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अल्पकालिक खुली पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024	30.08.2024
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025	28.01.2025
6	हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति (षष्ठम संशोधन) संहिता, 2025	17.03.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनियंत्रित मापदंडों को सही करना, चौथे एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24) के अधीनवित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बेकाबू मापदंडों को अस्थायी रूप से सही करना, चौथे एमवाईटी नियंत्रण अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2020-24 के नियंत्रण योग्य मापदंडों को सही करना, 5वें एमवाईटी की पहली वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (एपीआर) नियंत्रण अवधि, कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) निर्धारित की गई और 5वीं एमवाईटी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29) के अधीनवित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एचपीएसईबीएल के वितरण व्यवसाय के लिए व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अनुमोदन दी गई।	28.03.2025

11. झारखण्ड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम और नेट ग्रॉस मीटरिंग) पांचवां संशोधन	04.12.2024
2	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (फीस, जुर्माना और शुल्क विनियम, 2024	25.11.2024
3	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2024	25.11.2024
4	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता के लिए रूपरेखा) विनियम, 2024	05.11.2024

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
5	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग) विनियम, 2024	23.09.2024
6	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024	27.08.2024
7	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम और नेटवर्क मीटरिंग) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024	29.05.2024
8	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव उपभोक्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2024	09.05.2024
9	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रुप नेट मीटरिंग एवं वर्चुअल नेट मीटरिंग) विनियम, 2024	09.05.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 (1) (च) और जेएसईआरसी (व्यवसाय का संचालन), विनियम 2016 के विनियम 41 के अधीनदाखिल याचिका जिसमें झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के पदापुर और श्रीरामपुर गांवों में एपीएनआरएल के 540 मेगावाट कोयला आधारित बिजली संयंत्र से जेयूवीएनएल/जेबीवीएनएल को विनियमित संविदात्मक क्षमता की आपूर्ति के लिए जेएसईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें), विनियम 2015 के प्रावधानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए टू-अप और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एपीआर के विषय में जेएसईआरसी द्वारा 22.05.2023 को पारित आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	16.04.2024
2	24000 केवीए की बढ़ी हुई संविदा मांग के साथ मौजूदा 33 केवी बिजली आपूर्ति प्राप्त करने/बनाए रखने के संबंध में	16.04.2024
3	झारखंड राज्य के क्षेत्र के भीतर दामोदर घाटी क्षेत्र के लिए बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए उपभोक्ता श्रेणीवार टैरिफ का निर्धारण।	30.04.2024
4	मेसर्स नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड के 49 (1237) एमवीए कैप्टिव पावर प्लांट को प्रतिवादियों के ग्रिड के साथ समन्वयित करने तथा याचिकाकर्ता के सीपीपी से जेबीवीएनएल को 12.5 मेगावाट अधिशेष बिजली की आपूर्ति के लिए पक्षों के बीच निष्पादित करार के प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में	30.04.2024
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जेएसईआरसी टैरिफ आदेश की समीक्षा, जेबीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ	29.05.2024
6	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विद्वान सी.जी.आर.एफ., रांची द्वारा मामला संख्या 04/08 में पारित दिनांक 22.04.2008 के आदेश का अनुपालन करें, जिसकी पुष्टि विद्युत लोकपाल द्वारा केस संख्या ई.ओ.जे. ६17६2008 में पारित दिनांक 30.08.2008 के आदेश द्वारा की गई है, तथा ब्याज सहित राशि को तत्काल वापस करें, जहां तक कुछ मामलों में राशि पहले ही के.वी.ए. प्रभारों के विरुद्ध राशि समायोजित करके जारी कर दी गई है।	29.05.2024
7	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर समयबद्ध निर्णय लें, जिसमें उसने गम्हरिया स्थित अपने इस्पात संयंत्र के लिए दिनांक 06.12.2022 के पत्र में निहित पूर्व सीपीपी व्यवस्था से एचटी औद्योगिक कनेक्शन की मांग की है, जो 01.07.2023 से प्रभावी होगा।	30.05.2024
8	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विद्वान सी.जी.आर.एफ., रांची द्वारा केस संख्या 04/08 में पारित दिनांक 22.04.2008 के आदेश का अनुपालन करें, जिसकी पुष्टि विद्युत लोकपाल द्वारा केस संख्या ई.ओ.जे. /17६2008 में पारित दिनांक 30.08.2008 के आदेश द्वारा की गई है, तथा ब्याज सहित राशि को तत्काल वापस करें, जहां तक कुछ मामलों में राशि पहले ही के.वी.ए. प्रभारों के विरुद्ध राशि समायोजित करके जारी कर दी गई है।	30.05.2024
9	प्रतिवादियों को निर्देश पर आदेश कि वे याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर समयबद्ध निर्णय लें, जिसमें उसने गम्हरिया स्थित अपने इस्पात संयंत्र के लिए दिनांक 06.12.2022 के पत्र में निहित पूर्व सीपीपी व्यवस्था से एचटी औद्योगिक कनेक्शन की मांग की है, जो 01.07.2023 से प्रभावी होगा।	30.05.2024
10	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विद्वान सी.जी.आर.एफ., रांची द्वारा केस संख्या 04६08 में पारित दिनांक 22.04.2008 के आदेश का अनुपालन करें, जिसकी पुष्टि विद्युत लोकपाल द्वारा केस संख्या ई.ओ.जे.६17६2008	28.06.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	में पारित दिनांक 30.08.2008 के आदेश द्वारा की गई है, तथा ब्याज सहित राशि को तत्काल वापस करें, जहां तक कुछ मामलों में राशि पहले ही के.वी.ए. प्रभारों के विरुद्ध राशि समायोजित करके जारी कर दी गई है।	
11	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर समयबद्ध निर्णय लें, जिसमें उसने गम्हरिया स्थित अपने इस्पात संयंत्र के लिए दिनांक 06.12.2022 के पत्र में निहित पूर्व सीपीपी व्यवस्था से एचटी औद्योगिक कनेक्शन की मांग की है, जो 01.07.2023 से प्रभावी होगा।	28.06.2024
12	2000 केवीए की संविदा मांग के लिए प्रतिवादी से 220 केवी लाइन पर ई.एच.टी. कनेक्शन लेने के लिए अनुमोदन के संबंध में	23.07.2024
13	झारखंड राज्य के क्षेत्र के भीतर दामोदर घाटी क्षेत्र के लिए बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए उपभोक्ता श्रेणीवार टैरिफ का निर्धारण।	23.07.2024
14	शुद्धिपत्र –झारखंड राज्य के क्षेत्र के भीतर दामोदर घाटी क्षेत्र के लिए बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए उपभोक्ता श्रेणीवार टैरिफ का निर्धारण।	23.07.2024
15	सीपीपी विनियम 2023 के खंड 8 के अनुसार बैंकिंग व्यवस्था के साथ 7.5 एमवीए की स्टैंडबाय संविदा मांग/समर्थन के साथ याचिकाकर्ता के ग्रिड के साथ मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन, रेहला के 60 (2 ग30) मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के समन्वय के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच निष्पादित किए जाने वाले मसौदा करार के अनुमोदन के संबंध में	01.08.2024
16	सीपीपी विनियम 2023 के खंड 8 के अनुसार बैंकिंग व्यवस्था के साथ 15 एमवीए की स्टैंडबाय अनुबंध मांग/समर्थन के साथ याचिकाकर्ता के ग्रिड के साथ मेसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड के (2 ग10) मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के समन्वय के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच निष्पादित किए जाने वाले मसौदा करार के अनुमोदन के संबंध में	01.08.2024
17	दोनों पक्षों के बीच निष्पादित किए जाने वाले सीपीपी करार के मसौदे का अनुमोदन	01.08.2024
18	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए 2023 के केस नंबर 08 में दिनांक 26/06/2024 के आदेश की समीक्षा	24.09.2024
19	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) के जोजोबेरा पावर प्लांट की यूनिट-2 और 3 (2 ग120 मेगावाट) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा के संबंध में दिनांक 09.01.2024 के आदेश की समीक्षा	01.08.2024
20	450 केवीए की अनुबंध मांग वाली जेबीवीएनएल से 33 केवी लाइन पर एच.टी. कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक अनुमोदन के संबंध में	24.09.2024
21	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू अप हेतु 2023 के मामले (टैरिफ) संख्या 09, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षाएं और टैरिफ के संबंध में इस आयोग द्वारा पारित दिनांक 26.06.2024 के आदेश की समीक्षा	01.08.2024
22	इस आयोग द्वारा 2020 के मामला संख्या 26 में पारित दिनांक 16.05.2023 के आदेश/निर्देश का अनुपालन न करना	24.09.2024
23	जेबीवीएनएल से 33 केवी लाइन पर 400 केवीए की अनुबंध मांग के साथ एच.टी. कनेक्शन लेने के अनुमोदन के संबंध में	08.10.2024
24	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) के जोजोबेरा पावर प्लांट की यूनिट 2 और 3 (2 ग120 मेगावाट) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एपीआर के लिए केस (टी) संख्या 11वीं 2023 में जेएसईआरसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2024 की समीक्षा	10.12.2024
25	100 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए सेल और एसईसीआई के बीच विद्युत बिक्री करार (पीएसए) का अनुमोदन, जिसे एसईसीआई द्वारा आईएसटीएस- कनेक्टेड ट्रैच-VIII से खरीदा जाएगा।	18.12.2024
26	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 (1) (च) और जेएसईआरसी (व्यवसाय का संचालन), विनियम 2016 के विनियम 41 के अधीनदाखिल याचिका जिसमें झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के पदापुर और श्रीरामपुर गांवों में एपीएनआरएल के 540 मेगावाट कोयला आधारित बिजली संयंत्र से जेयूवीएनएल/जेबीवीएनएल को विनियमित संविदात्मक क्षमता की आपूर्ति के लिए जेएसईआरसी (उत्पादन	20.12.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तों), विनियम 2015 के प्रावधानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए टू-अप और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एपीआर के विषय में जेएसईआरसी द्वारा 22.05.2023 को पारित आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	
27	24000 केवीए की बढ़ी हुई सविदा मांग के साथ मौजूदा 33 केवी बिजली आपूर्ति प्राप्त करने/बनाए रखने के संबंध में	20.12.2024
28	झारखंड राज्य के क्षेत्र के भीतर दामोदर घाटी क्षेत्र के लिए बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए उपभोक्ता श्रेणीवार टैरिफ का निर्धारण।	20.12.2024
29	मेसर्स नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड के 49 (1237) एमवीए कैप्टिव पावर प्लांट को प्रतिवादियों के ग्रिड के साथ समन्वयित करने तथा याचिकाकर्ता के सीपीपी से जेबीवीएनएल को 12.5 मेगावाट अधिशेष बिजली की आपूर्ति के लिए पक्षों के बीच निष्पादित करार के प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में	20.12.2024
30	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जेएसईआरसी टैरिफ आदेश की समीक्षा, जेबीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ	20.12.2024
31	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विद्वान सी.जी.आर.एफ., रांची द्वारा मामला संख्या 04/08 में पारित दिनांक 22.04.2008 के आदेश का अनुपालन करें, जिसकी पुष्टि विद्युत लोकपाल द्वारा केस संख्या ई.ओ.जे. ६17६2008 में पारित दिनांक 30.08.2008 के आदेश द्वारा की गई है, तथा ब्याज सहित राशि को तत्काल वापस करें, जहां तक कुछ मामलों में राशि पहले ही के.वी.ए. प्रभारों के विरुद्ध राशि समायोजित करके जारी कर दी गई है।	20.12.2024
32	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर समयबद्ध निर्णय लें, जिसमें उसने गम्हरिया स्थित अपने इस्पात संयंत्र के लिए दिनांक 06.12.2022 के पत्र में निहित पूर्व सीपीपी व्यवस्था से एचटी औद्योगिक कनेक्शन की मांग की है, जो 01.07.2023 से प्रभावी होगा।	20.12.2024
33	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विद्वान सी.जी.आर.एफ., रांची द्वारा केस संख्या 04/08 में पारित दिनांक 22.04.2008 के आदेश का अनुपालन करें, जिसकी पुष्टि विद्युत लोकपाल द्वारा केस संख्या ई.ओ.जे.६17६2008 में पारित दिनांक 30.08.2008 के आदेश द्वारा की गई है, तथा ब्याज सहित राशि को तत्काल वापस करें, जहां तक कुछ मामलों में राशि पहले ही के.वी.ए. प्रभारों के विरुद्ध राशि समायोजित करके जारी कर दी गई है।	24.01.2025
34	प्रतिवादियों को निर्देश पर आदेश कि वे याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर समयबद्ध निर्णय लें, जिसमें उसने गम्हरिया स्थित अपने इस्पात संयंत्र के लिए दिनांक 06.12.2022 के पत्र में निहित पूर्व सीपीपी व्यवस्था से एचटी औद्योगिक कनेक्शन की मांग की है, जो 01.07.2023 से प्रभावी होगा।	27.02.2025
35	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विद्वान सी.जी.आर.एफ., रांची द्वारा केस संख्या 04/08 में पारित दिनांक 22.04.2008 के आदेश का अनुपालन करें, जिसकी पुष्टि विद्युत लोकपाल द्वारा केस संख्या ई.ओ.जे.६17६2008 में पारित दिनांक 30.08.2008 के आदेश द्वारा की गई है, तथा ब्याज सहित राशि को तत्काल वापस करें, जहां तक कुछ मामलों में राशि पहले ही के.वी.ए. प्रभारों के विरुद्ध राशि समायोजित करके जारी कर दी गई है।	27.02.2025
36	प्रतिवादियों को निर्देश कि वे याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर समयबद्ध निर्णय लें, जिसमें उसने गम्हरिया स्थित अपने इस्पात संयंत्र के लिए दिनांक 06.12.2022 के पत्र में निहित पूर्व सीपीपी व्यवस्था से एचटी औद्योगिक कनेक्शन की मांग की है, जो 01.07.2023 से प्रभावी होगा।	27.02.2025

12. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं केंद्र शासित प्रदेश)

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए कार्य निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	27.05.2024
2	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2024	28.05.2024

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
3	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग और सकल मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी फ्रीड इंटरएक्टिव सिस्टम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	01.08.2024
4	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024	02.08.2024
5	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और खुली पहुँच) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024	13.08.2024
6	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2024	16.08.2024
7	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024	15.10.2024
8	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (निबंधन और शर्तों) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण हेतु) विनियम, 2024	24.10.2024
9	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2024	12.11.2024
10	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (खुदरा आपूर्ति टैरिफ संरचना) दिशानिर्देश, 2024	20.12.2024
11	गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाने वाली जाँच हेतु) विनियम, 2024	06.02.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर), वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा टैरिफ के निर्धारण हेतु अनुमोदन	10.06.2024
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा टैरिफ के निर्धारण हेतु अनुमोदन	12.06.2024
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा और टैरिफ के निर्धारण हेतु अनुमोदन	13.06.2024
4	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा शुल्क निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा शुल्क निर्धारण	13.06.2024
5	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा शुल्क निर्धारण का अनुमोदन	13.06.2024
6	वित्तीय वर्ष 2021-22 के टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर), समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा शुल्क निर्धारण का अनुमोदन	25.07.2024

13. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू कश्मीर और लद्दाख)

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और उससे संबंधित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	11.07.2024
2	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	24.07.2024
3	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तों) विनियम, 2024	19.12.2024
4	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक	18.02.2025

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
	आयोग (संसाधन पर्याप्तता हेतु रूपरेखा) विनियम, 2024	

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	लद्दाख विद्युत विकास विभाग (एलपीडीडी) के वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रतिशत (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक प्रतिशत (एआरआर) और टैरिफ निर्धारण का अनुमोदन।	27.06.2024
2	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेपीडीसीएल) द्वारा दाखिलवित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 की समग्र राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारण का अनुमोदन।	24.03.2025
3	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (केपीडीसीएल) द्वारा दाखिलवित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 की समग्र राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारण का अनुमोदन।	24.03.2025

14. कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) (दसवाँ संशोधन) विनियम, 2024	19.06.2024
2	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (योग्यता आदेश प्रेषण और विद्युत क्रय लागत का अनुकूलन) विनियम, 2024	24.06.2024
3	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय पारेषण, वितरण और खुदरा आपूर्ति शुल्क) विनियम, 2024	24.06.2024
4	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (पीयर-टू-पीयर सौर ऊर्जा लेनदेन का कार्यान्वयन), विनियम, 2024	06.08.2024
5	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024	09.09.2024
6	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता हेतु रूपरेखा) विनियम, 2024	23.09.2024
7	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क) विनियम, 2024	26.11.2024
8	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय पारेषण, वितरण और खुदरा आपूर्ति टैरिफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2024	10.12.2024
9	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (सौर ऊर्जा सहित या उसके बिना रूफटॉप एयरो टर्बाइन का कार्यान्वयन) विनियम, 2025	20.01.2025
10	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियम, 2025	21.01.2025
11	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2025	26.03.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सौर रूफटॉप फोटोवोल्टिक परियोजनाओं सहित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में टैरिफ और मानदंडों का निर्धारण।	11.06.2024
2	नियंत्रण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2027 के दौरान चालू किए गए मिनी-हाइड्रल, खोई आधारित सह-उत्पादन और बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न विद्युत के लिए सामान्य टैरिफ निर्धारण के विषय में।	24.07.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
3	ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इकाइयों की स्थापना हेतु प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।	30.07.2024
4	सौर रूफटॉप फोटोवोल्टिक (एसआरटीपीवी) के लिए पात्र उपभोक्ताओं के लिए नेट मीटरिंग व्यवस्था।	12.09.2024
5	एसआरटीपीवी उपभोक्ताओं के लिए 10 किलोवाट तक और उसके सहित स्वीकृत भार में वृद्धि और अन्य संबंधित मामले।	05.12.2024
6	टीबीसीबी के माध्यम से पारेषण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीमा।	24.12.2024
7	जनरेटर और संबंधित उपायों के लिए एएमआर सुविधाओं का कार्यान्वयन।	01.01.2025
8	एसआरटीपीवी संयंत्रों सहित कैप्टिव पावर प्लांटों पर ग्रिड समर्थन शुल्क न लगाना।	15.01.2025
9	एस्कॉम का संयुक्त टैरिफ आदेश 2025	27.03.2025

15. केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	केरल विद्युत आपूर्ति (पाँचवाँ संशोधन) संहिता, 2024	31.07.2024
2	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा और नेट मीटरिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024	16.08.2024
3	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (न्यायिक प्रक्रिया) विनियम, 2024	03.09.2024
4	केरल विद्युत आपूर्ति संहिता (कठिनाइयों का निवारण), आदेश 2024	25.11.2024
5	केरल विद्युत आपूर्ति संहिता (कठिनाइयों का निवारण), आदेश 2025	07.01.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

1	ओपी 78/2023 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स कानन देवन हिल्स प्लांटेशनस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (केडीएचपीसीएल)	13.06.2024
2	ओपी 85/2023 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच पर आदेश – केएसईबी लिमिटेड	28.06.2024
3	ओपी 80/2023 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सीएसईजेडए)	02.07.2024
4	ओपी 82/2023 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स इन्फोपार्क केरल	12.07.2024
5	ओपी 65/2023 – केएसईबी लिमिटेड की रणनीतिक व्यावसायिक इकाई-उत्पादन (एसबीयू-जी) की वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना के अनुमोदन पर आदेश।	21.10.2024
6	ओपी 79/2023 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स त्रिशूर कॉर्पोरेशन विद्युत विभाग (टीसीईडी)	04.11.2024
7	ओपी 10/2024 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन स्वतः संज्ञान कार्यवाही, एक कुशल, समन्वित और किफायती पारेषण एवं वितरण प्रणाली विकसित करने न करने परिणामस्वरूप विद्युत मंडल, तिरु-केएसईबी लिमिटेड के अधीन विद्युत आवंटन बड़ी संख्या में आवेदनलंबित	06.11.2024
8	ओपी संख्या 30/2024 और आईए संख्या 3६2024 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच पर आदेश – मेसर्स स्मार्ट सिटी	13.11.2024
9	ओपी 81/2023 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन हेतु याचिका पर आदेश – मेसर्स कोचीन पोर्ट अथॉरिटी	26.11.2024
10	ओपी 18/2023 – केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और अन्य सभी लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ अनुसूची और निबंधन व शर्तें 05.12.2024 से 31.03.2027 तक	05.12.2024
11	ओपी 77/2023 – वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों की जाँच पर आदेश – मेसर्स रबर पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरपीआईएल)	26.12.2024

12	ओपी 46/2024 – केएसईबी लिमिटेड द्वारा अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 की अवधि के दौरान स्वचालित वसूली तंत्र के माध्यम से ईंधन अधिभार की वसूली के लिए अनुमत अधिकतम सीमा से अधिक अतिरिक्त देयता की वसूली के प्रस्तावों पर आदेश, जिसमें थोक उपभोक्ता और अन्य लाइसेंसधारियों के उपभोक्ता शामिल हैं।	31.12.2024
13	ओपी 33/2024 – एनएचपीसी – केएसईबी लिमिटेड की पश्चिम कल्लदा में 50 मेगावाट की पश्चिम कल्लदा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एनएचपीसी के साथ पीपीए करने के अनुमोदन पर आदेश।	01.01.2025
14	ओपी 7/2024 और आईए संख्या 01६24 – वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खातों की जाँच पर आदेश। – मेसर्स केपीयूपीएल	10.02.2025
15	ओपी 65/2023 – केएसईबी लिमिटेड की रणनीतिक व्यावसायिक इकाई-ट्रांसमिशन (एसबीयू-टी) की वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना के अनुमोदन पर आदेश	27.02.2025
16	ओपी 51/2024 – वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सीएसईजेडए)	27.02.2025
17	ओपी 52/2024 – वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स इन्फोपार्क केरल	11.03.2025
18	ओपी 50/2024 – वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स केडीएचपीसीएल	26.03.2025
19	ओपी 84/2023 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए खातों की जाँच के अनुमोदन पर आदेश – मेसर्स टेक्नोपार्क	26.03.2025

16. मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) (संशोधन-1) विनियम, 2024 में तृतीय संशोधन।	31.05.2024
2	मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2021 (तृतीय संशोधन), 2024।	31.05.2024
3	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा एवं मुक्त पहुँच उपभोक्ताओं के लिए मुक्त पहुँच शुल्क एवं बैंकिंग शुल्क निर्धारण की पद्धति विनियम, 2023 में द्वितीय संशोधन।	31.05.2024
4	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मध्य प्रदेश में अंतर-राज्यीय मुक्त पहुँच के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, (संशोधन-1) 2021 में चतुर्थ संशोधन। [एआरजी-24 (1) (पअ) वर्ष 2024]	31.05.2024
5	मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2021 (चतुर्थ संशोधन)	28.06.2024
6	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024	29.06.2024
7	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024	05.07.2024
8	मध्य प्रदेश विद्युत संतुलन एवं निपटान संहिता, 2023 में प्रथम संशोधन	02.08.2024
9	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (संशोधन-1) विनियम, 2024 [आरजी -43(1) वर्ष 2024]	02.08.2024
10	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना) (संशोधन-2) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	30.08.2024
11	सौर पवन संकर उत्पादन परियोजनाओं के पूर्वानुमान, समय-निर्धारण, विचलन शुल्क गणना की प्रक्रिया।	13.09.2024
12	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएँ) विनियम, 2024	04.10.2024
13	मध्य प्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024	04.10.2024
14	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम, 2025	10.01.2025
15	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (सह-उत्पादन एवं उत्पादन) में चतुर्थ संशोधन। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति, (संशोधन-2), विनियम, 2021. [एआरजी-33(2)(पअ) वर्ष 2025]	07.03.2025
16	मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2021 (पाँचवाँ संशोधन) खएआरजी-1(2)(अ) वर्ष 2025,	28.03.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	याचिका संख्या: पी-09/2024 विद्युत मंत्रालय द्वारा 20.10.2022 को जारी दिशा-निर्देशों के अधीन पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद के लिए एमपीपीएमसीएल द्वारा हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार के अनुमोदन हेतु याचिका।	05.04.2024
2	याचिका संख्या: पी-01/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (च) के अधीन जेपीवीएल (निगरी) द्वारा दाखिल याचिका के विषय में, एमपीईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2015 के विनियम 36.4 और एमपीईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020 के विनियम 42.6 के अनुसार देय प्रोत्साहन से संबंधित याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 (एमपीपीएमसीएल) के बीच विवाद के निर्णय हेतु।	23.04.2024
3	याचिका संख्या: पी-07/2024 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1) (एफ) के अधीन एमपीपीटीसीएल की समीक्षा याचिका के विषय में, जिसमें पी. संख्या 55ध2023 में एमपीईआरसी के दिनांक 12.12.2023 के आदेश की समीक्षासंशोधन की मांग की गई हैं	22.05.2024
4	याचिका संख्या: पी- 31/2024 मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2021 के खंड 11.23 सहपठित खंड 11.19 के अधीन अभ्यास निर्देशों के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध निष्पादित करने और उपभोक्ता को ऑनलाइन मोड के माध्यम से ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट को स्व-प्रमाणितअपलोड करने की अनुमति देने हेतु आवश्यक नियामक छूट की मांग करने वाली याचिका।	12.06.2024
5	याचिका संख्या: पी-43/2024 मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2021 के खंड 4.84 के उप-खंड (प) और उसके पश्चात के संशोधनों के संबंध में आवश्यक अभ्यास निर्देश की मांग करने वाली याचिका।	12.08.2024
6	याचिका संख्या: पी-23/2024 जेपीवीएल (निगरी) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (एफ) के अधीन याचिका संख्या 62ध2023 में पारित दिनांक 28.02.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु समीक्षा याचिका दाखिल की गई।	13.08.2024
7	याचिका संख्या: पी-24/2024 जेपीवीएल (बीना) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1) (च) के अधीनदाखिल समीक्षा याचिका, जिसमें आयोग द्वारा याचिका संख्या 63/2023 में पारित दिनांक 22.02.2024 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	13.08.2024
8	याचिका संख्या: पी-33/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1)(च) के अधीन जिंदल पावर द्वारा दाखिल समीक्षा याचिका के विषय में, आयोग द्वारा याचिका संख्या 09/2024 में दिनांक 05.04.2024 को आदेश पारित किया गया।	13.08.2024
9	याचिका संख्या: पी-40/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 (आज तक संशोधित) की धारा 86 (1)(ड) और (च) के साथ पठित मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 9 (ए)(ओ) और 9(आर) के अधीन, लाइसेंसधारी प्रतिवादी के मामलों के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में उचित आदेश पारित करने हेतु याचिका, एन-2 स्थित मशीन के लिए दिनांक 18.01.2012 की पीपीडब्ल्यूए अवधि के विस्तार हेतु अनुमति प्रदान करने के विषय में, जो 17.10.2024 को समाप्त होने वाली है और एन-5 स्थित मशीन के लिए दिनांक 18.01.2012 की एक अन्य पीपीडब्ल्यूए, जो 24.01.2025 को समाप्त होने वाली है।	13.08.2024
10	याचिका संख्या: पी-26/2024 एमपीपीजीसीएल द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीनदाखिल समीक्षा याचिका जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमपीपीजीसीएल के तापीय और जल विद्युत संयंत्रों के उत्पादन शुल्क के सत्यापन के संबंध में याचिका संख्या 71/2023 में आयोग द्वारा पारित दिनांक 07.03.2024 के आदेश में अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट त्रुटि के कारण शुद्धिपत्र की मांग की गई है।	23.08.2024
11	याचिका संख्या: पी-35/2024 जेपीवीएल (निगरी) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1) (च) के अधीन याचिका संख्या 01/2024	23.08.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	में दिनांक 23.04.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु समीक्षा याचिका दाखिल की गई।	
12	याचिका संख्या: पी-39/2024 एमपीपीएमसीएल और राज्य डिस्कॉम द्वारा दाखिल याचिका में सभी नए कनेक्शनों के लिए स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर की अनिवार्य स्थापना से छूट बढ़ाने और साथ ही बंद पड़े/खराब/जले हुए मीटरों को स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर से बदलने की मांग की गई है। साथ ही, एमपीपीएमसीएल और राज्य डिस्कॉम द्वारा पीवीजीटी/अन्य घरों के विद्युतीकरण के लिए भी ऐसी छूट बढ़ाने की मांग की गई है।	23.08.2024
13	याचिका संख्या:पी-08/2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के अनुरूप ट्रांसमिशन कार्यों के लिए पूंजी निवेश योजना के अनुमोदन हेतु एमपीपीटीसीएल की याचिका के विषय में।	03.09.2024
14	याचिका संख्या: पी-20/2024 वितरण लाइसेंसधारी के रूप में एमपीपीकेवीवीसीएल, जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संशोधित कैपेक्स आवेदन (पूंजी निवेश योजना) हेतु याचिका।	04.09.2024
15	याचिका संख्या: पी-37/2024 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन एमपीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन एवं उत्पादन) विनियम, 2021 (संशोधन-II) के प्रावधानों और 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरपीओ दायित्व का पालन न करने के लिए नोटिस।	19.09.2024
16	याचिका संख्या:पी-48/2024 दिनांक 19.11.2010 से वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक खुले बाजार से आरईसी खरीदनेधूसमायोजित करने और बकाया राशि प्राप्त करनेधआरपीओ को आगे बढ़ाने के अनुमोदन का अनुरोध।	23.09.2024
17	याचिका संख्या: पी-30/2024 अधिनियम की धारा 46 और मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति के उद्देश्य से प्रयुक्त विद्युत लाइन या संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु व्यय एवं अन्य शुल्कों की वसूली) (संशोधन-II विनियम 22 आरजी-31 (II) 2022 दिनांक 31 मई 2022) के खंड 6.5, 6.6 के अधीनदाखिल याचिका।	24.09.2024
18	याचिका संख्या: पी-36/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन नोटिस	26.09.2024
19	याचिका संख्या: पी-41/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ग), 86(1)(च) और 86(1)(के) के अधीन याचिका, साथ ही मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 45, अनुच्छेद 4.4, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16 और दिनांक 21.01.2023 को याचिकाकर्ता और दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के बीच निष्पादित पारेषण सेवा करार के अन्य प्रासंगिक खंडों के साथ, अप्रत्याशित घटनाओं और उनसे उत्पन्न होने वाली परिणामी राहतों के कारण निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि के विस्तार की मांग के लिए।	01.10.2024
20	याचिका संख्या: पी- 27, 28 और 29/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9, 42 और 86 के साथ विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142, 146 और 149 के अधीन याचिकाएँ, कैप्टिव पावर पर अतिरिक्त अधिभार लगाने को चुनौती दी गई है।	07.10.2024
21	याचिका संख्या: पी-46/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (च) के अधीन याचिका, जिसमें याचिका संख्या 11/2024 में पारित दिनांक 20.06.2024 के विवादित आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	07.10.2024
22	याचिका संख्या: पी-42/2024 एमपीईआरसी (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिए खुली पहुंच शुल्क और बैंकिंग शुल्क निर्धारण की पद्धति) विनियम 2023 के कुछ प्रावधानों में संशोधन, परिवर्धन और स्पष्टीकरण की मांग करने वाली याचिका।	05.11.2024
23	याचिका संख्या: पी-44/2024 माननीय आयोग के दिनांक 28.11.2022 और 21.09.2023 के आदेशों का पालन न करने पर अवज्ञा और अवमानना कार्यवाही हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन याचिका।	06.11.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
24	याचिका संख्या: पी-47/2024 एमपीपीजीसीएल द्वारा एसजीटीपीएस, बिरसिंहपुर के पीएच-2 की इकाई संख्या 4 (210 मेगावाट) के लिए विशेष भत्ता प्राप्त करने हेतु दाखिल याचिका के विषय में।	08.11.2024
25	याचिका संख्या: पी-25/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अधीन अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश के लिए वितरण लाइसेंस के क्षेत्र में संशोधन हेतु याचिका (डीएल/1 दिनांक 16 जून, 2021)।	12.11.2024
26	याचिका संख्या: पी-49/2024 आर.पी.ओ. दायित्वों के अनुपालन हेतु 19.11.2010 से वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक खुले बाजार से आर.ई.सी. खरीदने और बकाया आर.पी.ओ. प्राप्त करने के अनुमोदन का अनुरोध।	19.11.2024
27	याचिका संख्या: पी-59/2024 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) के साथ पठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (संशोधन-पे) विनियम 2016 के खंड 45, 46 और 47 के अधीन याचिका, जिसमें टैरिफ आदेश के टैरिफ अनुसूची-एचवी-3 के विशिष्ट नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट खंड (घ) और (च) के अनुसार याचिकाकर्ता को वृद्धिशील खपत की छूट और कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ताओं के लिए छूट प्रदान करने हेतु उचित निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका मेसर्स दीपक स्पिनर्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल डिस्कॉम द्वारा दाखिल की गई है।	09.12.2024
28	याचिका संख्या: पी-60/2024 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति के उद्देश्य से प्रयुक्त विद्युत लाइन या संयंत्र प्रदान करने हेतु व्यय और अन्य शुल्कों की वसूली) विनियम, 2022 के विनियम 6.5 और 6.6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 46, 86(1) और 181 के अधीन विद्युतीकृत क्षेत्रों में नए सेवा कनेक्शनों के लिए सरलीकृत शुल्कों के विषय में।	11.12.2024
29	याचिका क्रमांक पी-58/2024 मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2021 के खंड 7.29 में आवश्यक संशोधन हेतु याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से आवश्यक नियामक व्यवस्था की मांग की गई है।	12.12.2024
30	याचिका संख्या: पी-38/2024 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अधीन एमपीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन एवं उत्पादन) विनियम, 2021 (संशोधन-II) के प्रावधानों और 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरपीओ दायित्व का पालन न करने के लिए नोटिस।	18.12.2024
31	याचिका संख्या: पी-61/2024 एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन दाखिल याचिका के विषय में, याचिकाकर्ता की परियोजना के संबंध में ऋणदाता (या उनके किसी भी समनुदेशिती, हस्तान्तरित या नवप्रवर्तक) के लाभ के लिए कार्यरत प्रतिवादी संख्या 2 (मेसर्स कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड) के पक्ष में याचिकाकर्ता की सभी परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित के सृजन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।	30.12.2024
32	याचिका संख्या: पी-32/2024 जिला अनूपपुर (मध्य प्रदेश) में कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (2 ग 600 मेगावाट) की इकाई संख्या 1 के लिए फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली के संबंध में इसके संचालन की तिथि (ओडीई) से 31.03.2024 तक अनुपूरक शुल्क का निर्धारण।	31.12.2024
33	याचिका संख्या: पी-50/2024 मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 28 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 142, एवं प्रतिवादी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन एवं प्रतिवादी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश के उल्लंघन के विषय में	31.12.2024
34	याचिका संख्या: पी-74/2024	22.01.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 40 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 1 के आदेश 47 के साथ पठित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन, स्वतः संज्ञान से याचिका संख्या 45/2024 में पारित दिनांक 04.10.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु याचिका।	
35	याचिका संख्या: पी-51/2024 ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, (मध्य प्रदेश) में 2ग45 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (इकाई संख्या 1 और 2) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।	13.02.2025
36	याचिका संख्या: पी-79/2024 मध्य प्रदेश में लघु जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत क्रय हेतु टैरिफ निर्धारण के विषय में स्वतः संज्ञान से दाखिल याचिका।	20.02.2025
37	याचिका संख्या: पी-52/2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की नियंत्रण अवधि के लिए बीना, जिला सागर (मध्य प्रदेश) में 2 ग 250 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।	28.02.2025
38	याचिका संख्या: पी-53/2024 मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निगरी में 2 ग 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की नियंत्रण अवधि के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।	28.02.2025
39	याचिका संख्या: पी-57/2024 मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 2 ग 600 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की नियंत्रण अवधि के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।	28.02.2025
40	याचिका संख्या: पी-56/2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की नियंत्रण अवधि के लिए एमपीपीजीसीएल के तापीय और जल विद्युत संयंत्रों के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ का निर्धारण।	04.03.2025
41	याचिका संख्या: पी-67/2024 एसएलडीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसएलडीसी जबलपुर के एआरआर के निर्धारण, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसएलडीसी द्वारा शुल्क और प्रभारों के आरोपण और संग्रहण तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर के टू-अप निर्धारण हेतु दाखिल याचिका के विषय में	04.03.2025
42	याचिका संख्या: पी-34/2024 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अधीन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका, जिसमें (प) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच दिनांक 01.08.2012 को निष्पादित विद्युत क्रय करार में उल्लिखित ऊर्जा दायित्वों को पूरा करने के लिए एसी क्षमता या संविदात्मक क्षमता में वृद्धि किए बिना, याचिकाकर्ता की सौर ऊर्जा परियोजना की डीसी क्षमता को पुनः शक्ति प्रदान करने और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल की स्थापना हेतु अनुमोदन की मांग की गई है।	12.03.2025
43	याचिका संख्या: पी-68/2024 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमपीपीटीसीएल जबलपुर के ट्रांसमिशन टैरिफ के टू-अप के लिए एमपीपीटीसीएल द्वारा दाखिल याचिका के विषय में। एमपीईआरसी द्वारा 19 मई, 2021 के एमवाईटी आदेश में पी. संख्या 45/2020 में निर्धारित।	18.03.2025
44	याचिका संख्या: पी-54/2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय पारेषण शुल्क निर्धारण हेतु एमपीपीटीसीएल द्वारा दाखिल याचिका के विषय में।	20.03.2025
45	याचिका संख्या: पी-63/2024 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) में 2ग45 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (इकाई संख्या 1 और 2) के लिए टैरिफ का सही निर्धारण।	21.03.2025
46	याचिका संख्या: पी-64/2024 एमबी पावर (एमपी) लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 ग 600 मेगावाट कोयला आधारित अनूपपुर ताप विद्युत परियोजना के लिए उत्पादन शुल्क के सत्यापन हेतु दाखिल याचिका के विषय में।	28.03.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
47	याचिका संख्या: पी-69/2024 कोरबा पावर लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पटाडी गाँव में स्थित 1 ग300 मेगावाट (यूनिट संख्या 1) कोरबा पावर लिमिटेड (पूर्वनामलैंको अमरकंटक) कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादन शुल्क में संशोधन हेतु दाखिल याचिका के विषय में।	28.03.2025
48	याचिका संख्या: पी - 70/2024 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति एवं व्हीलिंग हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभार निर्धारण हेतु विधि एवं सिद्धांत) विनियम, 2021 के विनियम 7.2 के अधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर के ट्र-अप निर्धारण हेतु याचिका और उसका संशोधनय वितरण लाइसेंसधारी के रूप में एमपीपीएमसीएल और एमपीपीओकेवीवीसीएल, एमपीपीएकेवीवीसीएल और एमपीएमकेवीवीसीएल द्वारा दाखिल।	28.03.2025
49	याचिका संख्या: पी-75/2024 एमपीईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 40 एवं 45 तथा एमपीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन एवं उत्पादन) विनियम, 2021 के विनियम 18 एवं विनियम 19 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(1) के अधीन माननीय आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान से पारित याचिका संख्या 37/2024 के दिनांक 19.09.2024 के आदेश की समीक्षा एवं संशोधन हेतु याचिका	28.03.2025
50	याचिका संख्या: पी - 71/2024 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति एवं व्हीलिंग हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभार निर्धारण हेतु विधि एवं सिद्धांत) विनियम, 2021 दिनांकित एवं उसके संशोधनों में निर्धारित टैरिफ सिद्धांतों के अधीन मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीआईडीसी), विशेष आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर, इंदौर के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु एआरआर के ट्रू अप निर्धारण हेतु याचिका।	29.03.2025
51	याचिका संख्या: पी - 72/2024 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति एवं व्हीलिंग हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभार निर्धारण हेतु विधि एवं सिद्धांत) विनियम, 2021 और उसके संशोधनों में निर्धारित टैरिफ सिद्धांतों के अधीन, वितरण लाइसेंसधारियों अर्थात् मध्य प्रदेश पूर्व डिस्कॉम, मध्य प्रदेश मध्य डिस्कॉम, मध्य प्रदेश पश्चिम डिस्कॉम और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु संशोधित एआरआर और टैरिफ प्रस्ताव के निर्धारण हेतु याचिका।	29.03.2025
52	याचिका संख्या: पी-45/2024 एमपीईआरसी ने स्वतः संज्ञान याचिका संख्या 45/2024 में 77 अंतिम आदेश जारी किए हैं। एमपीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन एवं उत्पादन) विनियम, 2010 (संशोधन-I) के प्रावधानों और 10.11.2010 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समय-समय पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरपीओ दायित्व का पालन न करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन नोटिस।	25.09.2024, 27.09.2024, 30.09.2024, 01.10.2024, 03.10.2024, 04.10.2024, 07.10.2024, 08.10.2024, 10.10.2024, 15.10.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 23.10.2024, 24.10.2024,

17. महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और विद्युत लोकपाल) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	22.05.2024
2	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता हेतु रूपरेखा) विनियम, 2024	20.06.2024
3	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पूर्वानुमान, समय-निर्धारण और विचलन निपटान) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	04.07.2024
4	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता और विद्युत गुणवत्ता सहित वितरण	05.07.2024

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
	लाइसेंसधारियों के कार्य निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	
5	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024	19.08.2024
6	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024	29.08.2024
7	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (व्यावसायिक लेन-देन और शुल्क और प्रभार) (पहला संशोधन) विनियम, 2024	23.09.2024
8	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) विनियम, 2024	25.09.2024
9	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (माँग लचीलापन और माँग पक्ष प्रबंधन – कार्यान्वयन ढाँचा, लागत प्रभावशीलता आकलनय और मूल्यांकन, मापन और सत्यापन) विनियम, 2024	19.11.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मामला, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के टू-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के अनंतिम टू-अप और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए एआरआर और टैरिफ के अनुमोदन हेतु, महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 के अनुसार।	28.03.2025
2.	बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम (बेस्ट) का मामला, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के टू-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टू-अप और एआरआर अनुमानों और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
3.	अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई का मामला लिमिटेड (वितरण व्यवसाय) को वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम टूइंग-अप, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और टैरिफ के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
4.	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण) का मामला वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के अनंतिम टूइंग-अप, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और टैरिफ के निर्धारण के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
5.	एमईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 के अधीनवित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और श्रेणीवार टैरिफ सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के निर्धारण और अनुमोदन के लिए एमआईटीएल बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का मामला।	28.03.2025
6.	एमईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 के अधीनवित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और श्रेणीवार टैरिफ सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के निर्धारण और अनुमोदन के लिए एमआईटीएल शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र का मामला।	28.03.2025
7.	मेसर्स एसईजेड बायो-टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मामला। लिमिटेड दृ मंजरी एसईजेड (एसईजेड बायो-टेक मंजरी) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग-अप के लिए, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5वीं नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ निर्धारण के अनुमोदन	28.03.2025
8.	मेसर्स एसईजेड बायो-टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – हडपसर एसईजेड (एसईजेड बायो-टेक हडपसर) का मामला, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग-अप के लिए, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5वीं नियंत्रण अवधि के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ निर्धारण का अनुमोदन।	28.03.2025
9.	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) का मामला, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग-अप और वित्तीय वर्ष 2025-26 से	28.03.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की बहु-वर्षीय टैरिफ अवधि के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ के अनुमोदन के लिए।	
10.	ईओएन खराड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ईओएन एसईजेड चरण पे) का मामला, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग-अप और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की बहु-वर्षीय टैरिफ अवधि के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ निर्धारण के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
11.	ईओएन खराड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ईओएन एसईजेड चरण पे) का मामला वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 का टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनंतिम टूइंग-अप, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक बहु-वर्षीय टैरिफ अवधि के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ निर्धारण का अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
12.	एईएमएल सीपिज लिमिटेड (एएसएल) का मामला, जिसके वितरण व्यवसाय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग-अप, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
13.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का मामला, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग-अप, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
14.	गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का मामला, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के टूइंग-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग-अप, और कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ के अनुमोदन हेतु। वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ	28.03.2025
15.	माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का मामला लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के टूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग अप, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
16.	केआरसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का मामला वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के टूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग अप, और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ के अनुमोदन हेतु।	28.03.2025
17.	लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाय चेन मैनेजमेंट लिमिटेड का मामला वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के टूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम टूइंग अप और कुल राजस्व के अनुमोदन हेतु। वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए अपेक्षा (एआरआर) और बहु-वर्षीय टैरिफ	28.03.2025
18.	महाराष्ट्र में कैप्टिव पावर प्लांट उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन लक्ष्यों का सत्यापन और अनुपालन। (1/एसएम/2024)	18.02.2025
19.	मेसर्स खरे और तारकुंडे ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की याचिका, हिंगोली जिले के ताल कलमनुरी के कडपदेव गांव में ईसापुर बांध की दाहिनी तट नहर पर स्थित 4 मेगावाट (2 ग 2 मेगावाट) क्षमता की ईसापुर जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए। (मामला संख्या 59/2024)	20.09.2024

18. मणिपुर विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच शुल्क निर्धारण की पद्धति) विनियम, 2024	09.04.2024

2	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (अठारहवाँ संशोधन) विनियम, 2024	08.06.2024
---	---	------------

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वार्षिक प्रतिशत समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा का निर्धारण और खुदरा टैरिफ आदेश	शून्य
2	मणिपुर राज्य में मणिपुर राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत पारेषण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	शून्य

19. मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2023	09.05.2024
2	मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता के लिए ढांचा) विनियम, 2023	09.05.2024
3	मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व और उसका अनुपालन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018	26.11.2024
4	मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) (प्रथम संशोधन) (2024 का 2) विनियम, 2017	20.12.2024
5	मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग (नेट मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सोलर ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 (1/2025)	15.01.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप आदेश।	18.10.2024
2	मेघालय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप आदेश।	18.10.2024
3	मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप आदेश।	18.10.2024
4	मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक की नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन शुल्क	24.10.2024
5	मेघालय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक की नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारेषण और खुली पहुंच शुल्क और एसएलडीसी शुल्क	24.10.2024
6	मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक की नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वितरण शुल्क	24.10.2024
7	मेघालय के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू-अप आदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	22.03.2025
8	मेघालय विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू-अप आदेश	22.03.2025
9	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्पादन शुल्क	22.03.2025
10	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पारेषण शुल्क	22.03.2025
11	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू-अप आदेश	24.03.2025
12	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वितरण शुल्क	24.03.2025

20. मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना के निर्माण हेतु सीमा)	29.08.2024
2	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग (अनुपालन लेखा परीक्षा) विनियम, 2024	30.09.2024
3	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग (ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन) विनियम, 2024	30.09.2024
4	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग (वितरण एवं पारेषण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक) विनियम, 2014, आदेश 2024, (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	11.10.2024
5	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति का गठन) विनियम, 2024	14.10.2024
6	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं उसका अनुपालन) विनियम, 2024	18.11.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	24.03.2025

21. नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसधारी के वितरण और पारेषण के लिए कार्य निष्पादन के मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	17.05.2024
2	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (रूफटॉप सोलर ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नेटवर्क मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	20.05.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप का निर्धारण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) एवं टैरिफ का निर्धारण – विद्युत विभाग, नागालैंड सरकार के नेतृत्व में	13.03.2024
2	एनईसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए उत्पादन टैरिफ आदेश	11.03.2025

22. ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (एकीकृत खदान से कोयले के इनपुट मूल्य का निर्धारण) विनियम, 2024	16.07.2024
2	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024	13.11.2024
3	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता हेतु रूपरेखा) विनियम, 2024	12.02.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2025-25 के लिए ओएचपीसी के एआरआर का अनुमोदन और उत्पादन शुल्क का निर्धारण (83/2024 और मामला संख्या 59/2024)	24.03.2025
2	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ओपीजीसी (इकाई 1 और 2) के उत्पादन शुल्क का निर्धारण (मामला संख्या 82/2024)	24.03.2025
3	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रिडको लिमिटेड के एआरआर का अनुमोदन और थोक आपूर्ति मूल्य का निर्धारण (मामला संख्या 94/2024 और 123/2024)	24.03.2025
4	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ओपीटीसीएल के एआरआर का अनुमोदन और ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण (मामला संख्या 93/2024)	24.03.2025
5	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसएलडीसी के एआरआर और फीस एवं परिचालन प्रभार के निर्धारण का अनुमोदन (मामला संख्या 92/2024)	24.03.2025
6	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए डिस्कॉम के एआरआर, व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अनुमोदन (मामला संख्या 84/2024, 2024 का 88/2024, 95/2024 और 99/2024)	24.03.2025

23. पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2024	21.05.2024
2	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024	11.06.2024
3	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024	17.09.2024
4	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, निष्पादन मानक और संबंधित मामले) विनियम, 2024	23.10.2024
5	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति)	04.12.2024
6	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेइक सिस्टम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025	20.02.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	याचिका संख्या: 32/2023	25.04.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	पीएसपीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 'पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना' (आरडीएसएस) के लिए पूंजीगत व्यय का अनुमोदन। इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इसके लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और सुधारों में बुनियादी न्यूनतम मानदंडों को प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना को मजबूत करने हेतु पीएसपीसीएल को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	
2	याचिका संख्या: 17/2024 ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार लगाने के संबंध में निर्देशों के लिए माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 71 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86, 181 और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन याचिका।	16.05.2024
3	याचिका संख्या: 04/2024 पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतर-राज्यीय खुली पहुंच के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 27 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 42 (4) के अतिरिक्त अधिभार के निर्धारण हेतु याचिका, जिसे 01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए पीएसपीसीएल के अलावा अन्य स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया जाएगा।	05.06.2024
4	समीक्षा याचिका संख्या: 04/2023, याचिका संख्या: 74/2022 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिनांक 15.05.2023 के टैरिफ आदेश के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अधीन समीक्षा याचिका, याचिका संख्या: 74/2022 के संदर्भ में।	06.06.2024
5	याचिका संख्या: 63/2023 पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 9 से 13 के साथ पढ़ें समय-समय पर यथा संशोधित के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अधीन और पीएसईआरसी के विनियमन 10 और 11 के साथ पठित (उत्पादन, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण की शर्तें) विनियम, 2022 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ट्रांसमिशन व्यवसाय और एसएलडीसी के लिए एआरआर के संशोधित पूर्वानुमान और टैरिफ के निर्धारण, द्वितीय एमवाईटी नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए पूंजीगत व्यय के टू-अप और ट्रांसमिशन व्यवसाय और एसएलडीसी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एआरआर के टू-अप के अनुमोदन के लिए याचिका।	14.06.2024
6	याचिका संख्या: 2023 की 64 पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 12 और 13, समय समय पर यथा संशोधित के साथ पठित और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के पूर्वानुमान और टैरिफ के निर्धारण, पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 के विनियम 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एआरआर के टू-अप आकलन के अनुमोदन हेतु याचिका,	14.06.2024
7	याचिका संख्या: 20/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 23 के अधीन टैरिफ वर्ष 2024-25 के लिए नियामक उपाय करने हेतु याचिका।	14.06.2024
8	18/2024 स्वतः संज्ञान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 33, पंजाब राज्य ग्रिड संहिता के विनियम 2.3 और इस संबंध में आयोग द्वारा पंजाब राज्य भार प्रेषण केंद्र को जारी निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन कार्रवाई।	11.07.2024
9	67/2023 स्वतः संज्ञान पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतर-राज्यीय ओपन एक्सेस के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 28 (6) के अधीन निर्देशों के अनुपालन में पीएसपीसीएल द्वारा प्रस्तुत हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिए पावर बैंकिंग और मॉडल बैंकिंग करार की प्रक्रिया, समय-समय पर संशोधित।	12.07.2024
10	याचिका संख्या: 22/2024	18.07.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	आपूर्ति संहिता-2014 के विनियम 47 और व्यवसाय संचालन विनियम 2005 के अध्याय गप्प के विनियम 69,70,71 और 72 के अधीन याचिका, जिसमें मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों के लिए याचिका संख्या 05६2023 में पारित दिनांक 15.05.2023 के आदेश में स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की गई है।	
11	याचिका संख्या: 15/2024 एमवाईटी 2023-26 में पहले से स्वीकृत कार्यों के संशोधित दायरे/लागत के अनुमोदन और पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 के विनियम-9 के अधीन तृतीय एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अत्यावश्यक प्रकृति के नए कार्य (पूँजीगत कार्य) को शामिल करने के संबंध में।	10.08.2024
12	याचिका संख्या: 29/2024 पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतर-राज्यीय खुली पहुँच के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 27 के साथ पठित,भारतीय विद्युत अधिनियम – 2003 की धारा 42 (4) के अधीन अतिरिक्त अधिभार के निर्धारण के लिए याचिका, दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि के लिए पीएसपीसीएल के अलावा अन्य स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले खुली पहुँच वाले उपभोक्ताओं पर लागू की जाएगी।	11.09.2024
13	याचिका संख्या: 03/2024 एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाली 500 मेगावाट तीस्ता टप, 120 मेगावाट रंगीत प्ट और 850 मेगावाट रैटल जलविद्युत परियोजनाओं से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा आवंटित की जाने वाली बिजली के लिए पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की खरीद प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु याचिका।	21.10.2024
14	याचिका संख्या: 41/2024 पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतर-राज्यीय खुली पहुँच के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के विनियम 27 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 42 (4) के अतिरिक्त अधिभार के निर्धारण हेतु याचिका, जिसे 01.10.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए पीएसपीसीएल के अलावा अन्य स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले खुली पहुँच वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया जाएगा।	04.11.2024
15	याचिका संख्या: 62/2021, साथ ही आईए संख्या 25/2022 व्यावसायिक नियमन 2005 के अध्याय XIII के विनियम 69, 70, 71 और 72 के अधीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों और कुछ अन्य प्रकार के उद्योगों पर पीआईयू टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु याचिका।	04.11.2024
16	याचिका संख्या: 70/2022 व्यवसाय संचालन विनियम, 2005 के अध्याय गप्प के विनियम 69, 70, 71 और 72 के अधीन हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रक्रिया के संयोजन का उपयोग करते हुए मेसर्स स्टेल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रामपुरा फूल पर पीआईयू टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु याचिका।	04.11.2024
17	समीक्षा याचिका संख्या 01 और याचिका संख्या 38, 2022। पीएसईआरसी (कार्य संचालन) विनियम 2005 के विनियम 69 के साथ पठित विनियम 64 के अधीन समीक्षा याचिका, जिसमें मुख्य याचिका में माननीय आयोग द्वारा दिए गए 30.11.2022 के आदेश की समीक्षा की प्रार्थना की गई है।	04.11.2024
18	याचिका संख्या: 10/2024 आपूर्ति संहिता – 2014 के विनियम 47 और व्यवसाय संचालन विनियम 2005 के अध्याय XIII के विनियम 69,70,71 और 72 के अधीन सभी श्रेणियों के चूककर्ता उपभोक्ताओं (एपी को छोड़कर) के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने हेतु याचिका 30.09.2023 तक मौजूद थी।	22.11.2024
19	2023 के भाग संख्या 63 में समीक्षा याचिका संख्या 01/2024 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 64 के साथ पठित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1) (च) के अधीन, याचिका संख्या 63/2023 में पारित दिनांक 14.06.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु याचिका।	28.11.2024
20	याचिका संख्या: 25/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 86 के अधीनपीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 के विनियम 47 तथा इसके संशोधन	05.12.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	सहित और पीएसईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 55 तथा इसके संशोधनसहित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएस) के टू-अपनिर्धारण के अनुमोदन हेतु याचिका।	
21	याचिका संख्या: 59/2023 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (ख) और पीएसईआरसी विनियम 9.14 के अधीन याचिका दायर की जा रही है।	11.12.2024
22	2023 की याचिका संख्या 64 में समीक्षा याचिका संख्या 02/2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिनांक 14.06.2024 के टैरिफ आदेश के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अधीन समीक्षा याचिका।	12.12.2024
23	56/2024 स्वतः संज्ञान पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, निष्पादन मानक और संबंधित मामले) विनियम, 2024, संक्षेप में आपूर्ति संहिता, 2024, जारी होने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीएसपीसीएल के लिए दिनांक 14.06.2024 के टैरिफ आदेश में संशोधन हेतु।	23.12.2024
24	याचिका संख्या: 64/2024 भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के स्वामित्व और संचालन वाली राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (आरएपीपी) की इकाई - 7 और 8 से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा आवंटित 64.55 मेगावाट बिजली के लिए पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की खरीद प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु याचिका।	03.02.2025
25	याचिका संख्या: 40/2024 आपूर्ति संहिता 2014 के विनियम 47 और व्यवसाय संचालन विनियम 2005 के अध्याय ८ के विनियम 8(4) के अधीन मानक लागत आंकड़ों में संशोधन हेतु याचिका।	31.12.2024
26	याचिका संख्या: 62/2023 पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 39.7 और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 38.7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 86 के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण प्रतिवादियों से कम वसूली गई ऊर्जा शुल्क की वसूली हेतु याचिका।	14.06.2024
27	याचिका संख्या: 66/2023 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखापरीक्षित खातों और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार, पूंजी निवेश योजना के आधार पर और पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें), विनियम, 2022 की धारा 60 के अधीन, बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए 100 मेगावाट मलाणा-८ जलविद्युत परियोजना हेतु वार्षिक निश्चित लागत के अनुमोदन हेतु याचिका।	24.10.2024
28	याचिका संख्या: 37/2014 माननीय एपीटीईएल द्वारा दिनांक 09.07.2024 के आदेश द्वारा प्रत्यावर्तन 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए 100 मेगावाट मलाणा ८ जलविद्युत परियोजना की वार्षिक स्थिर लागत के अनुमोदन, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 56 (2), (3) और (4) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन वित्तीय वर्ष 2012-13 और वित्तीय वर्ष 2013-14 के व्ययों का समायोजन हेतु याचिका।	13.11.2024
29	याचिका संख्या: 17/2017 माननीय एपीटीईएल द्वारा दिनांक 09.07.2024 के आदेश द्वारा वापस भेजा गया पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 56 (2) और (3) के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 100 मेगावाट मलाणा ८ जलविद्युत परियोजना की वार्षिक स्थिर लागत और सही करने के अनुमोदन हेतु याचिका।	13.11.2024
30	2014 की याचिका संख्या 37 में समीक्षा याचिका संख्या 09/2015 माननीय एपीटीईएल द्वारा दिनांक 09.07.2024 के आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 64 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका संख्या 37/2014 में दिनांक 31.08.2015 के	13.11.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	आदेश की समीक्षा हेतु समीक्षा याचिका	
31	2023 के भाग संख्या 63 में समीक्षा याचिका संख्या 01/2024 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 64 के साथ पठित, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1) (च) के अधीन,याचिका संख्या 63ध2023 में पारित दिनांक 14.06.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु याचिका।	28.11.2024
32	2023 की याचिका संख्या 64 में समीक्षा याचिका संख्या 02/2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिनांक 14.06.2024 के टैरिफ आदेश के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अधीन समीक्षा याचिका।	12.12.2024

24.राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024	30.08.2024
2	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राजस्थान विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2024	29.01.2025
3	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2024	12.03.2025
4	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025	06.03.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	याचिका संख्या 2121/2023, 2129/2023, 2176/2023, 2174/2023, 2175/2023 और 2178/2023 आयोग के दिनांक 14.07.2022 और 31.03.2023 के आदेशों की समीक्षा हेतु याचिकाएँ	18.04.2024
2	याचिका संख्या 2209/2024 राजस्थान में 810 मेगावाट की अंतर-राज्यीय संयोजित सौर पीवी विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संयोजन के माध्यम से तापीयध्वजल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन और समय-निर्धारण में लचीलेपन हेतु योजना के अधीन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त टैरिफ को अंगीकृत करने के लिए याचिका।	01.05.2024
3	याचिका संख्या 2226/2024 पीएम-कुसुम योजना के घटक ग (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अधीन 25 वर्षों की अवधि के लिए 2929.8 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 1111 सौर पीवी संयंत्रों के स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	01.05.2024
4	याचिका संख्या 2213/2024 900 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए टैरिफ अंगीकृत करने के लिए याचिका	15.05.2024
5	याचिका संख्या 2219/2024 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 (बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का निर्धारण) के अधीन, आरईआरसी (व्यावसायिक लेन-देन), विनियम 2021 के विनियम 19 और 21 के साथ पठित, टीएन-डीएसएम-07 के अधीन पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अधीन सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एवीवीएनएल द्वारा की गई पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु दाखिलयाचिका।	31.05.2024
6	याचिका संख्या 2233/2024	04.06.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन, दिनांक 01.05.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु, आरईआरसी (कारोबार का लेन-देन) विनियम, 2021 के साथ पठित, समीक्षा हेतु दाखिल समीक्षा याचिका।	
7	याचिका संख्या 2223/2024 पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अधीन 316.47 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जेवीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	04.06.2024
8	याचिका संख्या 2182/2023 राज्य भार प्रेषण केंद्र के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा एवं एसएलडीसी शुल्क के अनुमोदन के विषय में	19.07.2024
9	याचिका संख्या 2196/2024 आरवीयूएन के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (एसएससीटीपीपी) (यूनिट-7 और 8) के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) एवं टैरिफ के निर्धारण के विषय में	22.07.2024
10	याचिका संख्या 2193/2024 आरवीपीएन के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के अनुमोदन के विषय में	23.07.2024
11	याचिका संख्या 2183/2023 वित्तीय वर्ष 2022-23 के एआरआर और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ के सही निर्धारण के विषय में	23.07.2024
12	याचिका संख्या 2206/2024, 2207/2024, 2208/2024, 2236/2024 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिस्कॉम की कुल राजस्व आवश्यकता, टैरिफ और निवेश योजना के अनुमोदन के मामले में और अधिकतम सीमा से अधिक ईंधन अधिभार की वसूली के अनुमोदन हेतु याचिका।	26.07.2024
13	याचिका संख्या 2192/2024 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और एसएलडीसी के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन के विषय में	26.07.2024
14	याचिका संख्या 2241/2024 टीएन-06, टीएन-09 और टीएन-10 के अंतर्गत पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अंतर्गत 116.33 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जेवीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	26.07.2024
15	याचिका संख्या 2242/2024 टीएन-डीएसएम-11 से 14 के अंतर्गत पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एवीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	26.07.2024
16	याचिका संख्या 2261/2024 राजस्थान डिस्कॉम में पीएम-कुसुम योजना के घटक-ए के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के लिए पूर्व-निर्धारित स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	28.10.2024
17	याचिका संख्या 2238/2024 एसएससीटीपीपी इकाई 7 और 8 के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात मूल कार्यक्षेत्र के भीतर, कॉलोनी मद के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करने से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु याचिका।	30.10.2024
18	याचिका संख्या 2248/2024 याचिका संख्या 2193/24 में पारित आयोग के दिनांक 23.07.2024 के आदेश की समीक्षा के विषय में	18.11.2024
19	याचिका संख्या 2256/2024 राजस्थान राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा याचिका संख्या 2182/2023 में पारित आयोग के दिनांक 19.07.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु दाखिल याचिका के विषय में	27.11.2024
20	याचिका संख्या 2292/2025 राजस्थान डिस्कॉम में पीएम-कुसुम योजना के घटक ए के अधीन कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध 5000 मेगावाट	12.03.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	सौर ऊर्जा क्षमता के लिए पूर्व-निर्धारित स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	
21	याचिका संख्या 2167/2023 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(च) के अधीन विवाद के निर्णय हेतु दाखिल याचिका के विषय में	02.04.2024
22	याचिका संख्या 2198/2024 राजस्थान में बिजली वितरण कंपनियों के टैरिफ नियमों को अद्यतन करने के लिए दाखिल याचिका ताकि तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को आईटी कनेक्शन प्रदान किए जा सकें।	30.04.2024
23	याचिका संख्या 2235/2024 आरईआरसी (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ) विनियम, 2021 के विषय में	31.05.2024
24	याचिका संख्या 2234/2024 आरईआरसी (आरई प्रमाणपत्र और आरपीओ अनुपालन ढांचा), विनियम, 2010	31.05.2024
25	याचिका संख्या 1373/2018 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के साथ पठित अनुच्छेद 10 के अधीन क्षतिपूर्ति/टैरिफ समायोजन निर्धारित करने हेतु दाखिल याचिका, डिस्कॉम के साथ निष्पादित पीपीए के कानून में परिवर्तन।	19.06.2024
26	याचिका संख्या 2217/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(च) के अधीन दाखिल याचिका	20.06.2024
27	याचिका संख्या 2230/2024 मूल पीपीए में संशोधन के अनुमोदन और पीपीए में संशोधन के आधार पर अब याचिकाकर्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादन के 50 प्रतिशत के टैरिफ को अपनाने और अनुमोदित करने के लिए याचिका	27.06.2024
28	याचिका संख्या 2024/2022 कानून में बदलाव के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त बिजली क्रय लागत को मान्यता देने और विशेष एफएसए के माध्यम से अतिरिक्त बिजली क्रय लागत की वसूली की अनुमति देने के लिए याचिका	07.07.2024
29	याचिका संख्या 2242/2024 टीएन-डीएसएम-11 से 14 के अंतर्गत पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एवीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	10.07.2024
30	याचिका संख्या 2261/2024 राजस्थान डिस्कॉम में पीएम-कुसुम योजना के घटक-ए के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के लिए पूर्व-निर्धारित स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	16.07.2024
31	याचिका संख्या 2238/2024 एसएससीटीपीपी इकाई 7 और 8 के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात मूल कार्यक्षेत्र के भीतर, कॉलोनी मद के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करने से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु याचिका।	18.07.2024
32	याचिका संख्या 2248/2024 याचिका संख्या 2193/24 में पारित आयोग के दिनांक 23.07.2024 के आदेश की समीक्षा के विषय में	19.07.2024
33	याचिका संख्या 2256/2024 राजस्थान राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा याचिका संख्या 2182/2023 में पारित आयोग के दिनांक 19.07.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु दाखिल याचिका के विषय में	24.07.2024
34	याचिका संख्या 2292/2025 राजस्थान डिस्कॉम में पीएम-कुसुम योजना के घटक ए के अधीन कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के लिए पूर्व-निर्धारित स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	24.07.2024
35	याचिका संख्या 2167/2023	25.07.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(च) के अधीन विवाद के निर्णय हेतु दाखिल याचिका के विषय में याचिका संख्या 2244/2024	
36	पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अधीन 208.91 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जेवीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	11.09.2024
37	याचिका संख्या 2243/2024 पीएम-कुसुम योजना के घटक-सी (फीडर स्तरीय सौरीकरण) के अधीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जेवीवीएनएल द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त स्तरीय टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका।	11.09.2024
38	याचिका संख्या 2237/2024 पवन ऊर्जा उत्पादकों के विद्युत क्रय करार को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु याचिका।	22.10.2024
39	याचिका संख्या 2184/2023 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राजस्थान विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2024 के विषय में	29.10.2024
40	याचिका संख्या 2224/2024 आरईआरसी (निबंधन और शर्तें) खुली पहुंच (विनियम), 2016 के विनियम 30(3) के अधीन याचिका	30.10.2024
41	याचिका संख्या 2194/2024 विद्युत अधिनियम की धारा 86(1)(बी) के अधीन याचिका	04.11.2024
42	याचिका संख्या 2270/2024 याचिका संख्या 2270/2024 में नाम परिवर्तन की स्वीकृति हेतु याचिका	19.11.2024
43	याचिका संख्या 2227/2024 आरवीपीएन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अधीन 250 करोड़ रुपये के बजाय 2000 करोड़ रुपये की संशोधित सीमा का अनुमोदन देने के लिए दाखिल याचिका।	29.11.2024
44	याचिका संख्या 2262/2024 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2021 के विनियम 1.2, 6.1 एवं 13.4 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43, 44, 50, 86 (1) एवं 181 के अधीन 150 किलोवाट तक के सेवा कनेक्शन शुल्क के सरलीकरण हेतु शुल्क अनुसूची में आवश्यक संशोधन करने हेतु याचिका दाखिल की गई है।	11.12.2024
45	याचिका संख्या 2247/2024 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता एवं संबंधित मामले) विनियम, 2021 के विनियम 11.2 एवं 14.1 के साथ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) एवं 181 के अधीन उक्त विनियम के विनियम 11.8 (आपूर्ति की बहाली) में आवश्यक संशोधन करने हेतु दाखिल याचिका।	11.12.2024
46	याचिका संख्या 2277/2024 नई नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव विद्युत परियोजनाओं के संबंध में आरईआरसी (आरई टैरिफ) विनियम, 2020 में आवश्यक संशोधन के लिए याचिका।	13.12.2024
47	याचिका संख्या 2275/2024 आरईआरसी (आठवां संशोधन लागू) विनियम, 2024	15.01.2025
48	याचिका संख्या 2250/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (च) के अधीन विवाद का निर्णय	15.01.2025
49	याचिका संख्या 2255/2024 विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अधीन दिनांक 26.07.2024 के आदेश की समीक्षा हेतु याचिका	15.01.2025
50	याचिका संख्या 2253/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (च) के अधीन विवाद का निर्णय	16.01.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
51	याचिका संख्या 2274/2024 राज्य सरकार की बजट घोषणा में घोषित योजनाओं और वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत या स्वीकृत की जाने वाली अन्य योजनाओं के लिए प्रारंभिक व्यय की स्वीकृति हेतु दाखिल याचिका, अनुमोदित निवेश योजना 2024-25 की अधिकतम सीमा के भीतर।	17.01.2025
52	याचिका संख्या 2246/2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अधीन विद्युत चोरी से संबंधित दर्ज मामलों की समीक्षा हेतु वीसीआर समिति के गठन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) और 181 के अधीनदाखिलयाचिका।	20.01.2025
53	याचिका संख्या 2276/2024 आरईआरसी (शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025 के विषय में	24.01.2025
54	याचिका संख्या 2297/2025 वितरण लाइसेंसधारी के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र तथा टूइंग-अप याचिकाओं के अनुमोदन हेतु प्रपत्र।	24.02.2025
55	याचिका संख्या 2296/2025 उत्पादक कंपनियों, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और एसएलडीसी के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ/एमवाईटी प्रस्तुत करने और प्रस्तावों की पुष्टि करने हेतु प्रपत्र	24.02.2025
56	याचिका संख्या 2293/2025 रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधानों में छूट हेतु उक्त विनियमों में आवश्यक संशोधन करने हेतु राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ) विनियम, 2021 के विनियम 21 और उसके संशोधनों के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) और 181 के अधीनदाखिल याचिका।	07.03.2025
57	याचिका संख्या 2294/2025 आरईआरसी (वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत क्रय एवं खरीद प्रक्रिया) विनियम, 2004 के विनियम 7के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (ख) के अधीन, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य को आवंटित नबीनगर एसटीपीएस चरण-प् (3*800 मेगावाट) से विद्युत की खरीद हेतु विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुमोदन हेतु दाखिलयाचिका।	20.03.2025
58	याचिका संख्या 2222/2024 याचिका संख्या 2220/2024 में पृथक पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसिंग) विनियम, 2004 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15, 86 (1) (घ) के अधीन याचिका/आवेदन।	20.03.2025
59	याचिका संख्या 2221/2024 याचिका संख्या 2221/2024 में पृथक पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसिंग) विनियम, 2004 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15, 86 (1) (घ) के अधीन याचिका/आवेदन।	20.03.2025
60	याचिका संख्या 2220/2024 याचिका संख्या 2222/2024 में पृथक पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंसिंग) विनियम, 2004 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15, 86 (1) (घ) के अधीन याचिका/आवेदन।	20.03.2025

25.सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
01	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित सौर पीवी सिस्टम) (संशोधन) विनियम, 2024	12.06.2024
2	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण एवं पारेषण लाइसेंसधारी के लिए कार्यनिष्पादन मानक) (संशोधन) विनियम, 2024	22.07.2024
3	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	02.08.2024
4	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित सौर पीवी सिस्टम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	04.09.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	सिक्किम सरकार के विद्युत विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टू-अप आदेश, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ	27.03.2025

26.तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2024	04.09.2024
2	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (संशोधन)	22.01.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम टैरिफ सब्सिडी।	15.04.2024
2	वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सब्सिडी समाधान – वास्तविक खपत विवरण – घरेलू उपभोक्ता, सामान्य और एसएफएस श्रेणी के अधीन कृषि उपभोक्ता, झोपड़ी उपभोक्ता, सार्वजनिक पूजा के वास्तविक स्थल, पावरलूम, हथकरघा, कृषि श्रेणियों के लिए लिफ्ट सिंचाई सहकारी समितियाँ, एलटी व् बी पीक आवर शुल्क और नेटवर्क शुल्क में कमी।	24.06.2024
3	गैर-टैरिफ संबंधी विविध शुल्क	15.07.2024
4	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों का निर्धारण	15.07.2024
5	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एसएलडीसी शुल्कों का निर्धारण	15.07.2024
6	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वितरण हेतु शुल्क का निर्धारण	15.07.2024
7	तमिलनाडु सरकार द्वारा दिनांक 15-07-2024 के टैरिफ आदेश संख्या 6, 2024 के आधार पर 01-07-2024 से प्रभावी टैरिफ संशोधन के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी	12.08.2024
8	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टैट्रास्को के टू-अप का अनुमोदन	13.08.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
9	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैजको के टू-अप का अनुमोदन	14.08.2024
10	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एसएलडीसी के टू-अप का अनुमोदन	10.10.2024
11	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैट्रांस्को के टू-अप का अनुमोदन	10.10.2024
12	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एसएलडीसी के टू-अप का अनुमोदन	10.10.2024
13	वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ताओं द्वारा रखे गए अग्रिम चालू उपभोग शुल्क पर ब्याज	04.02.2025
14	एचटी और एलटी उपभोक्ताओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सुरक्षा जमा पर ब्याज	10.02.2025
15	तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम टैरिफ सब्सिडी।	26.03.2025

27. तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	ओ.पी.सं.8/2021 में आई.ए. संख्या 4/2023 डिस्कॉम को अनुसूचित विद्युत उत्पादन की मात्रा तक एसटीपीपी द्वारा वहन की गई कोयला लागत का भुगतान करने के लिए कुछ निर्देशों हेतु आदेश के पैराग्राफ 12 के भाग के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण की अपेक्षा।	01.04.2024
2	ओ.पी. संख्या 13/2023 सिंगारेनी थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2 ग600 मेगावाट से नैनी कोल ब्लॉक के संचालन की तिथि तक बिजली की खरीद के लिए लगाए गए बिजली मूल्य निर्धारण के संबंध में और बाद में अंतिम उपभोक्ताओं के हित में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) इनपुट मूल्य निर्धारण पद्धति अंगीकरण करने के संबंध में।	01.04.2024
3	ओ.पी. संख्या 16/2017 मौजूदा लाइसेंसधारी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए, उसे अपने क्षेत्र में आने वाली वितरण परिसंपत्तियों को सौंपने के निर्देश देने की मांग के संबंध में।	15.04.2024
4	ओपी सं.76 एवं 77/2015 एआरआर और टैरिफ प्रस्तावों के साथ क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस) के निर्धारण के संबंध में।	19.04.2024
5	ओ.पी. संख्या 04/2021 दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (जेचकब्स) के लिए निर्धारित टैरिफ को अधिकतम टैरिफ के रूप में अनुमोदित करते हुए, एक मान्य वितरण लाइसेंसधारी के रूप में अपने उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले टैरिफ के अनुमोदन हेतु।	15.04.2024
6	ओ.पी. संख्या 6/2023 और आई.ए. संख्या 1/2023 लाइन और बे रखरखाव शुल्क लगाने और परिणामी राहत पर सवाल	06.05.2024
7	ओ.पी. संख्या 12/2023 याचिकाकर्ता के 1.0 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा 01.10.2020 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए ग्रिड में डाली गई इकाइयों के दावे को मानित खरीद के रूप में स्वीकार करने और 2020-21 और 2021-22 के प्रासंगिक वर्षों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित औसत संयुक्त विद्युत क्रय लागत का भुगतान करने की मांग के संबंध में	06.05.2024
8	ओ.पी. संख्या 30/2023 आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में	27.05.2024
9	ओ.पी. संख्या 31/2023 आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में	27.05.2024
10	ओ.पी. संख्या 32/2023 आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में	27.05.2024
11	ओ.पी. संख्या 33/2023 आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में	27.05.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
12	ओ.पी. संख्या 34/2023 आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में	27.05.2024
13	ओ.पी. संख्या 16/2005मेंआई.ए. संख्या 9/2017, ओ.पी. संख्या 13/2006 में आई.ए. संख्या 10/2017 में, ओ.पी. संख्या 5/2007 में आई.ए. संख्या 11/2017, ओ.पी. संख्या 73/2012 में आई.ए. संख्या 12/2017, ओ.पी. संख्या 74/2012में आई.ए. 13/2017, ओ.पी. संख्या 75/2012में आई.ए. संख्या 14/2012,ओ.पी. संख्या 76/2017 में आई.ए. संख्या 15/2012 के ओ.पी. संख्या 77/2017 में आई.ए. संख्या 16/2017, ओ.पी. संख्या 13/2017 और ओ.पी. संख्या 14/2017 टीजीडिस्कॉम द्वारा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लिए लगाए जाने वाले क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज का नया निर्धारण	30.08.2024
14	ओ.पी. संख्या 11/2024 मौजूदा बायोमास, खोई और औद्योगिक अपशिष्ट-आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए परिवर्तनीय लागत का स्वतः निर्धारण	31.08.2024
15	ओ.पी. संख्या 22/2024 में आर.पी. संख्या 1/2024 नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीपीओ) के अनुपालन के संबंध में 2023 के ओ.पी. संख्या 22 में पारित दिनांक 27.03.2024 के आदेश की समीक्षा की मांग के संबंध में	25.09.2024
16	ओ.पी. संख्या 7/2024 और ओ.पी. संख्या 8/2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (एच2) के लिए खुली पहुंच (ओए) उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार (एएस) के निर्धारण हेतु	30.09.2024
17	ओ.पी.(एसआर) संख्या 50/2024 और आई.ए.(एसआर) संख्या 51, 52 और 70/2024 डुंडीगल में 14.2 मेगावाट अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) से उत्पन्न ऊर्जा की बिक्री के लिए परियोजना-विशिष्ट टैरिफ निर्धारण हेतु न्यायनिर्णयन की मांग के संबंध में	14.10.2024
18	ओ.पी. संख्या 23/2023 प्रतिवादियों को 19 वर्षों के लिए दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए) प्रदान करने के निर्देश देने की मांग	14.10.2024
19	ओ.पी. संख्या 24/2023 प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 31.03.2023 से दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए) प्रदान करने और ग्रिड में ऊर्जा इंजेक्शन का निपटान करने के निर्देश देने की मांग।	14.10.2024
20	ओ.पी. संख्या 27/2023 प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 31.03.2023 से दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए) प्रदान करने और 31.03.2023 से 14.06.2023 तक की अवधि के लिए ग्रिड में ऊर्जा इंजेक्शन और परिणामी राहत का निपटान करने के निर्देश देने की मांग।	14.10.2024
21	ओपी सं 2/2024 में आरपी सं. 3/2024 टीजीट्रांसको के पारेषण व्यवसाय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) के विषय में 2024 के परिचालन आदेश संख्या 2 के आदेश की समीक्षा की मांग।	18.10.2024
22	ओ.पी.सं.20/2024 और आई.ए.सं.19/2024 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई बिजली खरीद के संबंध में औसत संयुक्त बिजली खरीद लागत का निर्धारण, जिस पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विचार किया जाएगा।	19.10.2024
23	ओ.पी. संख्या 22/2024 आरटीएस-बी (62.5 मेगावाट) के लिए पीपीए की वैधता को 01-04-2024 से 03-06-2024 तक और कंटीपीएस-वी (500 मेगावाट) के लिए 01-04-2024 से 31-03-2029 तक बढ़ाने के लिए	22.10.2024
24	ओ.पी. संख्या 26/2020 टीजीएसपीडीसीएल को समय-समय पर संशोधित 2006 के विनियम संख्या 2 के प्रावधानों को लागू करने और दिन के समय के शुल्क न लगाने का निर्देश देने की मांग।	22.10.2024
25	ओ.पी. संख्या 3/2024 और आई.ए. संख्या 1/2024 प्रतिवादियों को विद्युत क्रय करार (पीपीए) और अन्य राहतों के अनुसार ऊर्जा की बिक्री पर ब्याज सहित बकाया बिलों का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग	26.10.2024
26	ओ.पी. संख्या 9/2024 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बाध्य संस्थाओं के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीपीओ) के अनुपालन का स्वतः निर्धारण	28.10.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
27	ओ.पी.सं.9 और 10/2019 में आई.ए.सं.5/2024 और 6/2024 31.03.2024 को नियंत्रण अवधि की समाप्ति पर व्हीलिंग शुल्क और वस्तुगत व्हीलिंग हानियों के आवेदन को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग	28.10.2024
28	ओ.पी.सं.80 और 81/2022 में आई.ए.सं.4/2024 और आई.ए.सं.7/2024 खुदरा आपूर्ति शुल्क (आरएसटी) और क्रॉस सब्सिडी अधिभार (सीएसएस) के आवेदन की अवधि बढ़ाने की मांग	28.10.2024
29	ओ.पी.सं.3/2019 में आई.ए.सं.8/2024 वित्तीय वर्ष 2019-24 की नियंत्रण अवधि के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ और हानियों के विस्तार के संबंध में जो 01.04.2024 से 31.03.2024 को समाप्त हो रहा है।	28.10.2024
30	ओ.पी.सं.2/2019 में आई.ए.सं. 9/2024 31.03.2024 को नियंत्रण अवधि की समाप्ति पर वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन हेतु एसएलडीसी शुल्क के निर्धारण के संबंध में	28.10.2024
31	ओ.पी.सं.6/2021 में आई.ए.सं.10/2024 31.03.2024 को नियंत्रण अवधि की समाप्ति पर वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत उत्पादन शुल्क निर्धारण के संबंध में	28.10.2024
32	ओ.पी.सं.79/2022 में आई.ए.सं.3/2024 डिस्कॉम को अनुसूचित विद्युत उत्पादन की मात्रा तक एसटीपीपी द्वारा वहन की गई कोयला लागत का भुगतान करने के लिए कुछ निर्देशों हेतु आदेश के पैराग्राफ 12 के भाग के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण की अपेक्षा।	28.10.2024
33	ओ.पी. संख्या 29/2023 31.03.2024 को विद्यमान आदेश की समाप्ति पर वर्ष 2024-25 के लिए थोक क्रय लागत और खुदरा टैरिफ जारी रखने के संबंध में	28.10.2024
34	आर.पी.(एसआर) संख्या 53/2024, ओ.पी. संख्या 4/2024 कोयला मूल्य, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, वार्षिक स्थिर शुल्क के संबंध में ओ.पी. संख्या 4/2024 के दिनांक 28.06.2024 के आदेश की समीक्षा की मांग	28.10.2024
35	ओ.पी. संख्या 20/2023 प्रतिवादियों को नियमित बिजली आपूर्ति बिलों के भुगतान में देरी के कारण अधिभार और ब्याज सहित बैकडाउन क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग	28.10.2024
36	ओ.पी. संख्या 36/2023 और आई.ए. संख्या 10 और 11/2023 व्हीलिंग शुल्क की वसूली और परिणामी राहत पर सवाल उठाते हुए दाखिल याचिका।	28.10.2024
37	ओ.पी. संख्या 35/2023 और आई.ए. संख्या 8 और 9/2023 ग्रिड सपोर्ट शुल्क की वसूली और परिणामी राहतों पर सवाल उठाते हुए। याचिकाकर्ता के कथन नीचे दिए गए हैं।	28.10.2024
38	ओ.पी. संख्या 25/2024 टीजीएसपीडीसीएल और मेसर्स डुंडीगल वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 14.02.2024 को हस्ताक्षरित मसौदा पीपीए का अनुमोदन	01.03.2025
39	ओ.पी. संख्या 24/2025 और आई.ए. संख्या 7/2025 24 मेगावाट की अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) आधारित विद्युत संयंत्र की इकाई-2 (चरण प्) से विद्युत क्रय हेतु विद्युत क्रय करार (पीपीए) के निष्पादन और/या अनुमोदन के संबंध में	12.03.2025

28. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	त्रिपुरा विद्युत विनियामकआयोग (सकल/नेट मीटरिंग के अधीन ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सिस्टम) विनियम, 2024	05.07.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवसाय के लिए एआरआर निर्धारण और त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अनुमोदन	14.08.2024

29. उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	16.12.2024
2	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण एवं पारेषण शुल्क हेतु एमवाईटी) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2025	08.01.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ का सही निर्धारण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) और दक्षिण अंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (डीवीवीएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और टैरिफ का अनुमोदन – (याचिका संख्या 2043/2023) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ (एमवीवीएनएल) – (याचिका संख्या 2042/2023) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पीवीवीएनएल) – (याचिका संख्या 2040/2023) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (पीयूवीवीएनएल) – (याचिका संख्या 2041/2023) कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड, कानपुर (केस्को) – (याचिका संख्या 2048/2023)	10.10.2024
2	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और टैरिफ, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एआरआर और राजस्व के टू-अप का अनुमोदन	10.10.2024

30. उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन स्टेशन से विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ और अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024	20.06.2024
2	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024	17.09.2024

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	नए एलटी कनेक्शन जारी करने में देरी के संबंध में देय जुर्माने का भुगतान न करने से संबंधित आयोग के आदेश दिनांक 06.07.2022 और 20.07.2022 के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने के लिए आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की गई। (स्वतः संज्ञान)	10.04.2024
2	सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वृद्धिशील बिजली खरीद लागत के विरुद्ध उपभोक्ताओं से वसूले गए ध्वापस किए गए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के अनुमोदन की मांग करने वाला आवेदन।	10.04.2024
3	निम्नलिखित परियोजनाओं पर निवेश हेतु अनुमोदन हेतु आवेदन: क) अकरी बरजुला, टिहरी (जी) में 2 ग5 एमवीए, 33/11 केवी सबस्टेशन का निर्माण और 33/11 केवी एस/एस न्यूलीसैण (कीर्तिनगर) से एसीएसआर डॉग कंडक्टर और एक्सएलपीई केबल पर इससे संबंधित 33 केवी लाइन के साथ-साथ 33/11 केवी एस/एस न्यूलीसैण में एक 33 केवी बे का निर्माण। ख) लोधीवाला, भगवानपुर (रुड़की) में 2 ग12.5 एमवीए, 33/11 केवी सबस्टेशन और इससे जुड़ी 33 केवी लाइन और 33/11 केवी एसधएस दादा जलालपुर लाइन पर छह 33 केवी 'बे' का निर्माण। 11 केवी ओ/जी फीडर। (याचिका सं. 06/2024)	18.04.2024
4	ईडीसी, रुड़की के अधीन 132 केवी चुड़ियाला सबस्टेशन से 33x11 केवी देवभूमि तक नई 33 केवी लाइन के निर्माण से संबंधित परियोजना पर निवेश के अनुमोदन हेतु आवेदन। (याचिका संख्या 18/2024)	30.04.2024
5	गैस भुगतान जारी करने हेतु संशोधित भुगतान शर्तों हेतु अनुपूरक पीपीए के विषय में स्वतः संज्ञान कार्यवाही।	03.05.2024
6	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ऊर्जा बैंकिंग करार के अधीन मेसर्स उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अग्रिम और वापसी ऊर्जा बैंकिंग के लिए आयोग की पूर्व स्वीकृति की मांग करने वाली याचिका।	13.05.2024
7	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स यूजेवीएन लिमिटेड के बीच धालीपुर एचईपी से डाकपत्थर बैराज के बीच यमुना पावर चैनल पर 2.5 मेगावाट कैनाल बैंक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए विद्युत क्रय करार के मसौदे पर आयोग की स्वीकृति की मांग करने वाला आवेदन।	16.05.2024
8	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स यूजेवीएन लिमिटेड के बीच ढकरानी एचईपी के पास यमुना पावर चैनल पर 9.5 मेगावाट कैनाल बैंक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए विद्युत क्रय करार के मसौदे पर आयोग की स्वीकृति की मांग करने वाला आवेदन।	
9	व्यासी पावर चैनल हाउस, डाकपत्थर में स्थित 1.5 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स यूजेवीएन लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय करार के प्रारूप पर आयोग के अनुमोदन के लिए आवेदन।	
10	धरासू पावर हाउस, चिन्वालीसौड़, जिला उत्तरकाशी में स्थित 4 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स यूजेवीएन लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय करार के प्रारूप पर आयोग के अनुमोदन के लिए आवेदन।	
11	भटवारी गांव, मनेरी, जिला उत्तरकाशी के पास स्थित 4 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स यूजेवीएन लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय करार के प्रारूप पर आयोग के अनुमोदन के लिए आवेदन।	
12	औंगी, मनेरी, जिला उत्तरकाशी के पास स्थित 7.75 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स यूजेवीएन लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय करार के प्रारूप पर आयोग के अनुमोदन के लिए आवेदन।	
13	वीरभद्र बैराज और चीला जलविद्युत परियोजना के पावर चैनल के पुनर्वास कार्यों पर पूंजी निवेश की पूर्व स्वीकृति हेतु याचिका। (याचिका संख्या 23x2024)	17.05.2024
14	दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए वृद्धिशील बिजली खरीद लागत के विरुद्ध उपभोक्ताओं से लिए गए ध्वापस किए गए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के अनुमोदन हेतु आवेदन।	30.05.2024
15	मेसर्स मेट्रो डेकोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड कटैया, काशीपुर जिला-उधमसिंह नगर के लिए 33 केवी बे से संबंधित यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियम, 2020 के विनियम 3.4.3 (11) का अनुपालन न करने के लिए आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की गई। (याचिका संख्या 22/2024)	21.06.2024
16	220 केवी सबस्टेशन, रामनगर, रुड़की में संबद्ध कार्यालय भवन और ट्रांजिट हॉस्टल के साथ एनएबीएल	26.06.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	मान्यता प्राप्त तेल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए निवेश अनुमोदन। और 132 केवी सबस्टेशन, काठगोदाम (हल्द्वानी) में ट्रांजिट हॉस्टल के साथ संबद्ध कार्यालयों, परियोजना प्रबंधन और निगरानी कार्यालय भवनों के साथ एनएबीएल मान्यता प्राप्त विशेष उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला (एसईटीएल) की स्थापना के लिए निवेश अनुमोदन।	
17	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को काशीपुर, उत्तराखंड में मेसर्स श्रवणथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 2 ग225 मेगावाट (450 मेगावाट आईएसओ) गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र के पहले चरण के लिए 214 मेगावाट (225 मेगावाट) आईएसओ से आपूर्ति की गई बिजली के लिए 'चालान के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे' से संबंधित मामले के समाधान के लिए याचिका। यह याचिका वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 की अवधि से संबंधित है।	12.07.2024
18	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86, उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के विनियम 45 और उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (एमवाईटी) विनियम 2021 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दाखिल की गई है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को काशीपुर स्थित 225 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र के 107 मेगावाट से आपूर्ति की गई विद्युत के लिए "बिलों के विलंबित भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति"।	30.07.2024
19	पीटीसीयूएल की पारेषण लाइनों के लिए आपातकालीन पुनर्स्थापन प्रणाली (ईआरएस) के 01 सेट की खरीद हेतु निवेश अनुमोदन।	14.08.2024
20	निम्नलिखित का निवेश अनुमोदन: क) 220/132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन बनबसा, टनकपुर का निर्माण। ख) प्रस्तावित 220 केवी सबस्टेशन बनबसा, टनकपुर में 220 केवी टनकपुर-सीबी गंज लाइन के एलआईएलओ का निर्माण। ग) 132 केवी एस/एस खटीमा-प से प्रस्तावित 220 केवी एस/एस बनबसा, टनकपुर तक 132 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण। घ) प्रस्तावित 220 केवी एसएस बनबसा, टनकपुर से प्रस्तावित 132 केवी एस/एस लोहाघाट तक 132 केवी डी/सी लाइन का निर्माण।	16.08.2024
21	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड द्वारा 28 मार्च, 2024 के आयोग के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टूटिंग अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित समग्र राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के विषय में संख्या 49/2023	21.08.2024
22	प्रस्तावित 220/132/33 केवी एसएस रायपुर (भगवानपुर), रुड़की के निर्माण के लिए निवेश अनुमोदन, साथ ही संबद्ध लाइनों का निर्माण (400 केवी सबस्टेशन, पुहाना (पीसीजीआईएल), रुड़की से प्रस्तावित 220/132/33 केवी एसएस रायपुर (भगवानपुर), रुड़की तक 220 केवी डीसी लाइन और प्रस्तावित 220/132/33 केवी एसएस रायपुर, भगवानपुर, रुड़की में 132 केवी भगवानपुर-एलएसएम लाइन की एलआईएलओ लाइन)।	02.09.2024
23	उत्तराखंड राज्य में 33/11 केवी सबस्टेशनों पर स्वचालित रिएक्टिव पावर सॉल्यूशन (कैपेसिटर बैंक) की स्थापना हेतु परियोजना पर निवेश हेतु अनुमोदन हेतु आवेदन। (याचिका संख्या 43/2024)	02.09.2024
24	मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वृद्धिशील बिजली खरीद लागत के विरुद्ध उपभोक्ताओं से लिए गए धापस किए गए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के अनुमोदन हेतु आवेदन।	10.09.2024
25	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स जेजीएन शुगर एंड बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच मसौदा विद्युत क्रय करार पर आयोग के अनुमोदन हेतु आवेदन।	19.09.2024
26	यूईआरसी (नए एलटी कनेक्शन जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2007 और यूईआरसी (नए एलटी कनेक्शन जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2013 और यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियम, 2020 के प्रावधानों को शिथिल ध्माफ या परिवर्तित करने के लिए समीक्षा याचिका, जिसके अधीन वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2018-19 और फरवरी-2020 तक और सितंबर-2021 से अप्रैल-2024 तक की अवधि के लिए नए एलटी सेवा कनेक्शन जारी करने में देरी के विषय में जुर्माना लगाया गया था। (विविध आवेदन संख्या 43/2024)	18.09.2024
27	220 केवी सबस्टेशन झाझरा के विस्तार हेतु निवेश स्वीकृति (220/132 केवी वोल्टेज स्तर पर 2ग160 एमवीए से 3 ग160 एमवीए टीएफ और 132/33 केवी वोल्टेज स्तर पर 2 ग80 एमवीए से 3 ग80	17.09.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	एमवीए)	
28	यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियम, 2020 (याचिका संख्या 07/2024) में कठिनाई/स्पष्टीकरण को दूर करने हेतु आवेदन	23.09.2024
29	खुली पहुंच उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्व से उत्पन्न यूपीसीएल की निश्चित लागत को पूरा करने के लिए यूईआरसी (इंट्रा-स्टेट खुली पहुंच के निबंधन और शर्त) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण।	30.09.2024
30	यूईआरसी (व्यवसाय संचालन विनियम), 2014 के विनियम 9, 20, 58, 59, 61 और 62 और यूईआरसी आपूर्ति संहिता विनियम 2020 के विनियम 3.6 और अध्याय-8 विनियम 1 से 3 के अधीन व्यक्तिगत कनेक्शनों को गलत तरीके से जारी करने के खिलाफ और विनियम 3.6 के उप-विनियम 6 के प्रावधान के दाखिले को स्पष्ट करने और डेवलपर को जारी किए गए थोक आपूर्ति कनेक्शनों से आपूर्ति लेने वाले उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत कनेक्शन जारी करने के संबंध में प्रावधानों को संशोधित या संशोधित करके कठिनाई को दूर करने के लिए याचिका दाखिल की गई। (याचिका संख्या 04/2024)	07.10.2024
31	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक अल्पकालिक विद्युत क्रय करारके अधीन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीसीपीएल) के बीच अल्पावधि विद्युत क्रय करार के प्रारूप पर आयोग के अनुमोदन हेतु आवेदन।	08.10.2024
32	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक अल्पकालिक विद्युत क्रय करार के अधीन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (टीपीटीसी लिमिटेड) के बीच अल्पावधि के लिए विद्युत क्रय करार के प्रारूप पर आयोग के अनुमोदन की मांग वाला आवेदन।	08.10.2024
33	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टू-अप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक स्थिर शुल्क पर यूईआरसी के दिनांक 28.03.2024 के टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग वाला आवेदन। (याचिकाकर्ता-यूजेवीएन लिमिटेड) (याचिका संख्या 39/2024)	10.10.2024
34	मेसर्स हिम ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के राजकीय लघु जल विद्युत संयंत्र के लिए लागू टैरिफ के अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा घटक के टैरिफ के विषय में स्वतः संज्ञान कार्यवाही। लिमिटेड	16.10.2024
35	सौर पीवी, सौर तापीय और ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप एवं लघु सौर पीवी संयंत्रों के लिए बेंचमार्क पूंजीगत लागत की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके पश्चात के लिए लागू रहेगी, जब तक कि आयोग द्वारा इसकी समीक्षा/संशोधन नहीं किया जाता।	19.11.2024
36	अपील संख्या 215/2016, अपील संख्या 283/2016 और अपील संख्या 139/2018 पर माननीय एपीटीईएल का दिनांक 19.07.2024 का निर्णय, 'एमबी-ए परियोजना के लिए अतिरिक्त आईडीसी के 50 प्रतिशत और पूंजीगत लागत के मूल्य परिवर्तन घटक के 50 प्रतिशत से इनकार' के संबंध में। ख्याचिका संख्या 59/2024 (स्वतः संज्ञान),	20.11.2024
37	आयोग के प्रासंगिक नियमों और दिशानिर्देशों के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 86 के अधीन इचारी बांध के नागरिक ढांचे के पुनर्वास कार्य पर पूंजी निवेश के अनुमोदन की मांग करने वाली याचिका। (याचिका संख्या 17/2024)	21.11.2024
38	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ऊर्जा बैंकिंग करार के अधीन मेसर्स हरियाणा पावर परचेज सेंटर को अग्रिम एवं वापसी ऊर्जा बैंकिंग हेतु आयोग की पूर्व स्वीकृति हेतु याचिका।	22.11.2024
39	जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वृद्धिशील बिजली खरीद लागत के विरुद्ध उपभोक्ताओं से लिए गए ध्वापस किए गए ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के अनुमोदन हेतु आवेदन।	09.12.2024
40	33 केवी की आपूर्ति वोल्टेज लाइन पर अतिरिक्त 2000 केवीए भार (कुल अनुबंधित भार 12000 केवीए) जारी करने और इस प्रकार यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियम, 2020 के विनियम संख्या 2.1 (4) में छूट प्रदान करने हेतु याचिका। (याचिका संख्या 58/2024)	24.12.2024
41	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ऊर्जा बैंकिंग करार के अधीन मेसर्स उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अग्रिम एवं वापसी ऊर्जा बैंकिंग हेतु आयोग की स्वीकृति हेतु याचिका।	06.01.2025
42	"एक अतिरिक्त 132/33 केवी 40 एमवीए टीएफ की खरीद, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग तथा 220 केवी एसधएस वीरभद्र, ऋषिकेश में संबद्ध 132/33 केवी बे के निर्माण द्वारा 2 ग40 एमवीए (132/33 केवी) से 3 ग40 एमवीए (132/33 केवी) तक परिवर्तन क्षमता का विस्तार।"	22.01.2025
43	"टावर संख्या 47 और 50 के बीच भूमिगत केबलिंग कार्य सहित 132 केवी बिंदल-पुरकुल ट्रांसमिशन	24.01.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	लाइन के निर्माण" की संशोधित डीपीआर का निवेश अनुमोदन।	
44	132/33 केवी वोल्टेज स्तर पर 100 एमवीए (2 ग40 एमवीए, 1 ग20 एमवीए) से 120 एमवीए (3 ग40 एमवीए) ट्रांसफार्मर तक 132 केवी एस/एस पुरकुल, देहरादून के विस्तार की डीपीआर के लिए निवेश अनुमोदन।	10.02.2025
45	सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वृद्धिशील बिजली खरीद लागत के विरुद्ध उपभोक्ताओं से लिए गए धापास किए गए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के अनुमोदन की मांग करने वाला आवेदन।	11.03.2025
46	यूईआरसी (अंतर-राज्यीय खुली पहुंच के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार के निर्धारण के संबंध में यूईआरसी आदेश दिनांक 30.09.2024 की समीक्षा, जो 01.10.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए खुली पहुंच उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्व से उत्पन्न यूपीसीएल की निश्चित लागत को पूरा करने से संबंधित है।	11.03.2025
47	220/33 केवी सबस्टेशन जाफरपुर और 220/132/33 केवी सबस्टेशन कमालुआगांजा में सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम (एसएस) की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु निवेश स्वीकृति।	24.03.2025
48	अल्मोड़ा के ओएंडएम डिवीजन के अधीन 132 केवी सबस्टेशन रानीखेत में पुराने 132/33 केवी 20 एमवीए ट्रांसफार्मर को नए 132/33 केवी 20 एमवीए ट्रांसफार्मर से बदलने हेतु निवेश स्वीकृति।	27.03.2025
49	उत्तराखंड राज्य में विभिन्न डेवलपर्स द्वारा विकसित किए जाने वाले सौर पीवी संयंत्रों की निर्धारित कमीशनिंग तिथि में समय विस्तार के विषय में स्वतः संज्ञान कार्यवाही। उत्तराखंड की सौर ऊर्जा नीति, 2013 की टाइप-८ परियोजनाओं के अधीन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया।	27.03.2025
50	रुद्रप्रयाग जिले में श्री केदारनाथ धाम में 33/11 केवी सबस्टेशन के निर्माण के संबंध में निवेश हेतु अनुमोदन हेतु आवेदन। (याचिका संख्या 33/2025)	24.03.2025

31.पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण विनियम

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क) (संशोधन) विनियम, 2025	06.01.2025

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
1	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति हेतु डीवीसी टैरिफ आदेश (मामला डीवीसीटीपी-104/22-23)	31.03.2025
2	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश (मामला एपीएनआरएलटीपी-108/24-25)	31.03.2025
3	सीईएससी लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए टैरिफ आदेश (मामला सीईएससी लिमिटेडटीपी-102/22-23)	25.03.2025
4	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (मामला डब्ल्यूबीएसईडीसीएलटीपी-98/22-23)	20.03.2025
5	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल आठवीं नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) के लिए टैरिफ आदेश (मामला डब्ल्यूबीएसईडीसीएलटीपी-99/22-23)	15.03.2025
6	हिरणमय एनर्जी लिमिटेड, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (मामला एचएमईएलटीपी-107/23-24)	13.03.2025
7	डब्ल्यूबीपीडीटीसीएल, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (मामला डब्ल्यूबीपीडीटीसीएलटीपी -103/22-23)	12.03.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
8	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, वित्तीय वर्ष 2025-26 (आठवीं नियंत्रण अवधि) के लिए टैरिफ आदेश (मामला डीपीएलटीपी-106/22-23)	05.03.2025
9	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (मामला एचईएलटीपी-101/22-23)	05.03.2025
10	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश (मामला आईपीसीएलटीपी-105/22-23)	21.01.2025
11	ब्लैक लिमिटेड, टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए (मामला सीईएससी लिमिटेडटीपी-102/22-23)	03.09.2024
12	वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश (टीपी-104/22-23) की डीवीसी समीक्षा (मामला डीवीसीटीपी(आर)-51/24-25)	02.07.2024
13	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड टैरिफ आदेश (मामला एपीएनआरएलटीपी-100/22-23)	06.06.2024
14	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति (पश्चिम बंगाल) हेतु डीवीसी एपीआर आदेश (मामला डीवीसीएपीआर-125/24&25)	31.03.2025
15	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति (पश्चिम बंगाल) हेतु डीवीसी एपीआर आदेश (मामला डीवीसीएपीआर-123/24&25)	29.03.2025
16	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले एपीएनआरएलएफपीपीसीए-125/24-25 और एपीआर -127/24-25)	28.03.2025
17	डब्ल्यूबीपीडीसीएल, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले डब्ल्यूबीपीडीसीएलएपीआर -91/22 और एफपीपीसीए -97/19-20)	12.03.2025
18	डब्ल्यूबीएसडीसीएल, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले डब्ल्यूबीपीएसडीसीएलएफपीपीसीए -120/23-24 और एपीआर-117/23-24)	09.12.2024
19	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले एचईएलएफपीपीसीए-98/20-21 और एपीआर -100/22-23)	23.10.2024
20	सीईएससी लिमिटेड, एफपीपीसीए और एपीआर। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आदेश (मामले सीईएससी लिमिटेड एफपीपीसीए-99/20-21 और अप्रैल-83/20-21)	05.10.2024
21	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले आईपीसीएलएफपीपीसीए-112/22-23 और अप्रैल-103/22-23)	16.08.2024
22	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफसीए और एपीआर आदेश (मामले डीपीएलएपीआर-92/21-22 और एफपीपीसीए-10आई/21-22)	16.07.2024
23	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफसीए और एपीआर आदेश (भाग-प्) (मामले डीपीएलएफपीपीसीए-101(ए)/21-22 (भाग-II) और अप्रैल-86/21-22 (भाग-II))	16.07.2024
24	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफपीए और एपीआर आदेश 2018-19 (भाग-I) (मामले डीपीएलएफपीपीसीए-101 (क)/21-22 (भाग-प्) और एपीआर -86/21-22 (भाग-I))	02.06.2024
25	सीईएससी लिमिटेड: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश की समीक्षा (मामला सीईएससीलिमिटेड:एपीआर(आर)-26/23-24)	02.06.2024
26	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले आईपीसीएलएफपीपीसीए-111/22-23 और एपीआर-102/22-23)	02.06.2024
27	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले एचईएलएफपीपीसीए-96/19-20 और एपीआर-99/22-23)	19.06.2024
28	आईपीसीएल वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एपीआर आदेश (एपीआर-41/13-14) की समीक्षा (मामला आईपीसीएलएपीआर(आर)- 9/19-20)	16.06.2024
29	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर आदेश (मामले एचईएलएफपीपीसीए- 94/18-19 और एपीआर-97/21-22)	16.05.2024
30	राज्य स्तरीय विचलन निपटान तंत्र के लेखांकन पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही (मामला एसएम-39/24-25)	10.09.2024
31	उपभोक्ता सेवाओं के लिए समय-सीमा के संरेखण पर स्वतः संज्ञान आदेश (मामला एसएम-38/24-25)	21.08.2024
32	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड (एचईएल) के लिए एपीआर और एफपीपीसीए आदेशों (2017-18 से 2019-20)	25.03.2025

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
	से वसूली योग्य/वापसी योग्य राशियों का समायोजन।	
33	आरटीएसएस से 16 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के बीच पीपीए का अनुमोदन।	12.03.2025
34	यूनिट 7 और 8 के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम की स्थापना के संबंध में दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (डीपीएल) का अनुमोदन।	05.03.2025
35	8वीं नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 24- वित्तीय वर्ष 26) के लिए डल्लू आदेश में अनुमोदित ऊर्जा शुल्क दर (ईसीआर) पर हिरण्मय एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के संबंध में	05.03.2025
36	प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए एचआरपी ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड और सीईएससी लिमिटेड के बीच पीपीए का अनुमोदन।	03.03.2025
37	फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड (पीसीबीएल) द्वारा खुली पट्टा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका।	28.02.2025
38	नई पारेषण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पूंजीगत व्यय (लगभग 16319 लाख रुपये) का अनुमोदन।	06.01.2025
39	पश्चिम बंगाल में एक नए 2x800 मेगावाट संयंत्र से 1600 मेगावाट दीर्घकालिक बिजली की खरीद के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा किए गए अनुमोदन के संबंध में	06.01.2025
40	प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 200 मेगावाट तक आरटीसी ताप विद्युत (मध्यम अवधि) की खरीद के लिए दिशानिर्देशों से विचलन के लिए सीईएससी लिमिटेड द्वारा किए गए अनुमोदन के संबंध में	12.01.2024
41	कल्याणेश्वरी और आसपास के क्षेत्रों में 220/132/33/11/0.4 केवी अवसंरचना विकास के लिए आईपीसीएल द्वारा 'सैद्धांतिक मंजूरी' की मांग	09.12.2024
42	1600 मेगावाट दीर्घकालिक बिजली (ओए-506/24-25 के समान) की खरीद के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा किए गए अनुमोदन के संबंध में	26.11.2024
43	खुली पट्टा विनियम, 2022 के अधीन कैप्टिव प्लांटों से व्हीलड बिजली के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा व्हीलिंग शुल्क लगाने के संबंध में डालमिया सीमेंट द्वारा याचिका।	25.11.2024
44	टैरिफ (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट संचालन एवं रखरखाव मानदंडों के संबंध में डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा समीक्षा की मांग के संबंध में	21.11.2024
45	दालिपाली एस आई पीएस बिजली के लिए एनटीपीसी लिमिटेड और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के बीच पीपीए के लिए पूरक करार (दिनांक 28.03.2024) का अनुमोदन।	21.11.2024
46	वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गंगारामचक और गंगारामचक-भदुलिया कोयला खदानों से आपूर्ति किए गए कोयले के इनपुट मूल्य के लिए डब्ल्यूबीपीडीसीएल द्वारा अनुमोदन मांगा गया।	19.11.2024
47	बडगेबडगे जनरेटिंग स्टेशन यूनिट 3 में नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रण अनुपालन हेतु पूंजीगत व्यय के लिए सीईएससी लिमिटेड द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन मांगा गया।	11.11.2024
48	मामला संख्या बी-117/1 में आयोग के दिनांक 14.03.2024 के आदेश की हल्दिया एनर्जी लिमिटेड द्वारा समीक्षा की मांग के संबंध में	06.11.2024
49	एससीईबीफोर्क में 2 मेगावाट सौर पीवी इकाई से बिजली की खरीद के लिए आईपीसीएल और डब्ल्यूबीजीईडीसीएल के बीच पूरक पीपीए का अनुमोदन (01.12.2019 से पूर्वव्यापी)।	22.10.2024
50	हल्दिया में 10 मेगावाट डब्ल्यूएचआरबी संयंत्र से बिजली की खरीद के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल और पेट्रो कार्बन एंड केमिकल लिमिटेड (पीसीसीएल) के बीच पीपीए का अनुमोदन के संबंध में	22.10.2024
51	टैरिफ विनियमों के अनुसार कोयला नमूनाकरण हेतु तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों की नियुक्ति हेतु डब्ल्यूबीपीडीसीएल द्वारा समय विस्तार का अनुरोध।	01.10.2024
52	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए एपीआर और एफसी ए आदेशों से वसूली योग्य/वापसी योग्य राशियों का समायोजन।	01.10.2024
53	1600 मेगावाट दीर्घकालिक विद्युत (ओए-503/24-25, ओए-506/24&25 के समान) की खरीद हेतु मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन हेतु डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा अनुमोदन का अनुरोध।	19.09.2024
54	डीपीएल स्थल पर एक नए संयंत्र से 660 मेगावाट दीर्घकालिक विद्युत की खरीद हेतु मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन हेतु डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा अनुमोदन का अनुरोध।	19.09.2024

क्र.सं.	आदेश	जारी करने/निपटान की तारीख
55	मेसर्स बीएसके एगो फार्म बनाम डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा प्रस्तुत आवेदन से संबंधित मामला।	04.09.2024
56	सीईएससी लिमिटेड द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक के बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से करने की अनुमति देने के संबंध में आवेदन।	03.09.2024
57	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड द्वारा मामला संख्या ग्व-बी-एल 17/1 में आयोग के दिनांक 03.10.2023 के आदेश की समीक्षा की माँग।	03.09.2024
58	बंगाल एनर्जी लिमिटेड (बीईएल) और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के बीच पीपीए के चौथे अनुपूरक करारका अनुमोदन (पीपीए को 16.03.2025 तक बढ़ाना)।	30.08.2024
59	डब्ल्यूबीएसईडीसीएलद्वारा अतिरिक्त अधिभार (वित्तीय वर्ष 24-वित्तीय वर्ष 25 टैरिफ) की गणना के लिए 'भाग शुल्क के माध्यम से वसूल की गई लागत' पैरामीटर के मूल्य के लिए अनुमोदन की माँग।	21.08.2024
60	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पवन-सौर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पारेषण शुल्क हेतु विनियम 18.2.1(एच) की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 23.03.2023 के आदेश की समीक्षा की माँग।	21.08.2024
61	नई पारेषण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत व्यय (लगभग 34290 लाख रुपये) वहन करने हेतु डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा अनुमोदन की माँग।	16.08.2024
62	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा आयोग के दिनांक 06.12.2022 और 10.03.2023 के आदेशों की समीक्षा की माँग।	16.07.2024
63	डब्ल्यूबीपीडीसीएल द्वारा सागरदिघी ताप विद्युत परियोजना में इकाई 1 और 2 (300 मेगावाट) तथा इकाई 3 और 4 (500 मेगावाट) के लिए एफजीडी प्रणाली की स्थापना हेतु निवेश हेतु अनुमोदन की माँग की गई।	05.07.2024
64	सीईएससी लिमिटेड द्वारा एनवीवीएनएल (व्यापारी) के माध्यम से 150 मेगावाट आरटीसी जलविद्युत की खरीद हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन की माँग।	02.07.2024
65	आईपीसीएल द्वारा दिशेशगढ़ में 1ग12 मेगावाट उत्पादन इकाई के पूंजीगत व्यय और परिचालन मानदंडों में संशोधन हेतु अनुमोदन की माँग।	19.06.2024
66	आरईसी आवेदन को सुगम बनाने के लिए आरपीओ से परे अतिरिक्त आरई विद्युत क्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आईपीसीएल द्वारा आवेदन।	19.06.2024
67	पूर्ववर्ती डीपीएल के अनबंडलिंग के अनुसरण में निर्देशों के संबंध में फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल/डब्ल्यूबीएसईटीसीएल के बीच विवादों का निर्णय।	12.06.2024
68	150 मेगावाट पवन-सौर हाइब्रिड आरई के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क माफ करने के लिए सीईएससी लिमिटेड द्वारा आवेदन।	28.05.2024
69	100 मेगावाट पवन-सौर हाइब्रिड आरई के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क माफ करने के लिए सीईएससी लिमिटेड द्वारा आवेदन।	28.05.2024
70	विलंबित भुगतान अधिभार में राहत प्रदान करके बकाया राशि (वित्तीय वर्ष 18-वित्तीय वर्ष 20) के लिए एकमुश्त निपटान योजना हेतु डीवीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध के संबंध में	28.05.2024
71	16.07.2021 के टैरिफ आदेश में दिए गए निर्देशों के संबंध में अंतरिम राहत की माँग करते हुए डीपीएल द्वारा याचिका।	22.05.2024
72	प्रतिस्पर्धी बोली (एफओओ आधार) के माध्यम से 200 मेगावाट जलविद्युत की खरीद के लिए विचलन हेतु सीईएससी लिमिटेड द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध के संबंध में	16.05.2024
73	विभिन्न पारेषण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत व्यय (लगभग 25147 लाख रुपये) करने हेतु डब्ल्यूबीएसईटीसीएल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध के संबंध में	13.05.2024
74	नई पारेषण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत व्यय (लगभग 76401 लाख रुपये) करने हेतु डब्ल्यूबीएसईटीसीएल द्वारा अनुमोदन अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध के संबंध में	13.05.2024
75	सागरदिघी टीपीपी सौर संयंत्र (25 वर्ष) से निर्यात योग्य संपूर्ण सौर ऊर्जा की खरीद हेतु डब्ल्यूबीपीडीसीएल और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के बीच पीपीए का अनुमोदन।	04.04.2024

सीईआरसी द्वारा निर्धारित उत्पादन शुल्क

क. थर्मल और गैस पावर स्टेशनों का निश्चित प्रभार और ऊर्जा प्रभार

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता (मेगावाट)	मानक निश्चित शुल्क (रु./किलोवाट घंटा) 85 प्रतिशत एसजी	ईसीआर (रु.धकिलोवाट घंटा)	कुल शुल्क (रु.धकिलोवाट घंटा)
एनटीपीसी जनरेटिंग स्टेशन					
1	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV	500	0.05	0.55	0.60
2	गाडरवारा	1600	2.06	2.50	4.56
3	वैल्यू एसटीपीएस-1	840	1.05	2.29	3.34
4	कुडगी	2400	1.66	3.81	5.47
5	वेनम	1600	2.31	1.95	4.26
6	एनसीटीपीएस दादरी-1	840	1.03	3.69	4.73
7	सोलापुर	1320	2.05	4.09	6.14
8	तालचेर एसटीपीएस-I	1000	0.90	1.83	2.72
9	साइन-1	440	1.25	2.81	4.06
एनटीपीसी-जेवी स्टेशन					
10	एमयूएनपीएल, मेजा	1320	2.24	2.61	4.86
एनएलसी स्टेशन					
11	एनटीपीएल	1000	1.73	3.20	4.93
12	एनएनटीपीपी	1000	1.92	2.12	4.03
जीएमआर जनरेटिंग स्टेशन					
13	जीएमआर-कमलांगा एनर्जी लिमिटेड (केईएल)	262.5	6.44	1.91	8.35

ख. हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों का समग्र टैरिफ

क्र.सं.	बिजलीघर	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	इकाइयों की संख्या/क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक निश्चित शुल्क (लाख रुपये में)	वार्षिक डीई (एमयू)	टैरिफ (रु. धकिलोवाट घंटा)
एनएचपीसी						
1	पार्वती 3	520	(4 x 130)	45961.20	1963.29	2.34
एनटीपीसी						
2	कोलडाम	800	(4x200)	117106.35	3054.79	3.83

ग. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए स्तरीय सामान्य टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (रु.धकिलोवाट घंटा)
लघु जल विद्युत परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख (5 मेगावाट से कम)	6.42
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं	5.82

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (रु.धकिलोवाट घंटा)
लद्दाख (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	
ओडिशा (5 मेगावाट से कम)	4.92
ओडिशा (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.84
पंजाब (5 मेगावाट से कम)	5.53
पंजाब (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.44
अन्य राज्य (5 मेगावाट से कम)	7.38
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	7.26

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं ख्वावल के भूसे और जूलिफलोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना के अलावा, जल-शीतित कंडेन्सर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.22	6.00	9.21	0.14	9.07
हरियाणा	3.28	6.83	10.10	0.14	9.96
महाराष्ट्र	3.29	6.98	10.27	0.14	10.13
पंजाब	3.30	7.14	10.44	0.14	10.30
राजस्थान	3.21	5.96	9.17	0.14	9.03
तमिलनाडु	3.21	5.90	9.11	0.14	8.97
तेलंगाना	3.22	6.00	9.21	0.14	9.07
उत्तर प्रदेश	3.22	6.10	9.33	0.14	9.19
अन्य	3.25	6.41	9.66	0.14	9.52

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं (चावल के भूसे और जूलिफलोरा वृक्षारोपण के अलावा) आधारित परियोजना, एयर कूल्ड कंडेन्सर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.39	6.13	9.52	0.15	9.37
हरियाणा	3.45	6.98	10.43	0.15	10.28
महाराष्ट्र	3.46	7.14	10.60	0.15	10.45
पंजाब	3.48	7.30	10.78	0.15	10.62
राजस्थान	3.39	6.09	9.48	0.15	9.33
तमिलनाडु	3.38	6.03	9.42	0.15	9.26
तेलंगाना	3.39	6.13	9.52	0.15	9.37
उत्तर प्रदेश	3.40	6.24	9.64	0.15	9.48

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024–25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
अन्य	3.42	6.56	9.98	0.15	9.83

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024–25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं खावल के भूसे और जूलिफलोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, जल-शीतित कंडेन्सर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.34	6.00	9.34	0.15	9.18
हरियाणा	3.40	6.83	10.23	0.15	10.08
महाराष्ट्र	3.41	6.98	10.39	0.15	10.24
पंजाब	3.43	7.14	10.56	0.15	10.41
राजस्थान	3.34	5.96	9.30	0.15	9.14
तमिलनाडु	3.33	5.90	9.23	0.15	9.08
तेलंगाना	3.34	6.00	9.34	0.15	9.18
उत्तर प्रदेश	3.35	6.10	9.45	0.15	9.30
अन्य	3.37	6.41	9.78	0.15	9.63

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024–25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं खावल के भूसे और जूलिफलोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, एयर कूल्ड कंडेन्सर और ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.52	6.13	9.65	0.17	9.48
हरियाणा	3.58	6.98	10.56	0.17	10.39
महाराष्ट्र	3.59	7.14	10.73	0.17	10.56
पंजाब	3.60	7.30	10.91	0.17	10.74
राजस्थान	3.51	6.09	9.61	0.17	9.44
तमिलनाडु	3.51	6.03	9.54	0.17	9.38
तेलंगाना	3.52	6.13	9.65	0.17	9.48
उत्तर प्रदेश	3.53	6.24	9.77	0.17	9.60
अन्य	3.55	6.56	10.11	0.17	9.94

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं ख्वावल के भूसे और जूलिफलोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना के अलावा, जल-शीतित कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.21	5.89	9.10	0.14	8.96
हरियाणा	3.27	6.70	9.97	0.14	9.83
महाराष्ट्र	3.28	6.86	10.14	0.14	10.00
पंजाब	3.29	7.01	10.30	0.14	10.16
राजस्थान	3.21	5.85	9.06	0.14	8.92
तमिलनाडु	3.20	5.79	8.99	0.14	8.85
तेलंगाना	3.21	5.89	9.10	0.14	8.96
उत्तर प्रदेश	3.22	5.99	9.21	0.14	9.07
अन्य	3.24	6.30	9.54	0.14	9.40

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं ख्वावल के भूसे और जूलिफलोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना के अलावा, एयर कूल्ड कंडेंसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.38	6.02	9.40	0.15	9.25
हरियाणा	3.44	6.86	10.30	0.15	10.15
महाराष्ट्र	3.46	7.01	10.47	0.15	10.31
पंजाब	3.47	7.17	10.64	0.15	10.48
राजस्थान	3.38	5.98	9.36	0.15	9.21
तमिलनाडु	3.37	5.92	9.30	0.15	9.15
तेलंगाना	3.38	6.02	9.40	0.15	9.25
उत्तर प्रदेश	3.39	6.13	9.52	0.15	9.37
अन्य	3.41	6.44	9.85	0.15	9.70

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)	(₹./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं ख्वावल के भूसे और जूलिफलोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, जल-शीतित कंडेनसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.33	5.89	9.22	0.15	9.07

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
हरियाणा	3.39	6.70	10.10	0.15	9.94
महाराष्ट्र	3.40	6.86	10.26	0.15	10.11
पंजाब	3.42	7.01	10.43	0.15	10.28
राजस्थान	3.33	5.85	9.18	0.15	9.03
तमिलनाडु	3.33	5.79	9.12	0.15	8.97
तेलंगाना	3.33	5.89	9.22	0.15	9.07
उत्तर प्रदेश	3.34	5.99	9.33	0.15	9.18
अन्य	3.36	6.30	9.66	0.15	9.51

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास विद्युत परियोजनाएं खावल के भूसे और जूलिफलोरा (वृक्षारोपण) आधारित परियोजना, एयर कूल्ड कंडेंसर और एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.51	6.02	9.53	0.17	9.37
हरियाणा	3.57	6.86	10.43	0.17	10.26
महाराष्ट्र	3.58	7.01	10.59	0.17	10.43
पंजाब	3.59	7.17	10.77	0.17	10.60
राजस्थान	3.51	5.98	9.49	0.17	9.33
तमिलनाडु	3.50	5.92	9.43	0.17	9.26
तेलंगाना	3.51	6.02	9.53	0.17	9.37
उत्तर प्रदेश	3.52	6.13	9.65	0.17	9.48
अन्य	3.54	6.44	9.98	0.17	9.82

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	3.68	3.93	7.61	0.21	7.40
हरियाणा	3.29	5.59	8.88	0.18	8.70
महाराष्ट्र	2.95	5.51	8.46	0.16	8.30
पंजाब	3.24	4.92	8.16	0.18	7.98
राजस्थान	2.85	4.24	7.09	0.16	6.93
तमिलनाडु	3.17	3.93	7.10	0.18	6.92
तेलंगाना	3.71	4.39	8.10	0.21	7.88

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
उत्तर प्रदेश	3.23	4.76	7.99	0.18	7.81

राज्य	स्तरीकृत निश्चित लागत	परिवर्तनीय लागत	लागू टैरिफ दरें (वित्तीय वर्ष 2024-25)	त्वरित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो)	निवल स्तरीय टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के समायोजन पर) (यदि लाभ उठाया गया हो)
	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)	(रु./किलोवाट घंटा)
बायोमास गैसीफायर पावर प्रोजेक्ट					
आंध्र प्रदेश	3.53	5.53	9.06	0.14	8.92
हरियाणा	3.58	6.30	9.88	0.14	9.74
महाराष्ट्र	3.59	6.44	10.03	0.14	9.90
पंजाब	3.61	6.59	10.19	0.14	10.05
राजस्थान	3.53	5.50	9.02	0.14	8.88
तमिलनाडु	3.52	5.44	8.96	0.14	8.82
तेलंगाना	3.53	5.53	9.06	0.14	8.92
उत्तर प्रदेश	3.53	5.63	9.16	0.14	9.02
अन्य	3.56	5.92	9.47	0.14	9.33
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	4.74	5.80	10.54	0.27	10.27
आरडीएफ प्रौद्योगिकी					
आरडीएफ	10.15		10.15	0.55	9.60

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ आदेश जारी करने की समय-सीमा

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2024-25 के लिए लागू टैरिफ आदेश			
			विनियम के अनुसार टैरिफ के अनुमोदन की तिथि	टैरिफ के अनुमोदन की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	टिप्पणी
1	आंध्र प्रदेश	एपीट्रांसको	31.03.2024	06.08.2024	01.04.2024 से 5 वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए एमवाईटी ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश
		एपीएसएलडीसी	31.03.2024	27.08.2024	01.04.2024 से 5 वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए एसएलडीसी शुल्क पर एमवाईटी आदेश
		एपीजेनको	31.03.2024	09.09.2024	01.04.2024 से 5 वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए एपी जेनको का एमवाईटी आदेश
		एपीएसपीडीसीएल एपीसीपीडीसीएल एपीईपीडीसीएल	31.03.2024	27.09.2024	01.04.2024 से 5 वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 की पाँचवीं नियंत्रण अवधि के लिए व्हीलिंग व्यवसाय के लिए एमवाईटी आदेश
		एपीएसपीडीसीएल एपीसीपीडीसीएल एपीईपीडीसीएल	31.03.2025	20.02.2025	01.04.2024 से 5 वर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क और क्रॉस सब्सिडी अधिभार पर आदेश जारी
2	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश	एमवाईटी विनियम 3.4 के अनुसार, टैरिफ आवेदन की स्वीकृति की तिथि से 120 दिनों की अवधि के भीतर और सुनवाई की कार्यवाही पर विचार करने के पश्चात	26 th 07 th 2024	01.07.2024 से प्रभावी और 31.03.2025 तक लागू रहेगा, जब तक कि इसमें संशोधन या संशोधन न किया जाए।	अधिक जानकारी के लिए एपीएसईआरसी की वेबसाइट ⁶ www.epesirsi.org पर चेक करें।
3	असम	एपीडीसीएल	31.03.2024	27.06.2024	31.03.2025	आम चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के कारण टैरिफ आदेशों में देरी हुई।
		एपीजीसीएल	31.03.2024	27.06.2024	31.03.2025	
		एईजीसीएल	31.03.2024	27.06.2024	31.03.2025	
		एसएलडीसी	31.03.2024	27.06.2024	31.03.2025	
4	बिहार	एनबीपीडीसीएल एसबीपीडीसीएल	लाइसेंसधारी को 15 नवंबर तक टैरिफ याचिका प्रस्तुत करनी होगी और आयोग एआरआर और टैरिफ के निर्धारण के लिए पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देगा।	01.03.2024	01.04.2024 to 31.03.2025	-
		एनबीपीडीसीएल एसबीपीडीसीएल		28.03.2025	01.04.2025 to 31.03.2026	
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)	31.03.2024	01.06.2024	01.06.2024	

		जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	31.03.2024	10.05.2024	01.05.2024	
		भिलाई स्टील प्लांट-टीईईडी	31.03.2024	24.06.2024	01.07.2024	
6	दिल्ली	टीपीडीडीएल	-	19.07.2024	-	-
		बीआरपीएल				
		बीवाईपीएल				
		एनडीएमसी				
		आईपीजीसीएल				
		पीपीसीएल				
7	गुजरात	डीजीवीसीएल	पूर्ण याचिका पंजीकृत होने की तिथि से एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर	01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	चुनाव आचार संहिता के कारण टैरिफ आदेश जारी करने में देरी
		एमजीवीसीएल		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		पीजीवीसीएल		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		यूजीवीसीएल		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		टीपीएल-अहमदाबाद		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		टीपीएल-सुरत		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		टीपीएल-दहेज		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		एमयूएल		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		एआईएल		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		गिफ्ट पीसीएल		01.06.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25	टैरिफ आदेश समय-सीमा के भीतर जारी किये जा रहे हैं।
		डीजीवीसीएल		31.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		पीजीवीसीएल		31.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		यूजीवीसीएल		31.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		टीपीएल-अहमदाबाद		29.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		टीपीएल-सुरत		29.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		टीपीएल-दाहेज		29.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		एमयूएल		29.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		एआईएल		23.04.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26	
		गिफ्ट पीसीएल		31.03.2025	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		डीपीटी		31.03.2025	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		जेआईएल		31.03.2025	वित्तीय वर्ष 2024-25	
8	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल	31.03.2024	05.03.2024	01.04.2024	-
		यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल	31.03.2025	28.03.2025	01.04.2025	समय सीमा के भीतर जारी किया गया
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल)	31.03.2025 (पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 120 दिनों के भीतर,)	28.03.2024	वित्तीय वर्ष 2025-26	-
10	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	31.03.2024	30.09.2024	01.10.2024	
		स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	31.03.2024	20.08.2024	01.09.2024	
		दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	31.03.2024	30.09.2024	01.10.2024	
		टाटा स्टील लिमिटेड	31.03.2024	26.06.2024	01.07.2024	
		टाटा स्टील लिमिटेड	31.03.2024	28.03.2025	01.04.2025	
		टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	31.03.2024	26.06.2024	01.07.2024	
		टाटा स्टील यूटिलिटीज	31.03.2024	28.03.2024	01.04.2024	

		एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड				
11	जेईआरसी (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)	अंडमान एवं निकोबार ईडीएएंडएन	30.04.2024	13.06.2024	16.06.2024	आम चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के कारण टैरिफ आदेशों में देरी हुई।
		चंडीगढ़-ईडब्ल्यूईडीसी	02.08.2024	25.07.2024	01.08.2024	आम चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के कारण टैरिफ आदेशों में देरी हुई।
		दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	19.04.2024	13.06.2024	16.06.2024	आम चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के कारण टैरिफ आदेशों में देरी हुई।
		बिजली विभाग, गोवा (ईडीजी)	16.04.2024	13.06.2024	16.06.2024	आम चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के कारण टैरिफ आदेशों में देरी हुई।
		पुडुचेरी-पीईडी	19.04.2024	12.06.2024	16.06.2024	
		लक्षद्वीप-एलईडी	19.04.2024	10.06.2024	16.06.2024	
12	जेईआरसी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख)	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेपीडीसीएल)	01.04.2024	24.03.2025	24.03.2025 से जब तक कि आयोग के आदेश द्वारा संशोधित या परिवर्तित न किया जाए या आगे न बढ़ाया जाए।	आदेश तब तक वैध है जब तक कि आयोग के आदेश द्वारा उसे संशोधित नहीं किया जाता या परिवर्तन न किया जाए या आगे न बढ़ाया जाए।
		कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (केपीडीसीएल)	01.04.2024	24.03.2025	24.03.2025 से जब तक कि आयोग के आदेश द्वारा संशोधित या परिवर्तित न किया जाए या आगे न बढ़ाया जाए।	आदेश तब तक वैध है जब तक कि आयोग के आदेश द्वारा उसे संशोधित नहीं किया जाता या परिवर्तन न किया जाए या आगे न बढ़ाया जाए।
		लद्दाख विद्युत वितरण विभाग (एलपीडीडी)	01.04.2024	27.06.2024	1.07.2025 से 31.03. 2025 तक	यह आदेश 31-03-2025 तक वैध है, जब तक कि आयोग के आदेश द्वारा इसमें संशोधन या परिवर्तन न किया जाए या आगे न बढ़ाया जाए।
13	कर्नाटक	केपीटीसीएल	डिस्कॉम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30.11. 2023 को अपना आवेदन भरने की तिथि से 120 दिनों के भीतर	27.02.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01.04.2024 से प्रभावी	
		बेसकॉम				
		मेसकॉम				
		सीईएससी				
		हेसकॉम				
		गेसकॉम				
		एचआरईसीएस				
		एमएसईजेड				
14	केरल	एईक्यूएस	01.04.2024	05.12.2024	05.12.2024 से 31.03. 2027 तक	राज्य में डिस्कॉम, केएसईबी लिमिटेड ने 10.02.2022 को आयोग के समक्ष नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के लिए टैरिफ याचिका दाखिल की है और आयोग ने 25.06.2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ
		केएसईबी लिमिटेड				

						अधिसूचित किया है, जिसे 31.10.2023 तक जारी रखा गया था। इसके अलावा, केएसईबी लिमिटेड ने 01.04.2023 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए टैरिफ संशोधन हेतु याचिका दाखिल की है। याचिका के आधार पर और उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, आयोग ने 31.10.2023 को 01.11.2023 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए टैरिफ आदेश जारी किया, जो 04.12.2024 तक जारी रहा। इसके पश्चात, केएसईबी लिमिटेड ने 02.08.2024 को केएसईबी लिमिटेड द्वारा 01.07.2023 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए शुल्क अनुसूची और नियम व शर्तों को संशोधित करने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। केएसईबी लिमिटेड के संशोधित प्रस्तावों और उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, आयोग ने 02.12.2024 को 05.12.2024 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए शुल्क आदेश जारी किया है।
15	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के पूर्व, पश्चिम और मध्य डिस्कॉम	31.03.2025	29.03.2025	वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी	--
16	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)	30.11.2022	31.03.2023	01.04.2024	
		बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट)		31.03.2023		
		अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (वितरण व्यवसाय) (ईएमएल-डी)		31.03.2023		
		टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण) (टीपीसी-डी)		06.03.2023		
		महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)	31.03.2025	28.03.2025	01.04.2025	पांच वर्षों के लिए प्रभावी (अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक)
		बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट)				
		अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (वितरण)				

		व्यवसाय) (ईएमएल-डी) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण) (टीपीसी-डी) एमआईटीएल बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र एमआईटीएल शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र मेसर्स एसईजेड बायो-टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – मंजरी एसईजेड (एसईजेड बायो-टेक मंजरी) मेसर्स एसईजेड बायो-टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – हडपसर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड बायो-टेक हडपसर) जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) ईओएन खराड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ईओएन विशेष आर्थिक क्षेत्र चरण प) ईओएन खराड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ईओएन विशेष आर्थिक क्षेत्र चरण प) ईएमएल सीपूज लिमिटेड (एसएल) महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड केआरसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाय चैन मैनेजमेंट लिमिटेड				
17	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	30.11.2023	14.06.2024	31.03.2025 तक	-
18	मेघालय	एमपीडीसीएल	टैरिफ आवेदन की स्वीकृति की तिथि से 120 दिनों	24.10.2024	01.04.2024	टैरिफ आदेश 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।

		एमपीडीसीएल	के भीतर	24.03.2025	01.04.2025	आदेश निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया।
19	मिजोरम	पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिजोरम सरकार	पूर्ण आवेदन के पंजीकरण की तिथि से 120 दिनों के भीतर तथा जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात	24.03.2025	01.04.2025	
20	नागालैंड	डीओपीएन	30.03.2024	13.03.2024	01.04.2024	खुदरा टैरिफ आदेश
		एनईसी प्राइवेट लिमिटेड	120 दिन	11.03.2025	11.03.2025	उत्पादन शुल्क आदेश
21	ओडिशा	टीपीसीओडीएल	फाइल करने की तिथि के 120 दिन बाद (अर्थात 31.03.2025 तक)	24.03.2025	2025-26	--
		टीपीएनओडीएल				
		टीपीडब्ल्यूओडीएल				
		टीपीएसओडीएल				
22	पंजाब	जाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	पीएसईआरसी टैरिफ विनियम 59 के अनुसार, एआरआर/टू अप की समयसीमा को दाखिल करने की स्वीकृति से 120 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है (याचिका 45260 को दाखिल की गई थी और 07.12.2023 को ग्रहण/स्वीकार की गई थी)	14.06.2024	16-06-2024 to 31.03.2025	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ आदेश में देरी हुई क्योंकि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा 19.04.2024 से 01.06.2024 तक आयोजित लोकसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी।
23	राजस्थान	सभी डिस्कॉम		26.07.2024	वित्तीय वर्ष 2024.25	
24	सिक्किम	बिजली विभाग, सिक्किम सरकार	याचिका के पंजीकरण की तिथि से 120 दिनों के भीतर	13.03.2024	01.04.2024	डिस्कॉम ने 30 नवंबर 2023 को याचिका दाखिल की और उसी दिन याचिका पंजीकृत कर ली गई। आयोग ने याचिका के पंजीकरण की तिथि से 120 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर टैरिफ का अनुमोदन दे दी है।
25	तमिलनाडु	टीएनपीडीसीएल	15.04.2024	15.04.2024	2024-25	अनंतिम सब्सिडी आदेश
		टीएनपीडीसीएल	24.06.2024	24.06.2024	2023-24	सभी चार तिमाहियों का सब्सिडी समाधान
		टीएनपीडीसीएल	15.07.2024	15.07.2024	2024-25	स्वतः संज्ञान टैरिफ आदेश
		टीएनपीडीसीएल	15.07.2024	15.07.2024	2024-25	एसएलडीसी शुल्क
		टीएनपीडीसीएल	15.07.2024	15.07.2024	2024-25	गैर-टैरिफ संबंधी विविध शुल्क
		टीएनपीडीसीएल	15.07.2024	15.07.2024	2024-25	अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क
		टीएनपीडीसीएल	12.08.2024	12.08.2024	01.07.2024	टैरिफ संशोधन के कारण अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी
		टीएनपीडीसीएल	13.08.2024	13.08.2024	2020-21	टैनट्रांसको के टू-अप का अनुमोदन
		टीएनपीडीसीएल	14.08.2024	14.08.2024	2022-23	टैंगेडको के टू-अप का अनुमोदन
		टीएनपीडीसीएल	10.10.2024	10.10.2024	2020-21	एसएलडीसी के टू-अप का अनुमोदन
		टीएनपीडीसीएल	04.02.2025	04.02.2025	2025-26	उपभोक्ताओं के पास अग्रिम चालू

		टीएनपीडीसीएल	10.02.2025	10.02.2025	2024-25	उपभोग शुल्क पर ब्याज
		टीएनपीडीसीएल	26.03.2025	26.03.2025	2025-26	सुरक्षा जमा पर ब्याज
		टीजीएसपीडीसीएल				अनंतिम सब्सिडी आदेश
26	तेलंगाना	टीजीएसपीडीसीएल	31.03.2024	28.10.2024	01.11.2024 to 31.03.2025	आयोग ने टैरिफ फाइलिंग में देरी के लिए टीजीडिस्कॉम पर जुर्माना लगाया है
		टीजीएनपीडीसीएल				
27	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल)	31.03.2024	14.07.2024	01.08.2024	यह विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि नियमों के अधीन निर्धारित याचिका शुल्क जमा न किए जाने के कारण इस आयोग द्वारा याचिका स्वीकार नहीं की गई।
28	उत्तर प्रदेश	एनपीसीएल	31.03.2024	10.10.2024	वित्तीय वर्ष 2024.25	-
		राज्य डिस्कॉम	31.03.2024	10.10.2024	वित्तीय वर्ष 2024.25	-
29	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28.03.2024	-	01.04.2024	आयोग ने टैरिफ आदेश पर 28.03.2024 को हस्ताक्षर किए, तथापि, आदर्श आचार संहिता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, राज्य में मतदान पूरा होने के पश्चात आदेश जारी करने के लिए, आदेश 26.04.2024 को जारी किया गया है।
		उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28.03.2025	11.04.2025	01.04.2025	चूंकि याचिका 08.01.2025 को स्वीकार की गई थी और आयोग ने 11.04.2025 को टैरिफ आदेश जारी किया था, इसलिए यह 120 दिनों की अवधि के भीतर है।
30	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	31.03.2024	06.03.2024	वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 - 31 मार्च, 2025)	8वीं बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 23-वित्तीय वर्ष 26) का हिस्सा। इस आदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ निर्धारित किए।
		कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय कॉर्पोरेशन (सीईएससी)	31.03.2024	03.09.2024	वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023- 31 मार्च, 2024) वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 - 31 मार्च, 2025)	8वीं बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 23-वित्तीय वर्ष 26) का हिस्सा। इस आदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए टैरिफ निर्धारित किए।
		दामोदर घाटी निगम (डीवीसी-पश्चिम बंगाल कमान क्षेत्र)	31.03.2024	13.03.2024	वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023- 31 मार्च, 2024) वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 - 31 मार्च, 2025)	8वीं बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 23-वित्तीय वर्ष 26) का हिस्सा। इस आदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए टैरिफ निर्धारित किए।
		इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल-आसनसोल)	31.03.2024	21.01.2025	वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023- 31 मार्च, 2024)	8वीं बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 23-वित्तीय वर्ष 26) का हिस्सा।

		क्षेत्र)			वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 - 31 मार्च, 2025) वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल, 2025- 31 मार्च, 2026)	इस आदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26के लिए टैरिफ निर्धारित किए।
--	--	----------	--	--	---	--

सीजीआरएफ और लोकपाल का कामकाज

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के संबंध में रिक्त पदों का सारांश

क्र.सं.	राज्य	सीजीआरएफ की रिक्तियों की स्थिति	लोकपाल की रिक्तियों की स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
2	अरुणाचल प्रदेश	कोई रिक्ति नहीं	रिक्त
3	असम	लागू नहीं	शून्य
4	बिहार	शून्य	शून्य
5	छत्तीसगढ़	एक रिक्ति	कोई रिक्ति नहीं
6	दिल्ली	एक रिक्ति	कोई रिक्ति नहीं
7	गुजरात	शून्य	शून्य
8	हरयाणा	शून्य	शून्य
9	हिमाचल प्रदेश	एक रिक्ति	कोई रिक्ति नहीं
10	झारखंड	चार रिक्तियां	कोई रिक्ति नहीं
11	जेईआरसी (गोवा और केंद्रशासित प्रदेश)	पाँच रिक्तियां	अनुमोदित नहीं
12	जेईआरसी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख)	दो रिक्तियां	कोई रिक्ति नहीं
13	कर्नाटक	शून्य	शून्य
14	केरल	दस रिक्तियां	शून्य
15	मध्य प्रदेश	दो रिक्तियां	कोई रिक्ति नहीं
16	महाराष्ट्र	बारह रिक्तियां	कोई रिक्ति नहीं
17	मणिपुर	कोई रिक्ति नहीं	शून्य
18	मेघालय	शून्य	शून्य
19	मिजोरम	शून्य	कोई रिक्ति नहीं
20	नगालैंड	शून्य	कोई रिक्ति नहीं
21	ओडिशा	पाँच रिक्तियां	शून्य
22	पंजाब	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं
23	राजस्थान	शून्य	शून्य
24	सिक्किम	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं
25	तमिलनाडु	चौदह रिक्तियां	शून्य
26	तेलंगाना	कोई रिक्ति नहीं	रिक्त
27	त्रिपुरा	कोई रिक्ति नहीं	एक रिक्ति (2015 से रिक्त)
28	उत्तर प्रदेश	सात रिक्तियां	कोई रिक्ति नहीं
29	उत्तराखंड	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं
30	पश्चिम बंगाल	कोई रिक्ति नहीं	कोई रिक्ति नहीं

टिप्पण- 29 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से सीजीआरएफ और लोकपाल संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है, जबकि 1 राज्य विद्युत विनियामक आयोग/राज्य विद्युत विनियामक आयोग से डेटा प्राप्त नहीं हुआ।

सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग/राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल	1	31	364	289	106	32	63
		एपीसीपीडीसीएल	1	17	406	412	11	9	137
		एपीईपीडीसीएल	1	128	705	692	141	-	110
		कुल	3	176	1475	1393	258	41	310
2	अरुणाचल प्रदेश	1. नहरियागुन सीजीआरएफ ए) एस.ई. (ई) अध्यक्ष बी) ई.ई. (पीएलजी) सदस्य ग) सहा. कानूनी मौसम विज्ञान एवं उपभोक्ता मामले, नाहरलागुन-सदस्य	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2. पासीघाट सीजीआरएफ क) एस.ई. (ई), पासीघाट, अध्यक्ष ख) ई.ई. (पीएलजी) पासीघाट, सदस्य ग) सहा. विधिक माप विज्ञान एवं उपभोक्ता मामले, पासीघाट-सदस्य							

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग/राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		1. 3. मियाओ सीजीआरएफ क) एस.ई. (ई) मियाओ, अध्यक्ष ख) ई.ई. (पीएलजी) मियाओ, सदस्य ग) सहा. लीगल मेट्रोलेजि एवं उपभोक्ता मामले, मियाओ सदस्य							
		2. दिरांग सीजीआरएफ क) एस.ई. (ई) दिरांग, अध्यक्ष ख) ई.ई. (पीएलजी) दिरांग, सदस्य ग) सहा. विधिक माप विज्ञान एवं उपभोक्ता मामले, दिरांग-सदस्य							
		3. 4. जीरो सीजीआरएफ क) एस.ई. (ई) जीरो, अध्यक्ष ख) ई.ई. (योजना) जीरो, सदस्य ग) सहायक विधिक मापविज्ञान एवं उपभोक्ता मामले, जीरो सदस्य							

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		4. 5. आलो सीजीआरएफ क) एस.ई. (ई), आलो, अध्यक्ष ख) ई.ई. (पीएलजी) आलो, सदस्य ग) सहा. लीगल मेट्रोर्लॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, आलो मेम्बे 5. तेजू सीजीआरएफ क) एस.ई. (ई), तेजू, अध्यक्ष ख) ई.ई. (पीएलजी) तेजू, सदस्य ग) सहायक, कानूनी माप विज्ञान और उपभोक्ता मामले, सदस्य 6. सुबू सीजीआरएफ क) एस.ई. (ई) सुबू, अध्यक्ष ख) ई.ई. सुबू, इलेक्ट्रिकल सर्कल सदस्य							
3	असम	राज्य स्तर	1	0	6	5	1	0	12
		जिला स्तर	28	2	43	26	23	16	17
		कुल	29	2	49	31	24	16	29
4	बिहार	पीईएसयू पश्चिम	6	118	111	13	22	115	6
		पीईएसयू पूर्वी	5	86	82	9	2	145	5
		पटना	31	75	61	45	5	37	31
		नालन्दा	13	166	170	9	1	124	13
		बेचनेवाला	13	105	104	14	1	110	13

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग/राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		गया	12	145	149	18	1	प्रतिदिन	12
		औरंगाबाद	8	76	58	26	17	48	8
		आरा	10	111	99	22	4	51	10
		सासाराम	137	9	128	110	18		137
		भागलपुर	24	309	303	30	1	53	24
		जमुई	20	92	91	21	0	65	20
		दरभंगा	12	131	141	2	0	66	12
		पूर्णिया	24	102	116	10	1	91	24
		मुजफ्फरपुर	17	409	382	44	0	87	17
		बेगूसराय	4	119	115	8	1	82	4
		मोतिहारी	8	173	156	17	0	112	8
		छपरा	11	150	155	6	1	99	11
		समस्तीपुर	0	62	48	0	0	150	0
		किशनगंज	7	30	22	15	0	71	7
		सहरसा	13	59	41	24	13	101	13
		कुल	375	2527	2532	443	88	1607	375
5	छत्तीसगढ़	रायपुर	5	1	61	57	5	0	81
		बिलासपुर		35	72	85	22	15	150
		जगदलपुर		1	11	11	1	0	11
		रायगढ़		-	-	-	-	-	-
		भिलाई		-	-	-	-	-	-
		कुल	5	37	144	153	28	15	242
6	दिल्ली	सीजीआरएफ- बीआरपीएल	1	7	180	160	27	1	46
		सीजीआरएफ- बीवाईपीएल	1	157	591	579	169	66	95
		सीजीआरएफ- टीपीडीडीएल	1	27	196	193	30	3	76

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग/राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		सीजीआरएफ- एनडीएमसी	1	2	19	17	4	3	47
		कुल	4	193	986	949	230	73	264
7	गुजरात	डीजीवीसीएल सूरत	1	4	56	55	5	0	24
		डीजीवीसीएल वलसाड	1	2	14	15	1	0	9
		एमजीवीसीएल वडोदरा	1	0	43	43	0	0	12
		एमजीवीसीएल गोधरा	1	2	32	32	2	0	11
		पीजीवीसीएल राजकोट	1	4	57	50	11	0	14
		पीजीवीसीएल भावनगर	1	12	138	129	21	8	40
		पीजीवीसीएल भुज	1	4	26	25	5	0	10
		पीजीवीसीएल फुनागढ़	1	11	54	53	12	9	15
		यूजीवीसीएल मेहसाणा	1	0	25	25	0	0	11
		यूजीवीसीएल अहमदाबाद	1	4	41	43	2	0	22
		टीपीएल-डी अहमदाबाद	4	2	23	24	1	0	54
		टीपीएल-डी सूरत	1	0	29	28	1	0	52
		टीपीएल-डी दाहेज	1	0	0	0	0	0	11
		कुल	16	45	538	522	61	17	285
8	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	2	41	317	310	48	16	136
		डीएचबीवीएनएल		21	218	198	41	0	118
		कुल	2	62	535	508	89	16	254
9	हिमाचल प्रदेश	सीजीआरएफ, एचपीएसईबीएल, कसुम्पटी, शिमला-09	1	5	41	39	7	0	26

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
10	झारखंड	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) रांची, मेदिनीनगर, हजारीबाग, चाईबासा, दुमका	5	रांची-3 मेदिनीनगर-2 दुमका-1 चाईबासा-16 हजारीबाग-22	रांची-5 मेदिनीनगर-1 दुमका-3 चाईबासा-4 हजारीबाग-14	रांची-4 मेदिनीनगर-4 दुमका-4 चाईबासा-11 हजारीबाग-30	रांची-4 मेदिनीनगर-3 दुमका-0 चाईबासा-9 हजारीबाग-6	रांची-3 मेदिनीनगर-3 दुमका-0 चाईबासा-0 हजारीबाग-3	रांची-23 मेदिनीनगर-73 दुमका-8 चाईबासा-30 हजारीबाग-8
		उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (टाटा स्टील लिमिटेड)	1	0	0	0	0	0	0
		उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड)	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	31
		उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	1	0	0	0	0	0	0
		उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, सीजीआरएफ (दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, मैथन)	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	जेईआरसी (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)	चंडीगढ़	1	3	37	35	5	Nil	35
		गोवा	1	5	50	49	6	Nil	19
		दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0	0	0	0	0	53
		पुडुचेरी	1	15	86	86	15	12	55
		अंडमान और निकोबार	1	12	64	72	4	0	72
		लक्षद्वीप	1	0	9	8	1	Nil	10
		कुल	6	35	246	250	31	12	244
12	जेईआरसी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख)	जेपीडीसीएल, जम्मू	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		केपीडीसीएल, श्रीनगर	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		एलपीडीडी, लेह	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग/राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
13	कर्नाटक	बेसकॉम	8	28	18	25	92	81	21
		मेस्कॉम	4	2	6	8	3	0	8
		हेस्कॉम	5	1	7	8	8	2	10
		गेस्कम	7	7	13	11	38	27	11
		सीईएससी	7	12	41	41	55	32	23
14	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, दक्षिणी क्षेत्र, कोट्टाराक्कारा	3	15	82	72	25	5	98
		केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, मध्य क्षेत्र, एर्नाकुलम		29	142	122	49	0	122
		केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र, कोझिकोड		15	132	141	6	1	170
		त्रिशूर निगम विद्युत विभाग, त्रिशूर (जम्ब)	1	1	8	9	0	0	18
		कानन देवन हिल्स प्लांटेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुन्नार	1	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
		टेक्नोपार्क, कजहाकुट्टम, तिरुवनंतपुरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सीएसईजेडए), कक्कानाड, कोच्चि	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		किनेस्को पावर यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (केपीयूपीएल), कक्कानाड, कोच्चि	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		रबर पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरपीआईएल), वलयनचिरंगारा, एर्नाकुलम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, विलिंग्डन द्वीप, कोच्चि	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		इन्फोपार्क, कक्कानाड, कोच्चि	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		स्मार्ट सिटी कोच्चि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, भ्रमापुरम पी.ओ., कोच्चि	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल		12	60	365	344	81	6	408	
15	मध्य प्रदेश	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच जबलपुर	3	38	208	193	53	33	57
		उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच भोपाल		5	25	09	21	21	11

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच इंदौर		50	162	198	14	1	90
16	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	11	542	1415	1098	434	245	1343
		एईएमएल-डी	1	6	11	7	9	0	46
		टीपीसी-डी	1	1	1	0	1	0	4
		बीईएसटी	1	0	268	3	3	0	21
		एमबीपीपीएल	1	0	0	0	0	0	0
		जीईपीएल	1	0	0	0	0	0	0
		एनयूपीपीएल	1	0	0	0	0	0	0
		केआरसी	1	0	0	0	0	0	0
		एलबीसीएमएल	1	0	0	0	0	0	0
		एमएडीसी	1	0	0	0	0	0	0
		ईओएन 1,2	2	0	0	0	0	0	0
		जेएनपीटी	1	0	0	0	0	0	0
17	मणिपुर	सीजीआरएफ	2	1	0	0	0	0	0
18	मेघालय	मीईसीएल, सीजीआरएफ	2	1	0	1	0	0	0
19	मिजोरम	मिजोरम विद्युत विनियामक आयोग	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20	नागालैंड	कोहिमा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	ओडिशा	भुवनेश्वर	1	13	257	243	27	1	78
		खोरदा	1	24	559	543	40	0	118
		कटक	1	8	298	280	26	0	65
		पारादीप	1	11	165	162	14	शून्य	44
		ढेंकनाल	1	16	538	533	21	3	154
		बुर्ला	1	33	775	770	38	0	179
		बोलंगीर	1	07	704	697	14	0	196
		राउरकेला	1	01	815	800	16	01	212

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		बारगढ़	1	14	134	136	12	0	167
		भवानीपटना	1	119	583	702	0	0	114
		बालासोर	1	67	352	292	127	0	123
		जाजपुर	1	3	117	113	7	0	37
		बारीपदा	1	21	208	207	22	0	75
		क्योंझर	1	7	171	163	15	0	52
		बेरहामपुर	1	97	552	605	44	0	220
		जयपोर	1	89	610	635	64	28	205
		भंजनगर	1	65	307	323	49	1	96
		रायगढ़	1	44	189	208	25	0	112
		कुल	18	639	7334	7412	561	34	2247
22	पंजाब	कॉर्पोरेट, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, लुधियाना	01	09	183	181	11	02	53
23	राजस्थान	कॉर्पोरेट स्तर – जयपुर, अजमेर, जोधपुर (कुल 3) आंचलिक स्तर– जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर (कुल 9)	12	12	208	188	32	12	51
24	सिक्किम	सर्कल स्तरीय सीजीआरएफ गंगटोक जिला, मुख्यालय-1 मुख्यालय-2, मुख्यालय-3, मुख्यालय-1, एलएलएचपी, पूर्व-1, पाकयोंग जिला, पूर्व-2, पाकयोंग, रोंगली, ग्यालशिग जिला, पश्चिम-1, सोरेंग जिला, पश्चिम-2, मंगन जिला, उत्तर-1, उत्तर-2, नामची जिला, दक्षिण-1, दक्षिण-2, रवांगला, टेमी	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		प्रभाग स्तर							
		गंगटोक जिला, (मुख्यालय-1), विकास, डीपीएच, गंगटोक, (मुख्यालय-2), जेएनआर, वीआईपी, (मुख्यालय-3), देवराली, (मुख्यालय-1), ताडोंग, सिचे, रांका, (एलएलएचपी), टी एंड डी 1, टी एंड डी-2, (पूर्व-1), खामडोंग, सिंगतम, पाकयोंग जिला, (पूर्व-2), रंगपो, पेंडम, (पाकयोंग), पाकयोंग-1, पाकयोंग-2, (रोंगली), रोंगली-रेनॉक, ग्यालशिंग जिला, (पश्चिम-1), डेंटम, ग्यालशिंग। ताशीदिंग, सोरेंग जिला, (पश्चिम-2), कलुक, सोरेंग, सोम्बारिया, बैगुनी, मंगन जिला, (उत्तर-1), फोडोंग, (उत्तर-2), मंगन, चुंगथांग, नामची जिला, (दक्षिण-1), मेल्ली, जोरेथांग, (दक्षिण-2), नामची, नामथांग, (रावंगला), रावंगला, यांगंग, टेमी	35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	तमिलनाडु	कुल	41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		तिरुनेवेली	1	36	463	423	76	0	10
		विल्लुपुरम	1	36	524	358	202	0	6
		चेंगलपेट	1	31	639	631	39	0	9
		चेन्नई (उत्तर)	1	22	335	310	47	1	5
		चेन्नई (पश्चिम)	1	13	647	626	34	0	12
		चेन्नई सेंट्रल	1	23	435	453	5	1	11
		चेन्नई/दक्षिण-८	1	6	95	88	13	0	11
		चेन्नई/दक्षिण-८	1	0	75	63	12	0	3
		कोयंबटूर (दक्षिण)	1	3	93	94	2	2	5
		कोयंबटूर/मेट्रो	1	5	127	128	4	0	11
		कोयंबटूर/उत्तर	1	0	61	61	0	0	4
		कुड्डालोर	1	12	164	145	31	0	8
		धर्मपुरी	1	8	90	93	5	0	9

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		डिंडीगुई	1	6	48	53	1	3	9
		नमक्कल	1	2	57	45	14	0	17
		इरोड	1	8	150	132	26	0	7
		गोबी	1	5	142	139	8	0	12
		कल्लाकुरिची	1	0	37	28	9	0	4
		कांचीपुरम	1	0	136	136	0	0	6
		कन्याकुमारी	1	13	150	163	0	0	4
		करूर	1	0	120	120	0	0	4
		कृष्णागिरी	1	0	7	7	0	0	2
		मदुरै	1	16	73	45	44	0	4
		मदुरै (मेट्रो)	1	13	80	87	6	0	3
		मेदुर	1	1	37	36	2	0	4
		नागपट्टिनम	1	2	53	51	4	3	4
		नीलगिरी	1	2	95	92	5	0	5
		पल्लादम	1	1	43	44	0	0	5
		पेरम्बलुर	1	2	26	28	0	0	4
		पुडुकोट्टई	1	2	137	128	11	0	4
		रामनाथपुरम	1	5	94	93	6	0	5
		सलेम	1	11	142	102	51	0	5
		शिवगंगा	1	0	3	3	0	0	3
		तंजावुर	1	0	117	94	23	0	5
		तब मै	1	16	117	98	35	0	4
		थिरुपाथुर	1	3	96	90	21	0	6
		थिरुवन्नमलाई	1	26	157	186	2	0	7
		थिरुवरुर	1	3	59	39	6	0	5

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		तिरुपुर	1	7	276	257	26	0	6
		त्रिची (मेट्रो)	1	19	94	107	6	0	9
		तूतीकोरिन	1	0	59	58	1	5	4
		उदुमलपेट	1	2	13	13	2	0	7
		वेल्लोर	1	4	163	133	34	0	4
		विरुदुनगर	1	5	172	161	16	1	8
		कुल	44	369	6701	6241	829	16	280
26	तेलंगाना	टीजीएसपीडीसीएल सीजीआरएफ 1 (ग्रामीण)	I	91	323	383	31	0	33
		टीजीएसपीडीसीएल, सीजीआरएफ 2 (ग्रेटर हैदराबाद)	II	19	235	212	42	9	50
		टीजीएनपीडीसीएल, सीजीआरएफ 1	I	128	421	447	102	68	72
		टीजीएनपीडीसीएल, सीजीआरएफ 1	II	206	564	674	96	49	89
27	त्रिपुरा	जीएम (तकनीकी) विद्युत भवन, अगरतला, सीजीआरएफ, टियर-3	34	0	25	20	5	0	0
28	उत्तर प्रदेश	कंपनी स्तर	6	7	41	36	12	9	168
		फोरम जोन स्तर	35	319	185	304	200	181	242
		फोरम सर्कल स्तर	71	176	463	121	518	488	159
		कुल	112	502	689	461	730	678	569
29	उत्तराखंड	सीजीआरएफ देहरादून	8	55	231	248	38	185	पूर्णकालिक
		सीजीआरएफ हरिद्वार		28	360	326	62	86	
		सीजीआरएफ श्रीनगर (गढ़वाल)		9	49	52	6	2	
		सीजीआरएफ उत्तरकाशी		68	360	362	66	36	
		सीजीआरएफ कर्णप्रयाग		28	96	106	18	58	
		सीजीआरएफ हलद्वानी		22	223	239	6	12	
		सीजीआरएफ रुद्रपुर (यूएस नगर)		36	331	317	50	15	
		सीजीआरएफ अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़		40	112	124	28	31	

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
		कुल	8	286	1762	1774	274	425	पूर्णकालिक
30	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	24	89	847	787	149	58	341
		सीईएससी	10	4	1651	1655	0	0	269
		डीवीसी	1	0	0	0	0	0	0
		आईपीसीएल	5	4	0	0	4	4	06
		कुल	40	97	2498	2442	153	62	616

टिप्पण- सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति की जानकारी 29 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों से प्राप्त हुई है, जबकि 1 राज्य विद्युत विनियामक आयोग/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग से डेटा प्राप्त नहीं हुआ।

लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	लोकपाल की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1	1	20	17	4	0	94
2	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	असम	1	5	6	8	3	2	44
4	बिहार	1	58	45	54	48	35	सभी कार्य दिवस
5	छत्तीसगढ़	1	12	41	39	14	6	224
6	दिल्ली	1	7	77	59	25	14	60
7	गुजरात	2	15	107	109	13	1	136
8	हरियाणा	1	6	42	34	14	9	142
9	हिमाचल प्रदेश	1	5	20	17	8	0	16
10	झारखंड	1	9	7	12	4	4	पहली तिमाही – 60 दूसरी तिमाही – 57 तीसरी तिमाही – 56 चौथी तिमाही – 51 कुल – 224
11	जेईआरसी (गोवा और केंद्रशासित प्रदेश)	1	1	25	25	1	1	61
12	जेईआरसी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख)	1	शून्य	12	10	2	2	सभी कार्य दिवस
13	कर्नाटक	1	43	37	26	54	47	475
14	केरल	1	14	105	100	19	0	109
15	मध्य प्रदेश	1	4	11	15	0	0	30
16	महाराष्ट्र	1	92	115	124	81	0	134
		1	38	84	79	43	0	83

क्र.सं.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग का नाम	लोकपाल की संख्या	मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत में बकाया शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान शिकायतों के निपटान की स्थिति	मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	2 महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतें	अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
17	मणिपुर	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	मेघालय	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20	नागालैंड	अभी नियुक्ति बाकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	ओडिशा	लोकपाल 1	94	130	113	111	87	256
		लोकपाल 2	05	61	56	10	03	254
22	पंजाब	1	1	26	24	3	शून्य	69
23	राजस्थान	1	4	68	55	17	0	पूर्णकालिक
24	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	तमिलनाडु	1	13	95	93	15	2 (90 दिनों की समय सीमा के भीतर)	88
26	तेलंगाना	-	1	54	52	3	0	115
27	त्रिपुरा	शून्य (वर्ष 2015 से रिक्त)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	उत्तर प्रदेश	1	118	24	134	8	4	81
29	उत्तराखंड	1	15	53	43	25	30	पूर्णकालिक
30	पश्चिम बंगाल	1	138	290	215	213	172	133

टिप्पण- लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति की जानकारी 29 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों से प्राप्त हुई है, जबकि 1 राज्य विद्युत विनियामक आयोग/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

अनुबंध V

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरपीओ अनुपालन की स्थिति

ईआरसी द्वारा प्रदान किया गया आरसीओ/आरसीओ डेटा											
क्र.सं.	विद्युत विनियामक आयोग	आरसीओ का लक्ष्य	आरसीओ के लक्ष्य के सापेक्ष नवीकरणीय ऊर्जा खपत @			क्षेत्रों के लिए एसईआरसी/जेईआरसी का लक्ष्य	क्षेत्रों के लिए एसईआरसी/जेईआरसी का लक्ष्य	ओए के लिए एसईआरसी/जेईआरसी का लक्ष्य	एसईआरसी/जेईआरसी के लक्ष्य के सापेक्ष नवीकरणीय ऊर्जा की खपत @		
			डिस्कॉम	क्षेत्रीय उपयोगकर्ता	ओए उपयोगकर्ता				डिस्कॉम	क्षेत्रीय उपयोगकर्ता	ओए उपयोगकर्ता
1	आंध्र प्रदेश	29.91%	25.90%	17.26%		20%	20%	20%	25.28%	13.35%	
2	अरुणाचल प्रदेश	29.91%	75.52%	लागू नहीं	लागू नहीं	29.91%	29.91%	29.91%	75.52%	लागू नहीं	लागू नहीं
3	असम	29.91%	34.59%	-	-	29.91%	4.42% ⁶	29.91%	34.59%	13.46%	619.93% [^]
4	बिहार	29.91%	-	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	20.30%	*	*
5	छत्तीसगढ़	29.91%	-	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	10.80%	29.91%	
6	दिल्ली	29.91%	31.15%	251.85% [#]		29.91%	29.91%	29.91%	32.20%	63.83%	
7	गुजरात	29.91%	-	-	-	20.70%	20.70%	20.70%	20.01%	30.35%	
8	हरियाणा	29.91%	-	-	-	29.91%	7.13%	29.91%	35.98%	29.46%	36.01%
9	हिमाचल प्रदेश	29.91%	-	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	74.65%	*	*
10	झारखंड	29.91%	44.11%	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	44.11%	-	-
11	जेईआरसी (गोवा और केंद्रशासित प्रदेश)	29.91%	52.10%	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	52.10%	-	-
12	जेईआरसी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख)	29.91%	-	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	30.40%	2.42%	
13	कर्नाटक	29.91%	38.96%	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	38.96%	-	-
14	केरल	29.91%	37.77%	48.11%		37.00%	37.00%	37.00%	37.77%	48.11%	
15	मध्य प्रदेश	29.91%	25.59%	18.56%	31.00%	29.91%	29.91%	29.91%	25.59%	18.56%	31.00%
16	महाराष्ट्र	29.91%	18.82%	41.49%		29.91%	29.91%	29.91%	18.82%	-	-
17	मणिपुर	29.91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मेघालय	29.91%	91.90%	1.26%		7.50%	7.50%	7.50%	91.90%	6.82%	

ईआरसी द्वारा प्रदान किया गया आरसीजे/आसीजे डेटा											
क्र.सं.	विद्युत विनिर्माणक आयोजन	आरसीजे का लक्ष्य	आरसीजे के लक्ष्य के सापेक्ष नवीकरणीय ऊर्जा खपत @			डिस्कॉम के लिए एआईआरसी/जेईआरसी का लक्ष्य	कैपिटल के लिए एआईआरसी/जेईआरसी का लक्ष्य	ओए के लिए एआईआरसी/जेईआरसी का लक्ष्य	एआईआरसी/जेईआरसी के लक्ष्य के सापेक्ष नवीकरणीय ऊर्जा की खपत@		
			डिस्कॉम	कैपिटल उपयोगकर्ता	ओए उपभोक्ता				डिस्कॉम	कैपिटल उपयोगकर्ता	ओए उपभोक्ता
19	मिजोरम	29.91%	43.92%	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	43.92%	-	-
20	नागालैंड	29.91%	-	-	-	29.91%	29.91%	29.91%	31.08%	-	-
21	ओडिशा	29.91%	27.72%	-	-	18.00%	12.87%		-	31.35%	
22	पंजाब	29.91%	-	-	-	30.00%	4.90%	30.00%	32.95%	84.83%	27.54%
23	राजस्थान	29.91%	21.03%	99.69%		29.91%	29.91%	29.91%	21.46%	99.69%	
24	सिक्किम	29.91%	47.88%	-	-	17.40%	17.40%	17.40%	16.08%	-	-
25	तमिलनाडु	29.91%	23.80%	86.59%		29.91%	29.91%	29.91%	23.07%	56.86%	
26	तेलंगाना	29.91%	20.27%	4.43%#	28.41%#	10.50%	10.50%	10.50%	18.43%	4.43%#	49.14%#
27	त्रिपुरा	29.91%	-	-	-	15.00%	15.00%	15.00%	1.87%	-	-
28	उत्तर प्रदेश	29.91%	-	-	-	15.00%	15.00%	15.00%	7.27%	7.29%	
29	उत्तराखंड	29.91%	59.58%	36.44%		29.91%	29.91%	29.91%	59.58%	6.80%	
30	पश्चिम बंगाल	29.91%	-	-	-	17.00%	17.00%	17.00%	5.06%	-	-

* अपूर्ण/आंशिक डेटा प्रस्तुत किया गया

- यह डेटा दर्शाता है जो संस्था के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

एनए से लागू नहीं अभिप्रेत है बूटिके मौजूदा उपभोक्ता नहीं है

@ राज्य के सभी डिस्कॉम/कैपिटल/ओए उपभोक्ताओं के लिए समेकित

ईआरसी द्वारा समीक्षाधीन डेटा

^ किसी एक उपभोक्ताओं में से द्वारा आईसी की थोक खरीद के कारण उच्च प्रतिशत

& कैपिटल उत्पादन स्टेशन के बालू होने के वर्ष के आधार पर गणना की गई है, दायित्व इकाई के लिए विभिन्न लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
उपरोक्त डेटा 24.10.2025 तक किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर तैयार किया गया है।



विनियामक फोरम (एफ ओ आर)

सचिवालय : सी/ओ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीई आर सी)

आठवीं मंजिल टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नई दिल्ली 110029.

टेलीफ़ोन : +91-11-26189709